हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

8 मार्च, 1978

खंड 1, अंक 8

अधिकृत विवरण'

विषय–सूची

बधवार, 8 मार्च, 1 978

पृष्ठ

सख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (8) 1

नियम 45 के 'अधीन सदन की मैज पुर रखे गए

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

(8) 28

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर (8)

39

ओला वृष्टि से हुए तबाही 5 पर मुख्य मन्त्री

का वक्तव्य – (8)

48

नियम समिति का प्रतिवेदन सदन की मेज पर

रखना (8)

49

वर्ष 1978– 79 के बजट पर सामान्य चर्चा

(पुनरारम्भ)

(8) 49

बहिर्गमन (8)

48

वर्ष 1978–79 के बजट पर सामान्य चर्चा

(पुनरारम्भ) (8)

78–84

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 8 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर– 1, चण्डीगढ में 9. 30 बजे हुई ।

अध्यक्ष (ब्रिगेडियर रण सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

T.A. Drawn by each Minister

***211. Shri Shamsher Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the amount of T.A. drawn by each of the Ministers together-with the details of expenses incurred by the Government on account of telephones, electricity, water, furnishings of residences separately from the month of June to December, 1977 ?

Finance Minister (Chaudhri Satbir Singh Malik) : A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House (Annexure 'A')

ANNEXURE'A'

Statement showing the expenditure incurred by the State Government during the period from June, 1977 to December, I 977 on account of T. A. Telephones, Electricity, Water and Furnishings of residences meant for the Ministers of Haryana State,

Sr. No.	Name of the Minister	T.A. Rs.	Telephone Charges Rs.	Electricity Charges Rs.	Water Charges Rs.	Furnishing of residence Rs.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Shri Devi Lal, Chief Minister	7,382/-	30,434.20	4,329.97	266.10	3,672.68	
2.	Shri Mangal Sein, Minister	6,584/-	37,316.20	1,031.76	293.80	1,200.48	
3.	Shri Prit Singh "	3,366/-	19,837.90	1,271.51	227.90	901.25	

4 .	Smt . Kamla Devi ,,	4,018/-	13,468.00	1,272.45	184.86	2,007.45
5 .	Shri Virender Singh	4,131/-	13,955.90	265.50	177.60	988.80
6.	Shri Satbir Singh „	4,725.20	11,959.00	509.37	259.94	645.00
7.	Shri Tara Singh„	4,579.20	9,112.60	744.73	102.95	979.36
S.	Shri Ram Singh„	5,462.70	14,930.40	637,52	321,9"	-
9,	Smt,Sushma Sawraj ,.	4,013.70	15,359.65	493.53	178.50	1,174.20
10.	Shri Om Parkasb Ex-Minister (1-7-77 to 10-7-77)	—	300.50	—	—	—

श्री शमशेर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा, करेंसे कि. क्या जनता' सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी बात है कि खर्च कम करने के लिए मंत्रीगण के. दौरे तथा टेलीफोन पर कोई सीलिंग मुकर्रर की जाए?

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : जब से जनता पार्टी की सरकार बनी है, मत्रियों को दस दिन से ज्यादा का भला नहीं दिया जाता ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जेल मन्त्री कितने दिन दिल्ली टूर पर रहीं और कितना टी0 ए0 क्लेम किया?

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, इसका मुख्य सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है । अगर माननीय सदस्य अलग से नोटिस देंगे तो उत्तर दे दिया जाएगा ।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय मेरा सवाल मुख्य सवाल से कनेक्टिड है । मैंने यह पूछा था कि मिनिस्टर आफ जेल ने दिल्ली के टूर के लिए कितना टी0 ए0 क्लेम किया?

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, किन तारीखों में वे दिल्ली गई इसको बताने के लिए अलग से नोटिस चाहिए । जितना टोटल टी0 ए0 उन्होंने ड्रा किया वह बता दिया गया है ।

समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदय, जेल मन्त्री होने के नाते मैं इसका जवाब दे देती. हूं । अध्यक्ष महोदय, अनऔफिशियल विजिट के लिए एक दिन का भी दिल्ली का टी0ए0 वसूल नहीं किया ।

श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह दस दिन की टूर की कंडीशन इसी सरकार ने लगाई है या पहली सरकार की है?

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : पहले वाली सरकार की भी थी लेकिन हम उसका पालन स्ट्रिक्टली कर रहे हैं ।

चौधरी संत कंवर : स्पीकर साहब, टेलीफोन का जो खर्चा मन्त्री महोदय ने बताया है वह चीफ मिनिस्टर का है 30434. 20 रुपए और होम मिनिस्टर का 37,316.20 रुपए । क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह हो सकता है कि एक मन्त्री का खर्चा चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा हो?

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन जरूरत के मुताबिक किया जाता है । हो सकता है होम मिनिस्टर को ज्यादा टेलीफोन करने की जरूरत पड़ी हो । यह कोई ऐसी बात नहीं है । मुख्य मंत्री का ज्यादा भी ही सकता है और कम भी हो सकता है यह काम पर निर्भर करता है ।

श्री हीरा नन्द आर्य : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या टेली– कोन सौफिक्यिल बिजनैस के लिए किए जाते है या प्राईवेट कस्म के लिए भी किए गाते हें. ।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : आफिशियल बिजनैस के लिए किए जाते है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 224

यह प्रश्न पूछा नही गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी शेरे सिंह इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Families without Residence in the State

***230. Swami Aditya Vesh:** will the Minister for Social Welfare be pleased to state—

(a) the districtwise number of families who are without residence of their own in, the State at present ;

(b) the number of persons to whom the land has been allotted by the Janata Gov ment for residential purposes and

(c) whether there is an proposal under consideration of the Government to allot and/house to those persons, who. are without residence; its, the time by which the said proposal is likely to materialise

समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती सूषमा स्वराज) :

(क) बेघर परिवारो की संख्या का पता करने के लिये कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया तथा इस कारण से ऐसे परिवारों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । (ख) शून्य । (ग) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के अलावा आर्थिक दृष्टि से कमजोर अन्य जाति के लोगो को भी आवास स्थल अलाट करने का निर्णय लिया है और इस स्कीम को शीघ्रता. से कार्याम्बित, करने के. लिये. कदम उठाये जा रहे हैं।

स्वामी आदित्यवेश : क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि क्या बेघर परिवारों की संख्या जानने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय! सवाल कें क' भाग में मैने बताया है कि कोई ऐसा सर्वेक्षण. नहीं करवाया गया है । सर्वेक्षण कराने का उद्देश्य यह होता है कि लोगों. क्रो मकान र –प्लाट मुप्त दिए कए । शहरी क्षेत्र में. सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि सर्वेक्षण कबने के. बाद मुक्त में प्लाट या मकान अलाट कर सके लेकिन शहरी क्षेत में जहां तक मांग का पता करने का सवाल है उसके लिए. शहरी क्षेत्र में व्यवस्था भी है कि जब हाउसिंग बोर्ड बने हुए महानों के– लिए आवेदन– पल मांगता है तो उसमें हर केटेगरीज के लोग जैसे कमजोर वर्ग के लोग, यानी कम आप वाले, मध्यम आय वाले, 0ंची आय वाले लोग मकानों के लिए आवेदन–पत्र देते हैं और जितने मकानों की ड़िमान्ड बोड के पास आती है उसको देखकर हम यह अन्दाजा

लगाते हैं कि उस शहर में इतने मकानों की डिमान्ड है और उसके मुताबिक. मकान बनाए जाते है ।

चौधरी संत कंवर : मंत्री महोदया ने बताया है कि सर्वेक्षण कराने. का मतलब यह है कि लोगों को मुक्त मकान दिए जाएं । क्या मंत्री महोदया बताने का कष्ट करेंगी कि क्या सरकार का उद्देश्य यह नहीं है कि जिन लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है उनका सर्वे कराएं और उनको मकान दे?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले सवाल के जवाब में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उसका यह अर्थ नही है कि हम मकान नही देते । शहरी क्षेत्रों में हम इसलिए सर्वे नही कराते कि हम मुक्त मकान नही दे सकते । जब हम शहरी क्षेत्र में आवेदन–पत्र मांगते हैं तो उसके मुताबिक मकान बनाकर दे देते ' श्री जय नारायण वर्मा रू क्या मन्त्री महोदया की जानकारी में यह चीज है कि हिसार इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने मकानों तथा प्लाटों में पिछड़ी श्रेणी के लोगो के लिए कुछ कोटा सुरक्षित किया था लेकिन वे मकान और प्लाट उन पिछड़ी श्रेणी के लोगों को नहीं मिले बल्कि वे लोग उनको ले गए जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर नही थे । क्या सरकार का इसके बारे में कुछ– करने का विचार है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : स्पीकर साहब, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमने आय के अनुसार कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि

एल 0आई 0जी0 मकान जिनको मिलेगा उनकी इतनी आमदनी होगी । एक आदमी की जितनी आमदनी है वह उस आमदनी के अनु– सार उस कैटेगरी में मकान के लिए ऐप्लाई करेगा । फिर भी अगर माननीय सदस्य कोई ऐसी शिकायत मेरे नोटिस में लाएंगे तो हम उस पर गौर करेंगे ।

कवर राम पाल सिंह : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदया ने बताया कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के अलावा आर्थिक दृष्टि से कमजोर अन्य जाति के लोगो को भी आवास स्थल अलाट करने का निर्णय लिया हए । क्य. मन्त्री महोदया बमने की कृपा करेंगी। कि जब, आपके पास यहू फिगर ही नही है– कि कितने लोगो को मकान. देने पडेने' और कितने लोगो को प्लाट दे ने पडेंगे. तो सरकार किस तरह से यह निर्णय करेगी कि इतनी जमीन चाहिए?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल शहरी क्षेत की बात कर रही थी । जहां तक देहात का सवाल है उसके बारे में पोजीशन यह है कि पिछली सरकार ने अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के लिए प्लाट्स देने के लिए एक सर्वे कराया था और उसके अनुसार 2 लाख 14 हजार 753 की फिगर उनके पास आई थी और इसमें से 2 लाख, 13 हजार 841 लोगों को उन्होंने मकान नहीं, प्लाट्स दिए । बाकी 1 हजार 112 प्लाट्स रह जाते हैं । इसके साथ ही साथ मैंने सवाल के 'न' पार्ट के जवाब में बताया है कि अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के अलावा आर्थिक

दृष्टि से कमजोर अन्य जाति के लोगों को भी आवास स्थल अलाट करने का निर्णय लिया है । इससे हमको 71 हजार प्लाट देने पड़ेंगे । हम रैवेन्यू डिपार्टमैंट से सर्वे करा रहे हैं और हमने रैवेन्यू डिपार्टमैंट को हिदायत जारी कर दी हैं कि वे 71 हजार प्लाट देने के लिए जमीन एक्वायर करे ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि गांव में पंचायत की कामन लैड फ्री मिल जाती है इसलिए वहां पर की बांट देते है और शहरों में जमीन नही मिलती इसलिए यहा पर की नहीं देते । क्या मन्त्री महोदय गांव की तरह ही शहर में भी की जमीन लेने के बारे में कोई विचार करेंगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, हमें वास्तिवकता से आंखें नहीं बन्द करनी चाहिए । गांवों में हमें जितनी आसानी से भूमि उपलब्ध हो सकती है शहरों में उस लिहाज से बहुत कमी है ।

स्वामी आदित्यवेश : मंत्री महोदया ने अभी बताया है कि जो बेघर परिवार हैं उनके आंकड़े इकट्ठे नहीं किए गए । क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि क्या भविष्य में आंकड़े इकट्ठे करने का सरकार का कोई विचार है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने इस बारे में पिछले सवाल के जवाब में बताया है कि देहाती क्षेत्र से हमारे पास 71 हजार के

आंकडे आ चुके हैं और शहर में ऐसा सर्वे कराने का कोई विचार नहीं है ।

श्री शमशेर सिंह : स्पीकर साहब, इसी हाउस में पिछले सेशन में सरकार ने इस बात का वचन दिया था कि गांव की तरह शहर में भी पिछड़ी श्रेणी तथा कमजोर वर्ग के लोगों को प्लाट दिए जायेंगे । क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि क्या जो कुछ उन्होंने आज कहा है वह पहले वाले आश्वासन के उल्ट नही है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की एक योजना पिछली सरकार ने बनाई थी कि शहरों में भी 3600 रुपए सालाना से कम आमदनी वाले लोगों को, एन0ए0 सी0 के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भूमि और म्युनिसिपल कमेटी श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के लोगों को मकान अलाट किए जाएंगे लेकिन यह योजना केवल कागजी बनकर रह गई । न तो यह निश्चित किया गया कि यह भूमि किस तरह से ली जाएगी, न यह निश्चित किया गया कि बैंकर्ज कौन होंगे, ऋण का बन्दोबस्त कहां से किया जाएगा । इस योजना को हमने समाप्त नहीं किया है और अभी भी यह सरकार के विचाराधीन है । ज्यों ही इस पर कोई निश्चित योजना बन जाएगी मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर दूंगी ।

चौधरी ईश्वर सिंह : क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि हरिजनों को कब तक बकाया प्लाट दे दिए जाएंगे?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय एक हजार एक सौ बारह प्लाट्स जो बकाया हैं उनमें से 1 हजार 53 कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में और 59 सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में देने हैं । कुरुक्षेत्र के लिए डिप्टी कमिश्नर की डिस्पोजल पर फंड्ज रखे गए हैं और भूमि एक्वायर करने के लिए 4 और 6 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है । नसैसरी फार्मेलिटीज पूरी होने के बाद प्लाट दे दिए जाएंगे । सोनीपत में एक दिक्कत आ गई है कि वहां पर स्टे आर्डर हो गया है जैसे ही स्टे आर्डर समाप्त होगा 59 प्लाट दे दिए जाएंगे । जहां तक 71 हजार प्लाट देने की बात है उसके सम्बन्ध में रैवैन्यू डिपार्टमेंट को पूर्ण हिदायतें दे दी गई हैं जैसे ही फार्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी वे प्लाट भी दे दिए जाएंगे ।

चौधरी संत कंवर : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदया ने अपने जवाब में बताया है कि सरकार इस स्कीम को लागू करने के लिये कदम उठा रही है । क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि उन्होंने कोई नोटिस पंचायतों के पास भेजा है क्योंकि गांव के लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार की क्या–क्या स्कीमें है जिसके तहत लोगों को प्लाट दिये जाएंगे?

श्रीमती सुषमा स्वराज : रैवेन्यू विभाग के आफिसरों को हिदायतें दे दी गयीं है और वे लोग स्वयं वहां जाकर उसका निरीक्षण क्र रहे है ।

चौधरी हुक्म सिंह : क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि देहातों में जो जमीन ली गई है वह पंचायतों से ली गई है या किसानों से ली गई है और किस भाव पर ली गई है?

श्रीमती सुष्मा स्वराज : ज्यादा से ज्यादा जमीन पिछली सरकार ने शामलात देह पंचायतो से ली थी ।

श्रीमती शकुन्तला भगबाडिया : क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि यह जो स्कीम है यह हर जिले में चालू की गयी है या कि सिर्फ कुरुक्षेत्र जिले के लिये है?

श्रीमती सुष्मा स्वराज : कौन सी स्कीम की बात कर रही है आप?

श्रीमती शकुन्तला भगवाडिया : यह जो प्लाट पर मकान बनाकर दैने वाली स्कीम है ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह स्कीम सारे हरियाणा के हरेक जिले को कवर कर रही है ।

चौधरी वीर चन्द : क्या मन्त्री महोदया– क्याने की कृ पा करेगी कि सरकार जिन गरीब लोगों को प्लाट देना चाहती है एं क्या उनको उन प्लाटो पर मकान बनाने के लिये कोई कर्जा या ग्रांट भी देने का विचाररू रखती है ताकि वे लोग मकान भी आसानी सें बना सकें?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो प्रोपोजल इस प्रकार थी कि बैन्क द्वारा ऐसे लोगों को 4 प्रतिशत दर पर 3 हजार रुपया लोन दिलवाया जाता था लेकिन हाल ही में । एक मीटिंग में हम लोगों ने यह फैसला किया कि अगर लोगों को यह बैक की सुविधा दी जायेगीं तो शायद मकान पूरे न बर्न सकेंगे क्योकि पिछली दफा हमने देखा कि प्लाट तो बांटे गये 2 लाख 13 'हजार' के, करीब लेकिन मकान केवल 2 हजार या इस से भी कम ही बने थे 'तो हम ने हुडको की रुरल हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत यह फैसला किया है कि आधी मकान की कीमत हुडको वाले देगे और आधी हम लोग यानी राज्य सरकार बैक से ले ले जिससे कि खुद मकान बनाकर लोगों को दे सके तब तो आवास की पूरी प्रोबलम समाप्त हो जायेगी बजाये इसके कि उनको कर्जों दिलवाकर यह कहा जाए कि वे मकान खुद बनवाए ।

कंवर राम पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, ' क्या मन्त्री ''महोदया यह बताएगी कि जिस प्रकार गांवों में शामलात देह और पंचायतों से जमीन लेकर लोगों को प्लाट दिये जाते हए क्या उसी प्रकार सरकार शहरों में म्युनिसिपल कमेटियों की मिट बढ़ाकर और उनकी. जमीन एक्वायर करके लोगों को शहरों में भी प्लाट नही दे सकती और क्या हुस प्रकर की व्यवस्था करने में क्या सरकार को कोई रुकावट है ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, इस का जवाब मैंने दिया था कि शहरों में जमीन हमें उपलब्ध नही होती है ।

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि इसकी लिमिट और बढ़ा दें ।

कंवर राम पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, पंचायतों की जमीन तो ले ली जाती है लेकिन शहरों में कही पर इंडस्ट्रीयल एरिया बनाना हो या इंडस्ड़ी लगानी हो वहा पर नौटीफिकेशन के द्वारा सरकार जमीन एक्वायर कर लेती है इसी तरह से सरकार शहरों में गरीब आदमियों के लिये भी नौटीफिकेशन करके मकान बनाने के लिये क्यों नही जमीन एक्वायर कर रही, क्या सरकार की इसमे की इस मे कोई रुकावट है

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पंचायतों की जमीन का ताल्लुक है, पंचायत एक्ट में उस बारे लिखा हुआ है कि शामलात देह किन–किन चीजों के लिये इस्तेमाल की जा सकती है और उसमें एक प्रोविजन. हे कि हरिजन और पिछड़ी जाति के लोगों को बसाने के लिये शामलात देह का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन म्युनिसिपल कमेटी की जमीन के लिये ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं हैं ।

चौधरी लाल सिंह : क्या मन्त्री महोदया बताएंगी. कि जो सहूलियतें हरिजनों को गांवों में दी जाती हैं उसी तरह से उन लोगों को भी सरकार वे सहूलियतें देने का विचार रखती है जो हरिजनों से भी नीचे तक जा चुके हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, मैं ने बताया है कि 71 हजार प्लाट उन्हीं लोगों के लिये हैं जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं और अनुसूचित या पिछड़ी जाति के नहीं है ।

चौधरी राजेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब गुड़गांव में हा0सिंग बोर्ड की तरफ से एक कालोनी बनायी गयी है और उस कालोनी को बने अभी एक ही साल हुआ है, उन मकानों की छत्ते, दीवारें गिर गयी हैं और मन्त्री. महोदया स्वयं वहां का निरीक्षण भी कर के आयी हैं । क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि जिन आफिसर्ज की रहनुमाई में वे मकान बने हैं, क्या सरकार उन आफिसर्ज के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती हे?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, जैसा किं आदरणीय सदस्य ने बताया वह ठीक है । मैं ने ज्यू ही यह शिकायत अखबार में पढ़ी मैं वहां पर निरीक्षण के लिये गयी थी और उसके फौरन बाद मैं ने एक आफिसर श्री शर्मा को उसकी इंक्वायरी के लिये डिप्यूट किया है उसकी रिपोर्ट एक महीने तक मेरे पास पहुंच जाएगी ।

चौधरी गंगा राम : क्या मन्त्री महोदया बताएंगी. किं पंचायतों की– जो जमीन प्लाटों के! लिये सरकर ने ली है उसके बदले. में सरकार ने उनको कितना पैसा दिया है? इसके अलावा हरियाणा के अन्दर केवल बैक–वर्ड क्लासिज के लिये सरकर ने कितने प्लाट अलाट किये हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, कहां तक पहले सवाल का ताल्लुक है उसके बारे में इतना ही कहना हे कि यह जो पंचायतों की जमीन थी, यह पहली सरकार ने ली थी और उसने कोई पैसा नही दिया था और जैसा कि मैंने बताया है कि पंचायत एक्ट में यह लिखा है कि हरिजनो और पिछड़ी जाति के लोगों को बसाने के लिये वह जमीन इस्तेमाल की जा सकती है । जहां तक दूसरे प्रश्न का ताल्लुक है, उस बारे मुझे इतरा ही कहना है कि बैकवर्ड क्लासिज के लिये 77994 की फिगर्ज आयी थी, 77511 प्लाट केवल माल बैकवर्ड क्लासिज को दिये गये हैं ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, पंचायत एक्ट में यह लिखा है कि पंचायत अपने गांव में किसी गरीब आदमी को अगर चाहे तो जमीन दे सकती है, सरकार जबरदस्ती पंचायत की जमीन नहीं ले सकती, क्या मन्त्री महोदया इस बात की तशरी करेगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने पंचायत की जमीन ली थी, यह सौदा उसी ने ही किया था आज की सरकार ने कुछ नहीं किया ।

चौधरी गुलजार सिंह : अध्यक्ष महोदयय मन्त्री महोदया ने बताया कि गांव में जो गरीब आदमियों को मकान दिये जाते हैं वे उनकी आमदनी के हिसाब से दिये जाते हैं । क्या मन्त्री

महोदया बताने का कष्ट करेंगी कि यह जो आमदनी वाला हिसाब किताब है, सरकार ने इसके लिये क्या क्राईटेरिया फिक्स कर रखा है क्योंकि जो बहुत अमीर आदमी है वे ही इन प्लाटों को हड़प कर जाते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि इन प्लाटों को बांटने का सरकार ने क्या तरीका अपना रखा हे?

श्रीमती सुषमा स्वराज : आमदनी में फैमिंत्री इंकम देखी जाती है जिनकी सालाना आमदनी 3600 रुपये से ज्यादा हो उनको यह मकान नही दिये जाते ।

चौधरी संत कंवर : क्या मन्त्री महोदया फरमाएंगी कि जब से उन्होंने अपना मंत्रालय संभाला है, तब से कितने बेघरों को प्लाट अलाट किये गये हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर के 'ख' भाग में शून्य कहा है ।

श्री हरफूल सिंह. क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि जो पंचायत की जमीन है वह बगैर कीमत दिये नही मिल सकती क्या यह ठीक है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी राम किशन : स्पीकर साहब, इस तरह की स्कीम और नगरों में तथा यहां पंचकूला में भी चालू हे । क्या मंडी

महोदया बताने की कृपा करेगी कि इन मकानों की अलाटमैंट के लिये कौन सी नीति निर्धारित कर रखी है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, इसमें तीन तरह की श्रेणियां हैं :–

ई. डब्ल्यु एस. एल.आई.जी. और एम.आई. जी. । अगर आनरेबल मैम्बर साहेबान सारी डिटेल पूछना चाहें तो मैं बता देती हूं । अध्यक्ष महोदय 350 रुपये तक की आय वाले लोग वे ई. डब्ल्यु.एस. ग्रुप मे ऐप्लाई कर सकते हैं, 351 से 600 तक की आय वाले एल. आई. जी. ग्रुप में, 601 से 1 500 तक की आय वाले एम. आई. जी. में और 1501 से पर वाले एच. आई. जी. में ऐप्लाई कर सकते है ।

श्री हीरानन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, नबी महोदया ने अभी कहा कि पंचायत की जमीनों को ग्रहण करने के लिये सरकार को पूरा अख्तियार है, ऐसा कानून में है । क्या मन्त्री महोदया बताने का कष्ट करेंगी कि शहरों में म्युनिसिपल कमेटियो की जमीन को एक्वायर करने में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है और क्या इस बारे में सरकार ऐक्ट में तरमीम करने का कोई विचार रखती है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, अगर तरमीम की भी जाए तो इसका. कोई ज्यादा फायदा हो ने वाला नहीं है ।

में आप भाइयों को बता देती हूं कि देहात और शहरों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है । अगर हम अलग से भूमि देते हैं तो 4000 रुपये तक उनको कर्जा लेना होता है । हमने शहरों में गरीब.। के लिये 5000 रुपयें तक की आप के मकान बनाये है जिसके लिये उन्हें एक रुपया प्रतिदिन के हिसाब से किश्त देनी पड़ती है, वह भी मुफ्त के माफिक पड़ता है ।

चौधरी हरिचन्द्र हुड्डा : क्या मंन्ली महोदया बताने की कृपा करेंगी कि जब कि पिछ ने पंचायत के कानून अच्छे नहीं थे और मन्त्री महोदया ने उनको क्यों नही बदला और इस प्रकार थ्यूरी और प्रेक्टीकल में जो फर्क है क्या उस फासले को माप कर बतायें गी'?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, पंचायत के कानुनों को अकेली हाउ– सिंग मिनिस्टर नहीं बदल सकती ।

Tourist Centres

***252. Chaudhri Sant Kanwar :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open new Tourist Centres in District Rohtak; if so, the details and location thereof ?

शिक्षा मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

चौधरी संत कंवर : क्या मन्त्री महोदया बताएंगे कि ये पर्यटन स्थल फायदे में चल रहे हैं या नुकसान में । अगर फायदे में चल रहे हैं तो डनकी ऐनुयल इंकम क्या है?

कर्नल राव राम सिह : जो टूरिजम डिपार्टमैंट से या होटल इंडस्टरी से ताल्लुक रखने वाली संस्थाएं हैं उनको पहले खर्च करना पड़ता है उसके बाद वह पिकअप करती हैं । आम तौर पर जो बड़े–बड़े होटल वालों ने कैलकुलेट किया है. उसके मुताबिक रिटर्न 6– 7 साल के बाद शुरु होती है इसके बावजूद भी हमारे टुरिस्टस कम्प्लैक्स में थोड़ा बहुत फायदा होने लग गया है ।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह : मन्त्री महोदय ने बताया है कि फायदा होना शुरु हो गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि हरिया णा सरकार ने टूरिजम कार्पोरेशन को कितना पैसा शेयर कैपिटल के रूप में दिया हुआ है और सरकार को उससे कितनी इंकम हो रही है?

कर्नल राव राम सिंह : जो डटे भे आप पूछ रहे हैं कि कितना शेयर कैपिटल है यह इस सवाल से संबधिंत नहीं है । यह सवाल तो रो हतक िरिस्ट कम्पलैक्स से के जो फायदे होते हैं वे यह हैं कि इनसे हरियाणा प्रान्त की एडवरटाइज भेंट दूनिया में होती है ओर इस बात में फाईनैशियल इम्पलीकेशंज का कोई ताल्लुक नही होता ।

चौधरी गंगा राम : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि ये पर्यटन केन्द्र रो हतक में भी हैं, पानीपत में हैं और सोनी पत में भी हैं लेकिन गोहाना बीच में खाली पडा है । क्या गोहाना में भी कोई पर्यटन केन्द्र खोला जाएगा?

कर्नल राव राम सिंह : इस वक्त ऐसा कोई प्लान नहीं है कि गोहाना में भी कोई पर्यटन केन्द्र खोला जाए ।

Roads Repaired in the State

***262. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the steps taken or proposed to be taken by the Government to repair those roads which were damaged during the recent floods in the State and the time by which the aforesaid roads are likely to be completely repaired ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) The following steps are being taken :—

(i) Carrying out necessary repairs to demaged roads including raising and rebuilding them, if necessary in a phased programme.

(ii) Provision of additional water-ways required for cross drainage purposes.

It is expected that the Main Roads taken up for repairs will be made traffic worthy before July, 1978 and other roads where the work has been started or is being started will be completed upto earth work stage before the monsoons.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि सारे हरियाणा में कितनी सड़कें फन्डज से डेमेज हुई हैं और उनका जिलावार नंबर क्या है? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हर साल जो अरबों रुपये का फलडज. की वजह से नुकसान होता रहा है उसको बचाने के लिये अगली बरसात से पहले क्या सड़कें बना देंगे और इसके लिये क्या सरकार कोई स्टैप उठा रही हे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इस सवाल के दो भाग है । पहले मैं नंबर और नाम बताता हू ।

रोहतक सर्कल

रोहतक–झज्जर रोड, झज्जर–रिवाडी रोड, झज्जर–फरख नगर रोड, झज्जर बादली रोड, झज्जर–छारो रोड, सांपला –छारा रोड, खरखोदा सांपला रोड, रोहतक–पानीपत रोड, रोहतक–खरखोदा दिल्ली बार्डर, रोहतक–जींद रोड, रोहतक–भिवानी रोड छारा–दुजाना रोड, रिवाडी–पटोदी रोड, बहादुरगढ़–झज्जर रोड । ऐप्रोच रोडज यह हैं –

बहादुरगढ़–झज्जर रोड, कि गाना, चन्दौल, शिदीपुर, शाहपुर, अटैन मु ढेर, सुडानी, लुकसर, रिवाडी, रेवाड़ी खेड़ा, बामडाली, सारी बादली को आ रही हैं जराब पुर, सुराख, साल्हाबास, निवदा, इशरी, नून माज रा, लोहा खुर्द, महमूद माजरा समस्त पुर, सलौदा, नगलिया, भूरावास, कुंमावास, चेलावास,

कसाला, रूंडकी, नया बांस, देवराखाना, मुंडाखेडा, बरमा, गोराबास, चन्दाबात, जिवाडा, मलियासी, चिंकी चमारियां, आसन, बिखरी, हासावास, बहालगढ, खरमान, यकूबपुर स्पीकर साहब यह लम्बा काम शुरु हो गया है ।

श्री अधयक्ष : शायद मैंबर साहबान इतने में ही सैटिसफाइड हो गये होंगे ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं सारी ही पढूंगा जी ।

(आवाजें. स्टेटमैंट टैबल पर ले कर दी जाए ताकि समय की बचत हो सके)

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह मेरी मर्जी है मैं सारी ही पढूंगा । स्पीकर साहब, मेरे से सवाल पूछा गया है और मैं सारी स्टेटमैंट पढूंगा । '

आवाजें : हाउस का समय बचाने के लिये स्टेटमैंट सदन में रखे दी जाए ।

श्री अध्यक्ष : आप पोहलू साहब से पूछ लें जिन्होंने यी सवाल किया है ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : स्पीकर साहब, कैथल सब डिवीजन कां बता दे । (विध्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, करनाल सर्कल के बारे में मैं बताता हूं । इसमें ये सड़के हैं रू–भाना करोडा रोड, करनाल कैथल रोड, पुडरी–राजौंद रोड, पाई– हथोला रोड, रसीना–सिसाई रोड, । पुडरी–हाबरी रोड, कैथल–कनौरी रोड, पौदा–हरसोला रोड, कैथल–गुहला रोड, कैथल–राजौंद रोड, आसंध–राजौंद रोड, जैसंख–नगूरा रोड ।

एप्रोच रोडज टू दि विलेजिज

हरसोला माजरा, पौदा देवीगढ़, ननहेडा, रामसावाद, पाई, भाना, साच, हाबडी, सिरसन और हरसोला ।

Mr. Speaker : As I can see from the general sense of the House, since the answer is very long, the *information be put on the Table of the House.

श्री शमशेर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि अम्बाला हिसार स्टेट हाई वे जो है वह पिछले दस दिनों से मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिये बन्द पड़ा है वह कब तक चालू हो जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : बहुत जल्द चालू हो जाएगा ।

श्री मूल चन्द मंगला : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि गुड़गांव जिले में पहले ही सड़कें बहु त कम थीं और अब बारिश की वजह से तथा फल्ड की वजह से बहुत सी सड़कें खराब हो

गई हैं क्या इनको बनाने के लिये प्रायरिटी दी जाएगी अगर दी जाएगी तो वे कब तक मुकम्मल हो जाएंगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जो सड़कें फल्ड की वजह से डैमेज हो गई हैं उनके लिये साढ़े बारह करोड़ रुपया चाहिये । इस फाइनैशियल साल में 31–3–7 8 तक इन पर तीन करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाएगा और अगले साल में हमने दो करोड़ रुपया बजट में प्रोवाइड किया है । हम इनको फेज्ड प्रोग्राम में तैयार करेंगे लेकिन जीपेबल रोडज मौनसून से पहले तैयार करवा दी जाएंगी ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि फडज की वजह से जो सड़कें टूट गई हैं उनके अलावा जो सड़के टूटी हुई हैं उनके लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इस बारे में मैंने परसों विस्तारपूर्वक बता दिया था । मैं समझता हूं बारबार एक सवाल पूछने से सदन का समय ही खराब होता है ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि सड्कों को इन डेट्स तक कम्पलीट कर देंगे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इनके पास फंडज है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैंने अभी बताया कि हमें पूरा रुपया साढ़े बारह करोड चाहिये तीन करोड़ हम 31–3– 78 तक खर्च कर ओंने और दो करोड़ रुपया अगले साल में जून तक खर्च करेंगे ।

चौधरी लहरी सिंह मेहरा : मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सड़कें 20–20 या 30–30 मील लम्बाई हैं और बीच में उन पर या तो कोई पुल बनना रहता है या एक डेढ मील का टुकड़ा बनना रहता है जिसकी वजह से वह बेकार पड़ी है क्या उनको बनाने में प्रायरिटी दी जाएगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जो मैप्स रहते हैं उनको बनाने में प्रायरिटी दी जाएगी और जो ब्रिजज रहते है उनके लिये फिलहाल फंडज का प्रोवीजन नही है ।

चौधरी खुरशीद अहमद : क्या मन्त्री महोदय फरमाएंने कि जो सडकें तकरीबन हर फल्ड में टूट जाती हैं उनकी रिपेयर करते वक्त, कंस्ट्रक्शन करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि आयंदा फल्ड से न टूट पाए?

श्री वीरेन्द्र सिंह : अगर मेरे दोस्त कोई खास किस्म का मैटीरियल बताएंगे तो सरकार खुशी से उसको इस्तेमाल करेगी ताकि वे न टूटे ।

चौधरी खुरशीद अहमद : जहां तक मैटीरियल का ताल्लुक है, मैं मन्त्री महोदय से यही कहूंगा कि अर्थ–वर्क को 0ंचा कर दिया जाए तो शायद नुक्सान न हो ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : . यह तो पहले ही कर रहे है ।

Persons on the Live Registers

***273. Chaudhri liar Swarup Bura :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the district-wise total number of persons on the Live Registers of Employment Exchanges in the State as on 31.12.77; and

(b) the total number of persons out of those referred to therein part (a) above who will be overage with in two or three years to come ?

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik)

(a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

Statement

(a) District-wise total number of persons on the Live Registers of Employment Exchanges in the State as on 31-12-77 is given below

Name of the District	Total No. of persons on the Live Registers of Employment Exchanges in the Distt. as on 31-12-1977.
Ambala	50021
Kurukshetra	16943
Kar nal	32397
Rohtak	31105
Sonep at	19539
Jind	14536
Bhiwani	15683
Gurgaon	43470
Mohin dergarh	19223
Hiss ar	26073
Sirsa	6497
Total :	275487

चौधरी हरस्वरूप बूरा : जो लोग बहुत जल्दी ओवर–एज– होने जा रहे हैं उन का ध्यान रखते हुए, क्या सरकार एम्लायमैंट एक्सचेंज– और एस.एस.एस. बोर्ड में जो सर्विसिज निकलती हैं, उन में इन लोगों को एम्लायमैंट देते के लिए प्रैफरैस देगी?

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, हर सर्विस के लिए, जो एम्लायमैंट एक्सचेंज और एसएमएस. बोर्ड से निकलती हैं, 'डेट मुकर्रर होती है । क्लर्क की गेस्ट के लिए अलग टीजर्ज की पोस्ट के लिए अलग डेट्स फिक्स होती हैं । क्या मेरे साथी बतायेगे कि कौन सी श्रेणियों में प्रैफ्रैस चाहते हैं । इसके' लिए अलग से नोटिस दे दें, जवाब दे दुंगा ।

श्री जयनारायण वर्मा : क्या मन्त्री महोदय बनाने का कष्ट करेंगे कि जो ओटोनोमस बौडीज और निगम हैं, इम्प्रवूर्मेट ट्रस्ट है कारपारेशन्ज है, ये सर्विसिज के लिए कैडीडेट्स सीधे ही भर्ती कर लेते है और इस. वजह से इम्पलौयमैंट एक्सचेंज में लगी लम्बी क्यू (लाईन) लगी रहती हैं? क्या सरकार इस बारे में हिदायतें जारी करेगी कि वे सीधे भर्ती न करें?

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : जितनी कारपोरेशन्ज हैं, प्राईवेट अंडरटोंकग्ज हैं, उनको महकमे की तरफ से यह हिदायत जारी कर दी गई है कि वे सर्विसिज एम्पलाय– मेट एक्सचेंज की मारफत भर्ती करें । अगर मेरे साथी को कोई शिकायत हो तो वह शिकायत मेरे नोटिस में लाएं, हम छानबीन कर लेंगे ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : जो लोग ओवर–पुज हो जाएंगे और इसकी वजह से उनको सर्विस कहीं नहीं मिलेगी । क्या सरकार इनके लिए अन–एम्पलायमैंट अला0ंस देने का इन्तजाम करेगी? क्या कोई प्रपोजल सरकार के विचाराधीन है?

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : अलाउंस देने की कोई बात विचाराधीन नही है ।

श्री फतेह चन्द विज : जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया कि डिपार्टमैंट को हिदायत जीरी कर दी है । क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि यह हिदायत कब जारी की हैं?

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद की है ।

Officers/Officials belonging to Backward Classes

***241. Chaudhri Ram Kishan :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Class **I**to Class IV Officers/Officials belonging to Backward Classes in the State ; and

(b) whether the percentage fixed for Backward Classes in the services is up to mark ; if not, the steps taken or likely to be taken by the Government to achieve this end ?

Revenue Minister (Shri Preet Singh)

(a) The classwise position as on 1-1-1977 is given below :—

Class	No. of Officers/Officials belonging to Backward Classes

I	_____
II	24
III	5207
IV	2792

(b) In class I and II services the percentage fixed for Backward Classes is not upto the mark, whereas in Class III and IV their representation is much higher compared to the percentage fixed for Backward Classes. The Government have taken the follow, ing steps to achieve the objective of improving their representation in services :—

(i) The Backward Classes persons are given relaxation of 5 years in upper age limit for all posts under the State Government.

Only '1/4 the(ii) Only 1/4th of the prescribed fee is charged from Backward Class candidates.

(iii) The unfilled reserved posts are carried forward for a period of two years so that candidates belonging to Backward _Classes become available.

(iv) The posts are readvertised if in the first instance suitable candidates are not available for the posts reserved for the persons belonging to Backward Classes.

(v) If the candidates belonging to Scheduled Castes are not available on the reserved posts meant for them after their advertisement thrice then these posts are filled up from amongst the candidates belonging to Backward Classes

in the first instance before treating them as reserved.

श्री जयनारायण वर्मा : स्पीकर साहब, सवाल के पार्ट(बी)के जवाब में बतलाया गया है कि पिछडी श्रेणियों का कोई अधिकारी–क्लास वन अफसर नहीं है और क्लास टू के सारे हरियाणा में केवल 24 अधिकारी है। क्या इस दयनीय स्थिति को देखते हुए 2 प्रति शत रिजवेशन जो रखी गई है इन बैकवर्ड क्लासिज की दयनीय स्थिति को हल करने में सक्षम होगी? चुनाव घोषणा पत्र में जो जनता के साथ वायदे किये थे क्या सरकार उनको पूरा करेगी?

श्री प्रीत सिंह : गवनमैंट ने पहले ही बैकवर्ड क्लासीज को काफी कसैंशन दिया हैं । जहां सूटेबेल कडीडेटस आते है उन को रिक्रूट किया जाता है? और जहां नहीं मिलते वहां अन–फिल्ड पोस्टों को अगले साल के लिए कैरी फारवर्ड किया जाता है और दोबारा पोस्टों को ऐडवरटाईज किया जाता है ।

चौधरी राम किशन : जैसा मन्त्री महोदय ने सवाल के जवाब यें कहा है कि जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स' को कंडीडेट अवेलेवल नहीं होता तो बैकवर्ड क्लासिज के कंडिडेट को प्रैफैसं दी जाती है । क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि वे कौन–कौन से नाम हैं, किस–किस जगह पर ऐसा किया गया है ।

श्री प्रीत सिंह : अभी तक गवर्नमैंट के पास ऐसा कोई नाम नहीं आया।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : बैकबर्ड क्लासिक के लिए 10 परसैन्ट की रिजर्वेशन थी, लैकिन गवर्नमैंट ने घटाकर 2 परसैन्ट कर दी है जबकि शिडयूल्ड कास्ट की आबादी 10 परसैंट से 20 परसैन्ट तह बढ चुकी है । क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि 10 परसैन्ट से 2 परसैन्ट रिजर्वेशन क्यों की ?'

श्री प्रीत सिंह : गवर्नमैंट ने रेता कोई फैसला नहीं किया जिसमें 10 परसैंट से 2 परसैन्ट रिजर्वेशन की हो ।

चौधरी गंगा राम : स्पीकर साहब, क्लास वन में बैकवर्ड क्लासिज का एक भी कामरेड नही लिया गया और क्लास दो में भी पूरा कोटा नहीं दिया गया । क्या सरकार बैक वई क्लासिज को पूरा कोटा देने का प्रबन्ध करेगी? इसके अलावा मैं यह भी पूछना चाहता हूं, जैसा कि पड़ौसी प्रदेशों में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब प्रदेश में 10 परसैन्ट सर्विसिज में रिर्जवेशन को हूई, क्या हरियाणा सरकार के विचाराधीन कोई प्रपोजल है, जिसके तहत कोटा बढ़ा दिया जाए?

श्री प्रीत सिंह : जहां तक रिजर्बेशन में डैफिशिएंसी का सवाल है, गवर्नमैंट इसको पूरा करने को कोशिश करेगी, लेकिन रिजर्वेशन बढाने की कोई विचार नहीं है ।

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर साहब, शिडयूल्ड कास्ट्स का कोटा पूरा नहीं है, कृपया मन्त्री महोदय स्पैशल रिक्रूटमैंट करके कोटा पूरा करने को कृपा करेंगें ?

श्री प्रीत सिंह : स्पैशल रिक्रटमैंट करने का कोई विचार नहीं है । लेकिंन जहां पर सूटेबल कंडोडेट नहीं आते वहां पोस्टों को दोबारा एडवरटाईज किया जाता है और दो साल के लिए वे पोस्टें कैरी फारवर्ड की जाती है

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब, बैकवर्ड क्लास और शिडयूल्ड कास्ट की रिजर्वेशन जात पात के आधार पर नहीं होनी चाहिए, इनकम के आधार पर होनी चाहिए । क्या इनकम के आधार पर रिजर्वेशन करने का विचार सरकार के विचाराधीन है अगर नहीं है तो क्या विचार करने के लिए तैयार हैं?

श्री प्रीत सिंह : यह तो सैन्ट्रल गवर्नमैंट की पालिसी है, जो सैन्ट्रल गवर्नमैंट डिसाईड करेगी, स्टेट उसी के हिसाब से करती है ।

Construction of Roads

***287. Chaudhri Shiv Ram Verma :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the number of roads which are likely to be constructed during the current financial year in the State together with their total length in kilometres and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct the following roads ; if so, the time by which these are likely to be constructed ?

1. from village Anjan Thali to Travari in Nilokheri

Constituency;

2. from village Anjan Thali to village SohIon ;

3. from village Lalyani to Travari ;

4. from village Sitamarh to village Bahola via village Mohri ;

5. from village Sitamarh to village Brass ;

6. from village Salarpur to Village Suneheri;

7. from village Amin to viliage Fatuhpur;

8. from Jamba Kirmich road to village Kuwar Kheri ;

9. from Nilokheri-Karsa road to village Budhera ;

10. from Nilokheri-Karsa road to village Bhukapuri ;

11. from village Hathera to village Raison ;

12. from Janjhari-Lalyani road to village Sultanpur ;

13. from Nilokheri-Karsa road to village Soodhpur ;

14. from village Butana to village Sherpur ;

15. from village Jarba to village Gittalpur ;

16. from village Jarba to Borsham ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) :

(a) 320 roads covering a length of 550 kilometers are likely to be constructed during the financial year 1977-78.

(b) Yes, expect the roads mentioned at Sr. No. 3, 5, 11, 14 and 15. It is not possible to indicate a time schedule as the progress would depend upon the availability of funds.

चौधरी शिव राम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया कि सारे हरियाणा में, चालू साल में 320 सड़कें बनाई जाएंगी, और वे 550 किलोमीटर लम्बी बनाई जाएंगी । मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा ये सडकें जिस–जिस जिले में, कितनी–कितनी सड़कें कितनी– कितनी लम्बाई की बनाई जाएंगीं, यह डिस्ट्रिक्ट वाईज बता दें ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले अम्बाला से शुरु करता है–

(1) शाहपुर टू नगला, 4 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर बना दी गई है ।

(2) होली टू गगनपुर 1. 80 में से 1. 50 कम्पलीट है ।

(3) अम्बाला हिसार रोड टू कलावरपुर 7.10 में से 8. 10 कम्पलीट है।

(4) वराडा टू चौलमाजरा, 3.80 में से 1.80 कम्प्लीट है ।

(5) जी टी. रोड टू मछौंदा, 1 20 से 0 7 कम्प्लीट है ।

आवाजें – स्टेटमेंट लम्बी है, हाउस का समय बचाने के लिए इसको सदन की मेज पर रख दिया जाये । –– (व्ययधान) –

जेब मेरे से सवाल पूछा गया, तो I shall have to reply.

चौधरी भजन लाल : ये पूछ रहे हैं, कहां कहां बनाई जाएंगी । – (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : जो बनाई गई हैं, वह पूछ रहे हैं–– (व्यवधान) – सवाल तो उनका है–– (व्यवधान)जब पूरा जवाब देता हूं तो मैंबर साहिबान जवाब नही देने देते ।

चौधरी शिव राम वर्मा : मैं पूछना चाहता हूं कि 31 मार्च तक कौन–कौन सी सडकें हैं, जो मु कम्मल हो जाएगी। जो कर दी गई है, वह अलग बात है । – (व्यवधान) –

श्री अध्यक्ष : वही तो ये बता रहे हैं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : वही तो बता रहा हूं । इन में से कितनी लैंथ हो चुकी हैं और जो बाकी रहती हैं वह 31 मार्च तक पूरी कर दी जाएगी, आप जरा सब रखें (व्यवधान)

आवाजें : स्टेटमैंट को टेबल पर रख दीजिए ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह मेरी मर्जी है मैं टेबल पर रखुं या नहीं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक तरफ तो पूछते हैं कौन कौन सी सड़कें कम्पलीट हो गई हैं और जब मन्त्री जवाब देते हैं तो इतराज किया जाता है, Then why should you ask such a question 'which requires a lengthy reply ?

चौधरी शिवराम वर्मा : : अध्यक्ष महोदय, अगर जवाब लम्बा है तो इसे टेबल पर ही रखवा दो (विध्न)

चौधरी रिजक राम : स्पीकर– साहब, आनरेबल मैम्बर ने एक सवाल पूछा, उसका जवाब मंत्री जी दे रहेहैं लेकिन स्पीकर साहब को इसमें बड़ी भारी डिसक्रिशन है कि यदि जवाब की युटिलिटी कम हो, टाईम ज्यादा कंज्यूम हो रहा हो तो उसे टेबल पर रखवा सकते हें ताकि और सवालों का भी नम्बर आ जाए ।

श्री अध्यक्ष : पिछली दफा रखवा दिया था । I requested the hon. Minister to put it on the Table of the House but he has again asked the same sort of question.

चौधरी रिजक राम : मंत्री महोदय जवाब ले कर दें ।

Mr. Speaker ; I request the Hon. Minister to puts it on the Table of the House but kindly do not ask such long questions again.

चौधरी हरस्वरुप बूरा : क्या मन्त्री जी बताएंगे कि जिन विलेजिज को अभी तक ऐप्रोच रोडज नहीं मिंत्री है फेंगको अब प्रायरिटी दी जायेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, पहले, ए और बी कैटेगरी की जो रोडज हैं उनको प्रायरिटी दी जाएगी ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, स्टेट में कुछ सड़कें ऐसी हैं, जो बीच में थोडी बची हुई हैं और उनके न बनने से एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए लौंगैस्ट रूट तय करना पडता है । मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट हिसार में एक सीसवाल डोबी सड़क है । अगर आदमपुर से हमें बालसमन जाना हो, तो हिसार होकर हमें 40 मील दूर जाना पड़ता है लेकिन अगर यह सीसवाल से डोबी वाली पांच मील की सड़क बन जाए, तो केवल पन्द्रह मील का सफर तय करना पड़ेगा? इसलिए क्या मन्त्री जी बताएंगे कि इस तरह की सड़कों को पहले बनाया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : पहले सरकार यह चाहेगी कि सारे गांवों को किसी प्रकार कनैक्ट कर दिया जाए यह जो डिस्टैंसिज को कवर करने वाली बात है, इसके बारे में अर्ज यह है कि जहां बहुत ही दिक्कत है उसके बारे विचार कर लिया जाएगा ।

श्री मूल चन्द मंगला : क्या मन्त्री जी बताएंगे कि बिचुमन की सड्कों की बजाये सीमेंटिड सड़कें बनाई जाएंगी, क्योंकि ये ज्यादा मजबूत रहेंगी? इन पर स्पीकर साहब लागत तो दुगुनी आती हे, लेकिन युटिलिटी चार गुनी होती है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मंगला साहब ने एक दफा पहले भी प्राइवेट तौर पर यह बात कही थी । मैंने अपने चीफ इंजीनियर साहब से पूछा था लेकिन उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हरियाणा में सड़के बनाई जा रही हैं, वे सही हैं।

श्री दीप चन्द भाटिया : स्पीकर साहब, फरीदाबाद से डबु आ बहुत पुरानी सडक बनी हुई है, लेकिन उस पर केवल रोडी ही बिछी हुई है । वह सडक कम से कम पांच साल से वैसी ही पड़ी हुई है । इसलिए मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वह कब तक कम्पलीट हो जाएगी?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने अभी कहा कि 'ए' एंड 'बी' कैटेगरी को प्रायरिटी दी जाएगी । लेकिन मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि हमारे प्रान्त में कुछ जगह जहां लोगों ने श्रमदान करके मिट्टी डाली है, सड़क के लिए अपनी. जमीन भी दी है, जैसे हमारे एरिया में संजय गांधी रोड है, क्या ऐसी सड़कों को भी प्राथमिकता दी जाएगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : अगर वाकई ही लोगों ने श्रमदान से मिट्टी डाली है, तो उसको प्रायरिटी दी जाएगी । परन्तु उन दिनों लोग मिट्टी नहीं डालते थे, कोईऔर ही डालते थे ।

श्री लछमन सिंह : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने कहा कि जब तक 'ए' एंड 'बी' कैटेगरी की सड़के पूरी नहीं हो जाएंगी, उस वक्त तक आगे कदम नहीं उठाया जाएगा । (विघन) क्या मन्त्री जी इसमें रिलैक्सेशन के बारे में विचार करेंगे ताकि जो देहात ए एंड बी कैटेगरी में नहीं आते, उनमें भी सड़कें बन सके?

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, सारी बात पैसे पर निर्भर है । मैं तो चाहता हूं कि एक साल में ही सब गांव सड़कों सें मिल जाए, लेकिन जहां वहुत ही मुश्किल है, उस गांव के लिए रिलैक्सेशन के बारे में गौर किया जा सकता है ।

चौधरी देस राज : क्या मन्त्री जी बताएगे कि क्या इन्टर डिस्ट्रिक्ट सड्कों को प्रायरिटी दी जाऐगी जैसे इन्टर स्टेट रौडज को दी गई है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इस तरह की कोई खात सरकार के अन्दर कन्सीडेरशन नही है ।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब मन्त्री महोदय ने अभी फरमाया कि जिन सडको पर लोगो ने वाकई ही श्रमदान किया है उनका, तरजीह दी जाएगी । मैं मन्त्री महोदय हुए पूछना चाहता हूं कि जिस सड़क का मैंने जिक्र उसके बारे क्या उसके

बारे में वे तसल्ली करके उस पर जल्दी काम कराने की कोशिश करेगे, क्योंकि अब तो वह बारिश पड़ने के कारण खराब हो गई है, उसमें गड्ढे पड़ गए हैं और उसे पेर आमदो–रफ्त खत्म सी हो गई है?

वीरेन्द्र सिंह : उसके बारे में तसल्ली कर ली जाएगी और अगर उस पर वाकई ही वलटीयर लेबर से काम शुरू 'हुआ होगा तो उस सडक को जल्दी शुरू किया जाएगा ।

श्री फतेह चन्द विज : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो कैटेगरी के मुताल्लिक फरमाया है, क्या ये कैटेगरी पिछली सरकार ने बनाई थी या इस सरकार ने बनाई है? अगर पिछली सरकार ने बनाई थी तो क्या इनको बदलने की कृपी की जाएगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : ये कैटेगरीज ठीक डैश से ही बनाई गई थीं । तीन कैटेगरीज बनाई गई थी, ए बी और सी । इसलिए इनको रिव्यू करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती ।

राव राम नारायण : स्पीकर साहब, पिछली सरकार के वक्त में कुछ सडकें कागजों पर तो कम्प्लीट हो गई थीं, लेकिन गौके पर कोई सडक नही बनी थी । इसलिए मै मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनके बारे में कोई इनक्वायरी हुई है और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई?

श्री वीरेन्द्र सिंह : यदि माननीय सदस्य इस क्रिस्म की कोई बात नोटिस में लाएंगे, तो उस पर जरूर ऐक्शन लिया जाएगा ।

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि हर गांव को सड़क से कबैक्ट किया जाएगा । क्या मन्त्री जी बताएंगे कि हर गांव को वर्ष 1978–7 9 में सड़क मिल जाएगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : . इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मन्त्री' जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो गांव दरड और नाले के बीच में हैं, जैसे मेरा इलाका है, उनको भी सड़क की कोई सहूलियत मिलेगी? इसके साथ–साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने सड़कों के नाम से जो लूट मार की थी उसकी इनक्वायरी के जिए कोई कमीशन बैठेगा? – (विध्न) –

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैंने पहले भी अर्ज किया था किं जिन गांवो को रोडज से क्नैक्ट नहीं किया गया है, उनको सरकार ने रोडज से कनैक्ट करना है । जहां तक पिछली सरकार के वक्त में सड्कों के बनाने में हुई हेराफेरी का सम्बन्ध है, उसके बारे में कोई क्मीशन बैठाने का अभी तक कोई मसला सरकार केजेरे गौर नहीं है ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने रोडज की जो डिटेल बताई है, उससे ऐसा लगता है कि झज्जर–जहाजगढ–छुछकवास और बेरी– रोड गलती से इसमें से रह गयी है, हालांकि वह सबसे ज्यादा डैमेज्ड है । क्या मन्त्री जी उसे बनवाने की कृपा करेंगे ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी गंगा राम : अध्यक्ष महोदय, अभी पीछे जो श्रमदान हुआ उस दौरान मैंने कटवाल गांव, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत में एक किलोमीटर लम्बी,–34 फुट चौडी 5 फुट 0ची, जिसमें 6 हजार क्यूबिक फुट मिट्टी डली, सड़क बनवाई क्या मन्त्री जी बताएंगे कि उसको कितने दिन में पक्की करदेंने?

श्री वीरेन्द्र सिंह : आप नाम दीजिए फौरी तौर पर काम शुरू किया जाएगा ।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, अभी मन्त्री जी ने बताया कि ए और बी 'कैटेगरी की सड़कें हैं । क्या वे बताएंगे कि कितनी सड़के 'ए' कैटेगरी– में आती हैं और कितनी सड़कें 'बी' कैटेगरी मे आती हैं

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं नाम पढु?

श्री अध्यक्ष : कोई जरूरत नही ।

चौधरी शिव राम वर्मा : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने जो सड़कों के नाम लिए हैं, इनमें नम्बर तीन सड़क का नाम ललायानीटू तरावडी है । तरावडी मन्त्री है और ललायानी तक यह सड़क बनी हुई है । अगर यह सड़क बन जाए तो मन्त्री से दस पन्द्रह गांव मिल सकते हैं ।.यह मांग बहु त दिनों से है । सड़क मंजूर भी हो चुकी है । इसलिए क्या मन्त्री जी इसे प्रायरिटी बेस पर बनवाने की कृपा करेंगे ताकि लोगों को फायदा हो सके?

श्री वीरेन्द्र सिंह : झझेडी से ललयानी तक सड़क कम्पलीट हो चुकी है । तरावडी तक बनाने के लिए एम0एल0ए0 साहब ने कहा है । उस पर रास्ते में एक नाला पड़ता है, जिस नाले के पर एक पुल बनाना पड़ेगा । जब पुल के लिए सरकार के पास पैसा आ जाएगा तो वह सड़क बना दी जाएगी ।

चौधरी शिवराम वर्मा : ये सारे गांव तरावडी मंडी तक नही पहुंच सकते । पुल के कारण ही तो सड़क रुकी पड़ी है ।

चौधरी देस राज : जो सड़के मार्कीट कमेटी ने बनाई थी, उन सड्कों के फन्ड की कमी के कारण रिपेयर नहीं हो सकी, क्या सरकार उन सड़कों को अपने अन्डर लेने का विचार कर रही हे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : . जो सड़के मार्कीट कमेटी की डिपोजिट वर्क्स से नही बनी है, उन–फो लेने का कोई विचार नहीं है ।

Electricity Breakdown

***302. Shri Devender Sharma :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether it is in the knowledge of Government that there are many breakdowns in supply of electricity in Rural and Industrial Sectors of the State; if so, the steps being taken to ensure regular supply of Electricity ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) :

The Board is aware of the interruptions/break downs in the supply of electricity, which are mainly due to cutting of Feeders by. Bhakra Beas Management Board in the event of over-drawal of energy by Haryana on account of less availability of Power on certain occasions such as less generation from our own resources; hutting off Debar Unit for Inspection, less injection from Indira Prastha Station etc. We are, however, trying to get maximum generation from our own resources, as far as possible.

There may be certain break-downs due to fault on the system. These break-downs are attended to promptly by the staff.

Delhi Electricity Supply Undertaking is pursuaded vigorously by the Government for giving full share of power to Haryana from Indira Prastha Station daily in order to ensure regular supply of electrictity. Besides, preventive maintenance is being resorted to, to minimise the number of break-downs.

श्री देवेन्द्र शर्मा : क्या वजीर साहब बताएंगे कि जितनी बिजली उत्पादन की कोशिश की जा रही है, क्या उससे सरकार

सैटीसफाईड है, हम लोगों सो जो वायदा करके आए थे, क्या वे पूरे कर रहे हैं? मैं बी0 एम0 की डिटेल में न जाते हुए मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि जनता संतुष्ट नहीं है, उसका आप क्या इलाज कर रहे हें?

(कोई उत्तर नही दिया गया)

श्री जयनारायण वर्मा : क्या वजीर साहब के नोटिस में यह बात – है कि बिजली बोर्ड के अन्दर ऐ सी स्थिति है कि लोग कनैक्शन लेने के लिए जाते हैं, तो उनके पास मीटर नहीं होते, तार कम हो जाती है । लोगों को बाजार से तार लानी पड़ ती है, अगर वाकई ऐंसी स्थिति है तो क्या बोर्ड इन चीजों का जल्दी से प्रबन्ध करने जा रहा है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : मीटर्ज की तो अवश्य कमी है । मुख्य मन्त्री महोदय ने एलान कर दिया है कि किसानों को फलैट रेट पर बिजली दी जाए गी! वह सिस्टम जल्दी चालू किया जा रहा है, मीटर्ज की कोई कभी नहीं रहे गी । जहां तक ता रों का सवाल है! मेरे नोटिस में कोई शिकायत नहीं है । तारों की कोई दिक्कत नहीं है ।

चौधरी रिजक राम : मिनिस्टर साहब ने इन्ट्रप्शन और ब्रैक–डाउन के का रण बता एं हैं, क्या उनमें यह भी कारण है कि वारिंग और दूसरा मैटीरियल सबक्टैण्डर्ड लगा है जिस की वजह

से ब्रेक डाउन होते हैं, क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उसके लिए भी सरकार कोई प्रबन्ध करने जा रही है?

श्री बीरेन्द्र सिंह : जो माननीय सदस्य ने कहा है कि पहले तारे सब सटेण्डर्ड की लगी हुई हैं, यी ठीक बात है । बेक–डाउन होने का यह भी एक कारण है । हम कोशिश कर रहे हैं कि उस सारे ट्रांसमीशन सिस्टम को फेज्ड प्रोग्राम में चेंज किया जाये ।

चौधरी हुक्म सिंह : मन्त्री महोदय बताएंगे कि जब बिजली चली जाती है या वोल्टेज कम होती है तो उसकी किसानों के पास कोई पहले से इत्तला नहीं होती है, क्या सरकार इस किस्म का भी कोई प्रोग्राम बनाएगी कि किसानों को बिजली जाने और वोल्टेज कम होने की पहले ही इत्तला दे दी जाये?

श्री वीरेन्द्र सिंह : सीजन के दिनों में तो किसान या इंडस्ट्रियलिस्ट को इंश्योर करते हैं, कि उपको इत्तला देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो इंट्रप्शन हो जाती है, या वोल्टेज लो हो जार्ती है, उसकी इत्तला पहले देना बस की बात नहीं होती ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : हाउस में यह तो मान लिया कि तार खराब लगी हुई 'है, या सब स्टैण्डर्ड की हैं, लेकिन जो मीटर और ट्रांसफार्मर रोजाना जलते हैं, उनका खर्चा भी गरीब किसान से वसूल किया जाता है । क्या सरकार उस खर्चे को बरदाश्त करेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जहां तक ट्रांसफार्मर का खर्चा है, वह अब किसान पर नहीं पड़ता है । मीटर डैमेज हो जाता है, तो उसका खर्चा, अगर हमारी गलती होतीं है तो हम बरदाश्त करते हैए, और किसान की गलती होती है, तो किसान को बरदाश्त करना पड़ेगा ।

स्वामी अग्नि देश : क्या आदरणीय मन्त्री महोदय बताएंगे कि जो बिजली हरियाणा के किसानों को दी जा रही है, उसमें और इंडस्ट्रियलिस्ट को जो विजली दी जा रही है, रेट्स में इतना अन्तर क्यों है? बड़े–बड़े कारखानों को बिजली पांच और सात पैसे यूनिट के हिसाब से दी जा रही हे लेकिन किसानों को 22 और 28 पैसे यूनिट के हिसाब दी जा रही है । यह भेद भाव क्यों हए? क्या इस भेद भाव को समाप्त करने के विषय में सरकार कुछ प्रयास कर रही है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : अब सरकार ने फ्लैट रेट्स अनाउंस किए है । अब नए सिरे से रेट्म अलाउंम किए जाएंगे' । इस बारे में काफी ध्यान रखते हुए रेट्स फिक्स किए जाएंगे ।

चौधरी खुरशीद अहमद : जैसा कि अभी कहा हैं कि बिजली बोर्ड की वोल्टेज कम होने की वजह से किसानों के मीटर कुक जाते हैं लेकिन जो मीटर बिजली बोर्ड ने टैस्ट करके खुद फिट किए हैं, वे भी फुंक जाते–है, तो क्या यह बात उनके नोटिस में है कि मीटर के जल जाने पर 295 रुपए फी मीटर के हिसाब

से किसान को पैसे जमा कराने पड़ते हैं, मेरी कांस्टीच्यूएंसी के एक ताउडू गांवमें 8–9 फरवरी को तीस के करीब मीटर जल गए, तो क्या सरकार उनको खुद बनवाएगी ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : वोल्टेज की कमी के कारण कोई नुक्सान हुआ है, तो मैंम्बर साहब मेरे नोटिस में पहले भी ला सकते थे । ताउडू उनकी कस्टिच्यूएंसी है, उनको यह बात असैम्बली में अब लाने की क्या आवश्यकता थी, वे पहेले भी नोटिस में ला सकते 'थे । आज एक महीना गुजर चुका है । मेरे ' से पहले भी नोटिस में ला संकते थे, हम इनक्वायरी करी सकते थे ।

मास्टर शिव प्रशाद : क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगें कि अम्बाला शहर में एक दिन के अन्दर 10–10 और 15–15 बार बिजली चली जाती है, उसके बारे में कोई उपाय करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : अब तो 24 घंटे बिजली मिल रही है ।

श्री फतेह चन्द विज : मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि जब बिजली में कट लगाते हो तो किसी एरिया में ज्यादा कट लगाते हैं और किसी एरिया में कम लगाते हैं, ऐसा क्यों किया जाता हे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : ऐसी कोई बात नहीं है । इंडस्ट्री की बिजली में कट 40 परसैन्ट लगाई गई थी, वह थ्रू आउट हरियाणा लगाई थी ।

श्री कंवल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगें कि जो मीटर बिजली बोर्ड को लैबारेटरी में 'टैस्ट करके लगाए जाते हैं, अगर वे जल जाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कन्ज्यूमर पर क्यों डाली जाती है? बिजली बोर्ड अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं महसूस करता?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इस बारे में पहले नोटिस दिए बगैर कुछ नहीं कहा जा सकता ।

Mr. Speaker : Question hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Area Irrigated Through Canals

***338. Chaudhri Des Raj :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the cropwise total area irrigated by the canals running under Lift Irrigation Scheme during 1974-75, 1975-76, 1976-77 and total cropwise production under these years ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) : A statement containing the above information is laid on the Table of the House.

Statement

The cropwise total area irrigated and total cropwise production by canals running under Lift Irrigation Schemes, is as under :—

Year	Name of Crops	Total area irrigated in hectares	Total production in Tonnes
1974-75	Kharif-1974	7029	1123
	Rabi 1974-75	15499	7454
1975-76	Kharif 1975	7107	4356
	Rabi 1975-76	21153	17674
1976-77	Kharif 1976	5177	2941
	Rabi 1976-77	21610	16505

The details of total cropwise area irrigated and total cropwise production are indicated in the Annexure 'A'.

ANNEXURE 'A'

Statement showing the details of cropwise total area Irrigated and total cropwise production by the canals running under Lift Irrigation Schemes

Name of crops	1974-75		1975-76		1976-77	
	Area Irrigated in hectares	Production in Tonnes	Area irrigated in hectares	Production in Tonnes	Area Irrigated in hectares	Production in Tonnes
Sugarcane	2	6	-	24	49	236
Rice	19	27	-	—	19	47
Cotton	74	24	209	67	594	198
Bajra	5146	299	4633	2720	2843	1535
Maize	—	—	1	1	1	1
Misc. Kharif crops	1788	767	2258	1544	1671	924
Total Kharif	7029	1123	7107	4356	5177	294i

Wheat	601	918	2851	5907	3442	6361
Barley	519	408	780	941	463	457
Gram	9 51	3156	8420	6256	12021	5914
Oil Seed	4603	2918	8891	4472	5451	3669
Misc. Rabi Crops	126	54	211	98	233	144
Total Rabi	15499	7454	21153	17674	21610	16505
Grand Total :	22528	8577	28260	22030	36787	19446

Audit Reports of the Cooperative Sugar Mills.

***375 Rao Dail Singh:** Will the. Minister for. Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether the Co-operative Sugar Mills in the State have been audited during the period from 1971 to date;

(b) if the reply, is in the affirmative the audit-reports be placed on the table of the House

(c) whether any Cooperative- Sugar Mills in the State have been ordered to be specially audited for the period from 1975 to-date; and

(d) if the reply is in affirmative the Special Audit Reports be placed on the table- of the House ?

Work Charged Employees in the Irrigation Department

***384 Shri Ran Singh Maan :** Will the Minister for Irrigation and Power: be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to regularise the services of work-charged employees at present working in. Irrigation Department; and

(b) if so, the steps being contemplated in this regard ?

सिंचाई तथा विजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(ए) सभी सहकारी चीनी मिलों का 30—6—76 तक का आडिट पूर्ण हो चुका है ।

(बी) आडिट रिपोर्ट एक पब्लिक डाकूमैंट है, इसकी प्रतियां संस्था, महालेखाकार व वित्तीय संस्था को भेजी जाती हैं । यह आडिट रिपोर्टे काफी बड़ी हैं 200 से 300 पृष्ठ तक. । समय तथा मेहनत, जो इन रिपोर्टो को टाईप करने में लगेगी उससे कोई विशेष लाभ नही होगा ।

(सी) जी, हां ।

(डी) सिवाए एक्सपैन्सम प्रोग्राम के जिसका आडिट अभी चल रहा है, अन्तरिम रिपोर्ट जारी कर दीं गई है, जो सरकार द्वारा अध्ययन की जा रही है । समय. तथा मेहनत जो इन रिपोर्टो को टाईप करवाने में लगेगी, उससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा ।

Work Charged Employees in the Irrigation Department

***384 Shri Ran Singh Maan :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to regularise the services of work-charged ern. ployees at present working in Irrigation Department; and

(b) if so, the steps being contemplated in this regard ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क) जी, हां ।''

(ख) सरकार ने ऐसे 1208 वर्क चार्ज कर्मचारियो को जिनकी 1– 4– 1972 को सेवा 5 वर्ष से अधिक हो गई थी, पहले ही रैगुलर कर दिया है । अब ऐसे अन्य वर्कचार्ज कर्मचारियों को, जिनकी 31– 12– 1977 को सेवा 5 वर्ष से अधिक हो गई है, नियमित करने के लिए आवश्यक विवरण क्षेत्र से इकठ्ठा किया जा रहा है और इस विवरण के प्राप्त होने पर इस बारे 'में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

Construction of Roads

***460. Dr. Brij Mohan Gupta :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the names and mileage of road proposed to be constructed in each constituency of the State during the period from cm 1-2-1978 to 31-3-1978 and from 1-4-1978 to 31.3-1979, separately ?

***Interim Reply**

अ0 स0 क्र 0 58 (ए 0 क्य0) लो 0 नि0 4(3)

वीरेन्द्र सिंह मन्त्री

सिंचाई एंव विद्युत विभाग,
हरियाणा,

चण्डीगढ ।

7 मार्च, 1978

विषय : तारांकित प्रश्न नं. 460 जो श्री बृज मोहन गुप्ता एम0 एल0 ए0 ने पूछा है ।

प्रिय

विधान सभा की कार्यसूचि दिनांक 8–3– 78 में तारांकित प्रश्न नं 0 460 जो श्री बृज मोहन गुप्ता, विधान सभा सदस्य ने पूछा है । उत्तर के लिए शामिल किया हुआ है । उसके बारे में मैंने यह कहना है कि उसका उत्तर अभी तैयार नहीं है । सदस्य महोदय द्वारा मांगी गई सूचना अधीनस्थ कार्यालयों से मांगी हुई है और एकत्रित की जा रही है । सूचना एकत्रित करने में कुछ समय लग जाएगा । अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि तारांकित प्रश्न नं. 460 के उत्तर के लिए 8– 3– 78 की बजाए लगभग 7 दिन बाद की कोई अन्य तिथि निश्चित कर दी जाए ।

भवदीय

हस्ता –

ब्रिग्रे0 रण सिंह (वीरेन्द्र सिंह)

अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ ।

Market Committees in the State

***368. Shri Moot Chand Jain :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total number of Market Committees in Haryana together with the names thereof;

(b) the number of the Market Committees out of those referred to in para (a) above, whose terms have expired;

(c) whether the members of the said Committees are nominated ; If so, whether there is any proposal under consideration of the Govt. to get the members of these committees elected ; and

(d) The number of Market Committees whose Chairman are Govt. Employees ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) :

(a) 86. The statement is placed on the table of the house.

(b) 82.

(c) Yes. These are nominated committees. A bill to amend the existing Act so as to have elected Market Committees in place of nominated ones, is being introduced in the current session of the Haryana Vidhan Sabha.

(d) In 82 Market Committees, Government employees have been appointed to carry out their functions as Administrators.

Statement

S.No.	Name of Market Committee
	Ambala District
1.	Ambala City
2.	Ambala Cantt.
3.	Jagadhri
4.	Kalka
5.	Naraingarh
6.	Sadhaura
7.	Barara
8.	Mullana
9.	Yamunanagar
10.	Raipur Rani
11.	Chhachhrauli
12.	Naneola
	Bhiwani District
13.	Bhiwani

14. Charkhi-Dadri

15. Loharu

16. Siwani

17. Tosham

18. Behal

19. Jui

Gurgaon District

20. Gurgaon

21. Ballabgarh

22. Faridabad

23. Ferozepur

24. Hode

25. Nuh

26. Palwal

27. Pataudi

28. Punhana

29. Sohna

30. Tauru

Jind District

31. Jind

32 Narwana

33. Safidon

34. Kalayat

35. Uchana

36. Pillukhera

37. Julana

Karnal District

38, Karnal

39. Gharaunda

40. Panipat

41. Samalkha

42. Madlauda

43. Indri

44. Tarori Nissing

Kuruhshetra, District

46. Thanear

47. Kaithal

48. Shahabad

49. Ladwa

50. Cheeka

51. Pundri-Fatehpur

52. Radaur

53. Pehowa

54. Ismailabad

55. Dhand

56. Pipli

Mohendergarh District

57. Mohendergarh

58. Narnaul

59. Rewari

60. Ateli

61. Kanina

Hissar District

62. Hissar

63. Fatehabad

64. Hansi

65. Ratia

66. Bhuna

67. Adarnpur

68. Bhattukalan

69. Tohana

70. Jakhal

71. Barwala

72. Uklana

Rohtak District

73. Rohtak

74. Bahadurgarh

75. Jhajjar

76. Sampla

77. Meham

78. Kosli

Sonepat District

79. Sonepat

80. Gohana

81. Ganaur

Sirsa District

82. Sirsa

83. Dabwah

84. Kalanwali

85. Ding

86. Bllenabad

Safeguarding the Interests of Sugarcane Growers

***447. Master Shiv Parshad :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state -

(a) the policy formed by the Government to safeguard the interests of Sugaicarie grokwers in the State ;

(b) whether it is in `the knowledge of the Goverment that owners of the Sarswati Sugar Mills are harassing the farmers extent in procurement of the 'sugarcane and - determining the price thereof ; if so, the Steps taken 'by the Government in this respect ; and

(c) whether there is any proposal under -- consideration the Government to set up another. Sugar Mill, in ,the Government or Cooperative Sector in Ambala Tehsil; if so, the time-by which it is likely to be set up ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क) गन्ना उत्पादको के हितों को ध्यान में रखते हुंए भारत सरकार ने गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया हुआ । है जो कि मिलो द्वारा दिया जाता है । राज्य सरकार ने भी खण्ड सारी यूनिटों द्वारा अदा किए जानें वाले गन्नै का मूल्य निश्चित किया हुआ है। शूगर मिलें, गन्ना अधिक मात्रा में पेलेंगी

यहां तक, कि सीजन की समाप्ति पर भी वे देर से गन्ना पेलती रहेंगी ।

(ख) सरकार को स्थिति का पता है । सरस्वती शूगर मिल्ज यमुनानगर के प्रबन्धकों ने गन्ने की नोटिफाईड' कीमत जो 13.50 रुपए है को घटाकर 9.30 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जो कि भारत सरकार– द्वारा निर्धारित किया गया न्यूनतम मूल्य है और इस प्रकार किसानों को परेशान किया जा रहा है । इस मिल्ज के प्रबन्धकों से उक्त कीमत दिये जाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं । –

(ग) यह विषय विचाराधीन है, किन्तु मिल लगाने के बारे में समय निश्चित करना सम्भव नहीं है ।

Stadium at Bhiwani

***434. Shri Hira Nand Arya :** Will the Minister for Education be pleased to state the amount sanctioned for the Stadium at Bhiwani togetherwith the amount spent thereon so far ?

शिक्षा मन्त्री (कर्नल राव राम सिंह) : उपायुक्त भिवानी को स्टेडियम निर्माण हेतु कुल रुपये 23,42,000/– की राशि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त हुई, जिसमें दो लाख रु0 की राशि जो कि इस विभाग द्वारा अनुदान के रूप में दी गई थी, भी शामिल है । अब तक इस में से 8, 45, 381 की राशि व्यय की जा चुकी हैं ।

Share of Sirsa District

***423. Chaudhri Jagdish Kumar Baniwal :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the share of Sirsa District out of 6500 ousecs of water which is likely to be received by the State through Sutlej Yamuna Link togetherwith the arrangements made to supply the same to Sirsa District ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : सतलुज यमुना लिंक के माध्यम से राज्य को उपलब्ध कराये जाने वाले रावी–व्यास के फालतू जल के वितरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

Recommendations of the Persons for I.P.S.

***425. Shri Balwant Rai Tayal :** Will the Minister for Industries be pleased to state —

(a) the names of the persons who were recommended for the IPS to the Central Government after the formation of new Government and list of the same be placed on the table of the House ;

(b) the criteria adopted while making the said recommendations, and

(c) whether the name of any such officer has also been included, who remained in the lunatic asylum ?

उद्योग मन्त्री (.डा 0 मंगल सैन) :

(क) 1 श्री राज सिंह

2 श्री सतदेव सिंह

(ख) आई पी. एस. (रिक्रूटमैन्ट) रूलज, 1954 के रूल 9 (1) एवं आई. पी. एस (अप्वायटमैंट बाई प्रोमोशन)रेगुलेशनज 1955 के रैगुलेशन 9 (1) के अनुसार दो रिक्त स्थानों के विरुद्ध, आई. पी. एस. के पद पर नियुक्ति के लिए उपरोक्त दोनों अधिकारियों के नामों की सिफारिश केन्द्रीय सरकार को भेजी गई थी ।

(ग) नहीं ।

Expenditure incurred on Medicines

***454. Shri Fateh Chand Vij :** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) the average expenditure incurred in the shape of medicines on each out door and in-door patient during the years 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76 and 1976-77, separately in the Government Hospitals of the State ; and

(b) whether the Government has received complaints that this expenditure is much less and the patients get few medicines; if so, the action taken thereon?

Health Minister (Smt. Dr. Kamla Verma) :

(a) The record of consumption of medicines in Government Medical Institutions in Haryana is maintained for

all patients together and no separate accounts are kept for indoor and outdoor patients. The statistics of patients are kept according to Calender year and the expenditure on medicine is maintained according to financial year. A statement showing expenditure incurred on per patient during the years 1972 to 1976 is placed on the table of the house.

(b) It is correct- that all the medicines prescribed by the doctors to patients are not made available to them from Government stocks. It is not possible to provide all the medicines at Government expense due to financial implications. However, Government has been trying to increase expenditure on medicines. The expenditure on medicine which was Re. 0.21 during the year 1967-68 had risen to Rs. 1.05 in 1976-77.

STATEMENT

STATEMENT SHOWING EXPENDITURE OF MEDICINE ON EACH PATIENT

(Both in-door and out-door combined) treated in all Govnrment Medical Institutions of Haryana during 1972, 1973, 1974, 1975 and 1976.

Year	Total purchase and expenditure incurred on Medicines during	Patients			Expenditure incurred on each
		Indoor	Out-doot	Total	

	theyear				
1972	8096370	138302	-5999715	6138017	1,32 1,27
1973	8531400	151263	6581177	6732440	1,29 1,28
1974	9805930				1,25
1975	10850700	169901	7406582	7576483	
1976	@11700000	177878	8337797	8515675	
		197721	9181595	9379316	

@ Expenditure on meficines incurred by Medical College Hospital, Rohtak is not included but patients of Medical College Hospital, Rohtak are included, in the total patients.

Pay Scales of H.C.S. (Executive)

***212. Shri Shamsher Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the pay scales, cadre strength and selection grade of H.C.S,. (Executive) and H.C.S. (Judical) were the same in the past ;

(b) whether it is a fact that the service Condition's of the H.C.S. (Executive) have recently been improved *He the conditions of Judical Branch remained as before; and

(c) if so, whether any representations.. have .been received from Bar Associations of Haryana in regard to discriminatory service conditions of H,C.S. (Executive) and H.C.S. (Judicial), if so, the action taken thereon ?

मुख्य मन्त्री (श्री देवी लाल) :

(क) दिनांक 31– 12– 76 तक एच0 सी 0 एस 0 (कार्यकारी शाखा) तथा एच 0 सी0 एस0 (न्यायिक शाखा) के वेतनमान समान थे । दिनांक 1– 1–77 से एच 0 सी 0 एस0 (कार्यकारी शाखा) के वेतनमान बढ़ाए गए हैं । इन दनों सेवाओं की कार्डर संख्या समान नही रही है । दिनांक 16– 11– 75 तक

इन दोनों सेवाओं के सिलैक्शन ग्रेड पदों की प्रतिशतता 15 प्रतिशत थी । दिनांक 17– 11–75 से एच 0 सी0 एस0 (कार्यकारी शाखा) के सिलैक्शन ग्रेड पदों की प्रतिशतता 15 परतिशत से, बढाकर 20 प्रतिशत कर दी गई थी. ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां, सदन को दिनांक 2– 3– 1978 की आश्वासन दिलाया जा चुका है कि एच 0 सी 0 एस0 (न्यायिक शाखा) के' वेतनमानों को शीघ्र ही एच0 सी0 एस0 (कार्य का रई शाखा) के वेतनमाने के समान बना दिया जाएगा ।

अतारॉंकित प्रश्न एवं उत्तर

94. Swami Aditya Vesh : Will the Chief Minister be pleased to state--

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new capital of

Haryana if so, the name of the place together with the time by which it will be constructed; and

(b) if not, the amount being paid as, rent on the Secretariat building to the Union Government ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल) :

(क) जी नही ।

(ख) कोई नही ।

Development of Sanskrit Language

95. Swami Aditya Vesh : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the steps so for taken for the development of Sanskrit Language in the State; and

(b) whether the Government considers to provide the same facilities to this language which are being given for the development of language of other minorities ?

शिक्षा मन्त्री (कर्नल राव राम सिंह) :

(क) एक विवरणिका अनुबन्ध के रूप में सरन है । (ख) हा ।

विवरणिका

सस्कृत के विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमें राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सपन्न की जाती है ।

1. सस्कृत साहिप्यकार का सम्मान ।

2. संस्कृत की सर्वोत्तम पुस्तकों पर पुरस्कार ।

3 राज्य स्तरीय संस्कृत भाषण प्रतियोगिता ।

4. राज्य स्तरीय संस्कृत श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता ।

5. संस्कृत लेखक निधि

6. संस्कृत की साहित्यिक सं स्थाओं को सहायतानुदान ।

7 संस्कृत दिवस का आयोजन ।

8. सर्वोत्तम संस्कृत निबन्धों पर पुरस्कार ।

9. गीता पुरस्कार ।

10 संस्कृत रंगमंच का विकास ।

11. लेखक गोष्ठी ।

12. जिला स्तरीय भाषण तथा श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता ।

13. संस्कृत पुस्तक प्रकाशनार्थ सहायतानुदान ।

14 फुटकर व्यय तथा गीता पुरस्कार पर पारिश्रमिक ।

Government Advertisements for Newspapers

96. Swami Aditya Vesh: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of daily, weekly, fortnightly or monthly papers to whom the Government advertisements are being given by the State Government;

(b) the names and places of publications of the papers referred to in part (a) above ?

Chief Minister (Chaudhri Devi Lal)

(a&b) A Statement containing this information is placed on the table of the House.

STATEMENT

List of papers given Govt. advertisements between the 1st July and the 30th January, 1978.

S.No.	Name of paper	Place of publication
English Dailies-		
1.	Tribune	Chandigarh
2.	Indian Express	Chandigarh/ New Delhi
3.	Times of India	New Delhi
4.	Hindustan Times	New Delhi
5.	National Herald	New Delhi
6.	Patriot	New Delhi

7.	Statesman	New Delhi
8.	Economic Times	Delhi/Bombay
9.	Free Press Journa l	Bombay .
10.	Amrit Bazar Patrika	Calcutta
11.	Hindu	Madras
12.	Ananda Bazar Patrika	Calcutta
13.	Financial Express	Delhi/Calcutta
14.	Assam Tribune	Gauhati
15.	Decan Herald	Banglore
16.	Pioneer	Lucknow

Hindi Dailies-

1.	Navbharat Times	New Delhi
2.	Hindustan	New Delhi
3.	Janyug	New Delhi
4.	Vir Arjun	New Delhi
5.	Punjab Kesari	Jullunder
6.	Vir Partap	Jullundur
7.	Hindi Milap	Jullundur
8.	Nav Jyoti	Jaipur

9.	Rajasthan Patrika	Jaipur
10.	Jagran	Kanpur
11.	Swantantra Bharat	Lucknow
12.	Vishwamitra	Calcutta
13.	Arya Varta	Patna
14.	Amar Ujala	Agra
15.	Shivalak Sandesh	Chandigarh

Urdu Dailies—

1.	Partap	Delhi
2.	Milap	Delhi
3.	Tej	Delhi
4.	Hind Samachar	Jullundur
5.	Partap	Jullundur
6.	Milap	Jullundur
7.	Qaumi Awaz	Lucknow

Punjabi Dailies-

1.	Ajit	Jullundur
2.	Akali Patrika	Jullundur
3.	Nawan Zamana	Jullundur

4.	Ranjit	Patiala

WEEKLY PAPERS

English Weekly Papers-

1 .	Organiser	New Delhi
2.	Indian Tender Journal	New Delhi
3.	By Word	New Delhi
4.	Thought	New Delhi
5.	Blitz	Bombay
6.	Current	Bombay
7.	Nothern News	Chandigarh
8.	Chandigarh Post	Chandigarh
9.	Moon Light	Ambala
10.	Blast	Chandigarh
11.	Main Stream	New Delhi
12.	Link	New Delhi
13.	Punjab Mail	Chandigarh
14.	Dhrkan	Chandigarh

Hindi Weekly Papers-

1.	Ambala Times	Ambala

2.	Pawan Veg	Ambala
3.	Jyoti Kan	Ambala
4.	Gita Jyoti	Kurukshetra
5.	Haryana Leader	Kaithal
6.	Dehshat	Karnal
7.	Krishi Andolan	Karnal
8.	Haryana Bhoomi	Panipat
9.	Haryana Darpan	Karnal
10.	Janam Bhoomi	Karnal
11.	Nav Jeevan Path	Kurukshetra
12.	Nayaya Path	Hissar
13.	Haryana Sandesh	Hissar
14.	Gyanodya	Hissar
15.	Navn ad	Hissar
16.	Bharat Tek	Hissar
17.	Bhola lnsan	Rohtak
18.	Chakra View	Hissar
19.	Haryana Sangh	Hissar
20.	Dev Bhoomi	Jind

21.	Rastriya Vistar	Jajjar
22.	Haryana Khushal	Rohtak
23.	Purani Yadan	Rohtak
24.	Haryana Til ak	Rohtak
25.	Pursharthi Gazette	Rohtak
26.	Viyaparion Ki Awaz	Rohtak
27 .	Chetna .	Bhiwani
28.	Jagrit Samaj	Bhiwani
29.	Mewat	Gurgaon
30.	Haryana Times	Narnaul .
31.	Amrit	Karnal
32.	Panchajanya	New Delhi
33.	Sewagram	New Delhi
34.	Sakshi	New Delhi
35.	Ekta Sandesh	New Delhi
36.	Ek Nazar	New Delhi
37.	Grameen Duniya	New Delhi
38.	Raj Dharam	Chandigarh
39.	Udhyan	Kaithal

40.	Saptahik Hindustan	New Delhi
41.	Bhartiya Rail	New Delhi
42.	Dharamyug	Bombay
43.	Viyapar Udyog Samachar	New Delhi

Urdu Weekly Papers-

1.	Mera Desh	Ambala
2.	Roshni	Sonepat
3.	Hindu	Jullundur
4.	Tehqiqat	Rohtak
5.	Jat Gazette	Rohtak
6.	Navai Watan	Ambala
7.	Pegam	Sonepat
8.	Tehrik	New Delhi
9.	Awam	New Delhi
10.	Mehnat	Jullundur
11.	Chetawani'	Chandigarh
12.	Jagat	New Delhi

Punjabi Weekly Papers-

1.	Dater Punjab	Patiala

2.	Sarpanch	Patiala
3.	Pauphatti	Patiala
4.	Fateh	New Delhi
5.	Qaumi Ekta	New Delhi
6.	Panth Parkash	New Delhi
7.	Ranjit Nagara	Chandigarh
8.	Mel Milap	Chandigarh
9.	Jagi Munukta	Faridkot
10.	Niddar	Ambala Cantt.

MONTHLY PAPERS

English Monthly Papers-

1.	Yojna	New Delhi
2.	Orion	New Delhi
3.	Akashwani	New Delhi
4.	Turning Point	New Delhi
5.	Clinical Reporter	Fatehabad
6.	Internationist	Chandigarh
7.	News International	Simla
8.	Haryana Review	Chandigarh

9.	Indian Institute of Opinion	New Delhi
10.	Parents and Children	New Delhi
11.	Homeo Journal	Ambala Cantt .
12.	Art of Living	Amritsar

Monthly Papers (Hindi)-

1.	Prayaschit	New Delhi
2.	Kathalok	New Delhi
3.	Sampada	New Delhi
4.	Tamana	Chandigarh
5.	Jansahitya	Chandigarh
6.	Sapt Sindhu	Chandigarh
7.	Sarika	Bombay
8.	Kadambni	New Delhi
9.	Kurukshetra	New Delhi
10.	Yug Paribodb	New Delhi
11.	Gram Jan	New Delhi
12.	Udyan Patrika	Kaithal
13.	Sakti Putra	New Delhi

Urdu Monthly Papers-

1.	Mastana Jogi	New Delhi
2.	Biswani Sadi	New Delhi
3.	Nirala Jogi	Panipat
4.	Maseehi Duniya	New Delhi
5.	Shair	Bombay
6.	Khan Dani Mansuba Sandi	New Delhi
7,	Shama	New Delhi

Miscellaneous Papers-

1.	Sandesh, Gujarati daily	Ahmedabad
2.	Thanti, Tamil daily	Madras
3.	Endu, Telgu daily	Hydrabad
4.	Mathrubhoomj, Kalayam daily	Calicut/Cochin
5.	Malaya Manorma, Malaylam daily	Kottayam
6.	Prajawani, Kammada daily	Bangalore
7.	Phul Chhabi, Gujarati daily	Rajkot'
8.	Andhara Prabha, Talgu daily	Madras
9.	Andhra Patrika, Telgu daily	Madras/Vijayawada
10.	Malai Murasu, Tamil daily	Madras

11.	Roma, English Quarterly	Chandigarh
12.	Carvan, English Fortnightly	New Delhi
13.	Tourism & Travel, English Monthly	New Delhi
14.	India Calling; English Fortnightly	Canada

Auction of Hills of Gurukul Inderparasth

97. Sawami Aditya Vesh : Will the Minister for Industries be pleased to state the years and the amount for which the hills of Gurukul In Inderparasth have been auctioned by the Government and the quantity of Stone which is to be excavated daily according to the auction agreement together with the details of the places of residence and the names of the contractors ?

उद्योग मन्त्री (डाक्टर मंगल सैन) : गुरुकल इन्द्रप्रस्थ, सराय ख्वाजा, प्लाट नं 0 1 जिला गुड़गांव में स्थित है । इस प्लाट की पत्थर की खान 6— 12— 1977 को लगभग 3 वर्षों के लिये नीलामी की गई । इस ठेके की अवधि 3 1— 7— 1980 तक है । इस नीलामी में सबसे 0ंची बोली 1, 40,1 00/— रुपये प्रतिवर्ष की दर से थी ।

ठेकेदार प्रतिदिन कितना पत्थर निकालेगा, ऐसी कोई सीमा ठे के के इकरारनामे में निर्धारित नही की जाती । ठे केदार किसी माता में पत्थर निकाल सकता है ।

ठेकेदार फर्म मैसर्ज ओं 0पी0 भोला, नन्द लाल ऐंड कम्पनी, गांव तथा डाकखाना, सराय ख्वाजा, तहसील बल्लबगढ़, जिला गुड़गांव के हिस्सेदारों के नाम तथा पते निम्नलिखित हैं–

(1) श्री नन्द लाल सुपुत्र श्री हरि चन्द, 85–ए 1 22, डबलयू ईए. करोल बाग, नई दिल्ली ।

(2) श्री कैलाश आहूजा, सुपुत्र श्री मोकल चन्द आहूजा, 6 1! 2 9, रोहतक रोड़, नई दिल्ली ।

(3) श्री दर्शन लाल आहूजा, सुपुत्र श्री तीर्थ राम आहूजा, 40 पार्क एरिया, करोल बाग, नई दिल्ली ।

(4) श्री विजय कु मार चावला सुपुत्र श्री खरैती लाल, 3 7, नाईवाला गली, करोल बाग, नई दिल्ली ।

(5) श्री ओपी. भोला, सुपुत्र श्री. हरि चन्द, 8/9 5, गली–जैन मन्दिर, शहादरा दिल्ली ।

Mutation at Village Chautala

111. Shri Surrender Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state whether it is in the knowledge of the Government that Tehsildar Dabwali sanctioned many mutations at village Chautala on 17th, December, 1977 ?

राजस्व मन्त्री (श्री प्रीत सिंह) : तहसीलदार डबवाली दारा 1 7– 1 2– 1977 को ग्राम चोटाला के कोई इन्तकाल गांव

चोटाला में मन्जूर नहीं किये गए थे । परन्तु उस तिथि को नायब तहसीलदार डबवाली द्वारा 31 इन्तकाल मन्जूर किए गए थे ।

Metalled Roads

112. Shri Surrendar Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state -

(a) the length of metalled roads existed when the State of Haryana came into being together with the length of roads on 31st March, 1977 ;

(b) the year-wise expenditure incurred on roads from Ist April, 1967 to 31st March, 1977 ; and

(c) the length of pucca roads added after the Janata Government took over?

सिचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(ए) (1) 5100 कि0 मी0 1– 11–66 तक

(2) 15520 कि0 मीं 31–3– 77 तक

(बी)

1967– 68	1968– 69	1969– 70	1970– 71
98. 27 लाख	246. 86 लाख	545.03 लाख	1184. 48 लाख
1971 – 72	1972– 73	1973– 74	1974– 75

2214.49 लाख 1217.80 लाख 808.66 लाख 458.03 लाख

1975– 76 1976– 77

510. 43 लाख 607. 82 लाख

उपरोक्त आंकड़ों में वर्ष 1967 – 88 तथा 196 8– 69 के दौरान मार्किट कमेटी डिपोजिट सडक कार्य पर खर्च, जो कि उपलब्ध नही है, शामिल नहीं है । निहित राशि कोई ज्यादा नहीं है । – इस सूचना को एकत्रित करने में उतना लाभ नही होगा जिसक कि समय तथा मेहनत सूचना एकत्रित करने में निहित है ।

(सी) 31– 1 – 78 तक 372 कि0 मी 0

Number of Buses Owned by the State

113. Shri Surrender Singh ; Will the Chief Minister be pleased to State—

(a) the number of buses owned by the State on 1st April, 1968 together with the number of such buses on 1st April, 1977 ; and

(b) the number of buses added after the formation of Janata Government ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल) :

(क) 1 अप्रैल, 1968 567

1 अप्रैल, 1977 2041

(ख) शून्य

और नई बसों की बढ़ोतरी के लिए आर्डर जारी किये जा चुके हैं ।

Supply of Drinking Water

114. Shri Surrender Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the number of villages supplied w th drinking water up to 31st March, 1967, and the number of villages having water supply on 31st March, 1977 together with the total expenditure incurred on these schemes ?'

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : 31—3—67 तक, 182 गावों में पेयजल सुविधा उपलब्ध थी । 1— 4—6 7 से 3 1— 3— 77 तक, 739 अतिरिक्त गावों को (50 धानियो सहित)पेयजल सुविधा 1254.23 लाख रु0 के खर्चे से प्रदान की जा चुकी है । इस तप 31—3—77 को 921 गावों में (50 धानियों सहित) पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी थी और इस पर कुल 1481.20 लाख रुपये खर्च हुआ था ।

Employees belonging to Haryana State in the Punjab and Haryana

Nigh Court.

125. Shri Devender Sharma Will the Minister for Finance be

pleased to state —

(a) the number of employees belonging to the - State of Haryana in the establishment of the High Court ;

(b) the number of such employees on 1st of November, 1966 and on 31st January, 1978 ; and

(c) the total number of employees in the Punjab and Haryana High Court on 1st November, 1966 and on 31st of January, 1978 ?

वित्त मन्त्री (चौधरी सतवीर सिंह मलिक) : पंजाब राज्य के पुनर्गगठन के पश्चात् पंजाब तथा हरियाणा, उच्चन्यायालय का प्रशासकीय नियन्त्रण संघ क्षेत्र चण्डीगढ के अधीन चला गया है । अतः सूचना देना संभव नही है ।

ओला वृष्टि से हूई तबाही पर मुख्य मन्त्री द्वारा वक्तव्य

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल) : स्पीकर साहब, मैं हाउस को तुक इत्तलाह देना चाहता हूं पिछले दिनों एक मार्च और दो मार्च के बीच में जो ओले पड़े थे, उससे जो नुक्सान हुआ है, उसकी इत्तलाह अभी मुझे मिंत्री है । मैं इसे हाउस की इत्तलाह के लिए यहां पर रखना चाह रहा हूं । पिछले दिनों जो ओले पड़े थे, उससे जिलेवार जो नुक्सान हुआ है, वह मै अ) प लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं । नारनौल में 1 40 गांवो में नुक्सान हुआ है । 8 9, 768 एकड़ में ओले पड़े और 13 करोड़ 43 लाख 6 हजार रुपए का नुक्सान हुआ है । गुड़गांव में 53 गांवों में ओले पड़े, बाकी इत्तलाह अभी आई नही है । जीद में 64 गांव में ओले पड़े

40 हजार एकड़ में ओले पड़ने से 3 करोड़ 50 लाख रुपए का नुक्सान हुआ । हिसार में 1 8 गाव में 8 5, 600 एकड़ में ओले पड़ने से नुक्सान हुआ । बाकी इनफर्मेशन अभी आइए नही । करनाल में 34 गांव में ओले पड़े 22000 एकड़ में नुक्सान हुआ और 2 करोड़ 25 लाख रुपए का नुक्सान हुआ । सूचना मिलते ही गिरदावरी कराए जाने के आदेश दे दिए गए थे । 3! 3 को यह आदेश जारी कर दिए गए थे । इसकी इत्तलाह आने के बाद इनकी निम्नलिखित मदद की जाएगी ।

बिजली के बिलों की वसूली मुलतवी कर दी जाएंगी । सरकार द्वारा दी गई तकावी तथा द्वसरे कर्जो की वसूली मुल्तवी कर दी जाएगी । लैण्ड होस्टिंग टैक्स की वसूली के सम्बन्ध मे मुल्तवी माही का फैसला किया जाएगा । बीज, खाद, ट्रैक्टर, और इस किस्म की तकावी तथा सब सिडी आवश्यकतानुसार दी जाएगी । वह फसलें जो थोड़े अर्से में तैयार हो जाती हैं, उनका बीज उपलब्ध करवाया जाएगा । आवश्यकतानुसार जहां पर औलों से नुक्सान' हुआ है, वहां पर रिलीफ वर्क शुरु कर दिया जाएगा । राशन उपलब्ध कराने के व्यवस्था करायी जाएगी । यह फैसला सरकार ने किया है ।

चौधरी शिवराम बर्मा : चारे के बारे मै क्या फैसला किया है?

चौधरी देवी लाल :. गिरदावरी की रिर्पोट' आने के बाद चारा पहुंचीने का भी फैसला किया जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : सैन्ट्रल स्टडी टीम भी वहां पर गई है

चौधरी देवी लाल :. इसके अलावा सैन्ट्रल स्टडी टीम भी इलाके का सर्वे करने के लिए जा रही है ।

नियम समिति का प्रतिवेदन लदंन की मेज पैर रखना

वर्ष 1978–79 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनराम्भ)

Mr. Speaker : I lay on the Table of the House the Report of the Rules Committee containing the recommendations of the Committee regarding amendments in the Rules of procedure and conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, as required under Rule 234 ibid.

The House will now resume discussion on the Budget.

श्री अध्यक्ष : सरदार लछमन सिंह ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : स्पीकर साहब, मेरी स्पीच कन्टीन्यू करनी है ।

श्री अध्यक्ष : आपने काफी टाईम ले लिया है । 25 मिनट आप ने ले लिए है ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : स्पीकर साहब, सिर्फ दो मिनट और लूंगा?

श्री अध्यक्ष : अच्छा, दो मिनट ले लें ।

चौधरी जगजीत सिंह 'पोहलू (पाई) : स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत जनती सरकार से एक तो यह प्रार्थना करना चाहता हूं किं एक साल से इस हरियाणा में एक बटालियन जो सी.आर 0पी0 की बैठी हूई है, उसकी इस जगह अब आवश्यकता नहीं है, सरकार को पता ही है कि इस एक साल में हरियाणा के कितने ही आदमी तैयार हो सेकते थे । हमारे पास बेरोजगारी बहुत ज्यादा है । हमारे लाखों पढे लिखे नौजवान बेकार है । इसलिए मैं यह प्रार्थना करुंगा अपने चीफ मिनिस्टर साहब से कि फौरी तौर पर सी0 आर0 पी0 को वापिस भैजा जाए और हरियाणा की दो चार और बटालियने खड़ी की जाए, क्योकि मैं समझता हूं कि हमारे भाई देश की ज्यादा सेवाकर सकते. हैं । इसके साथ–साथ मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से यह भी प्रार्थना करुंगा कि मै केटेरिएट की बहुत हैवी एडमिनिडेशन है, इसको थोड़ा कम किया जाए इसको थोडा घटाया जाए, ताकि हमारे हरियाणा की बेरोजगारी का मसला हल हो सके । स्पीकर साहब, हमारें चीफ मिनिस्टर साहब बहुत खाँड माईडिड हैं, हर चीज को इन्होंने कदम–कदम पर री–कसीडर किया है, जैसे सेल्ज टैक्स पर जो सरचार्ज 1 5 प्रतिशत बढा दिया था अब उसे 5 प्रतिशत कर दिया गया है । मैं तो यह कहूंगा कि इसे 3 प्रतिशत और घटा

कर पहले वाली दर 2 प्रतिशत कर दो, तो भी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है । लेकिन मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से यह कहूंगा कि जिस गरीब जनता से आपने वोट मांगे थे उससे आपने यह वायदा भी किया था कि 6.50, किल्ले तक आबियाना माफ करेंगे । हमें थोड़े अरसे राव साहब की मिनिस्ट्री में मौका मिला था और हमने पांच किल्ले का आबियाना माफ किया था । मैं चाहता हू कि चीफ मिनिस्टर साहब इसी बजट सैशन के अन्दर यह ऐलान करे कि हमने भी 5 किल्ले का आवियाना माफ कर दिया है । मैं यह भी चाहता हूं कि वाटरटैक्स जो 10 प्रतिशत बढ़ाया है, उसको भी यह सरकार री–कंसीडर करके उसे वापिस ले । इसके साथ ही मैं आपके वह साधन भी बता0ंगा, कि रुपया कहां से आएगा । स्पीकर साहब,सरकार के पास इतना पैसा आ सकता है कि कोई लेने वाला तो हो । जितने हमारे इस वक्त हरियाणा के अन्दर सिनेमें हैं, उन सब को फौरी तौर पर गवर्नमैंट ले ले और उनको जो कम्पनसेशन देना पड़े वह उन्हें 1 2– 12 साल के बाउंडों की शक्ल में दे दिया जाए । इसके अलावा जो साल्ट पीटर की फैक्ट्रियां हरियाणा में हैं, उनसे आपको शायद यह भी पता हो कि एक–एक फैक्ट्री से लोग करोड़ों रुपया कमाने लग रहे हैं और जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, एक आदमी ऐश कर रहा है, ऐश लूट रहा है, उसके बच्चे कारों में घूमते हैं और एक गरीब आदमी 4– 4 रुपए रोज की दिहाड़ी के लिए धक्के खाता फिरता हए, स्पीकर साहब, इन फैक्ट्रियों को फौरी तौर पर सरकार अपने

कब्जे में ले ले और इन सब से जितनी आमदनी हो, वह बेरोजगारी दूर करने में लगाए ।

श्री अध्यक्ष : आपका टाईम हो गया है ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : बस एक मिन्ट में खत्म कर देता हूं । बार–बार मौका नहीं आता । स्पीकर साहब, सीरा जो शूगर मिल में बनता है, इसकी कीमत क्या है सिर्फ 67 पैसे पर–क्विंटल, पर–किलो नहीं पर क्विंटल । आपको पता है कि इसकी शराब बनती है । यह कहना चाहता हूं कि बेशक शराब मंहगी हो, कोई बात नहीं लेकिन आप शीरे की कीमत एकदम 40 रुपये पर–क्विंटल कर दो । इन सजैशन्ज के साथ–साथ मैं एक बात और कहना चाहता हू कि अगर फिर भी हुनको जरुरत पड़े तो साहुकार भाईयों से कर्जा ले लें और उन्हें आहिस्ता– आहिस्ता वापिस देते जाये । ऐसा करने से बेरोजगारी दूर हो सकती है । स्पीकर साहब एक मिनट में खत्म कूर रहा हूं । जिस तरह से आपने लैंडं होल्डिंग एक्ट लागू किया आपने खड़ी फसलो का कब्जा –दिलवाया, हमे कोई एतराज नहीं, लेकिन गरीब हरिजनों को रोजगार देना चाहिए उनकी बेरोजगारी का मसला हल होना चाहिए । आपने अर्बन प्रौपर्टी को एक दम माफ किया है । अर्बन प्रौपटी के पर भी सीलिंग इसी सैशन में आ जानी चाहिए ताकि– गरीब आदमी को रोजगार मिल सके । मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहता हूं कि वे बडे. ग्रौड माइडिड आदमी हैं, बड़े सीधे आदमी हैं लेकिन अगर वे कोई स्टैप जनता की

भलाई के लिए लगे तो हम उनका साथ देंगे और उनके हाथ मजबूत करेंगे । वाटरटैंक्स को वापिस लिया जाये । अगर सरकार वाटर टैक्स को वापिस नहीं लेती तो मैं इस बजट की मुखालिफत करता हूं ।

श्री लछमन सिंह (कालका) : स्पीकर साहब,

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,

वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नही होता । ।

गुनाहगारों में शामिल हैं गुनाहों से नही वाकिफ,

मजा तो जानते हैं, खुदा जाने गुनाह क्या हैं?

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

एमरजैसी की काली रातों के बाद जब इस देश के अन्दर जनता पार्टी जोकि लाखों–करोड़ों लोगों के हितों कीनुमायन्दगी करती है, ने जन्म लिया, तो उसने इस देश के 60 करोड लोगों के अन्दर एक भावना पैदा कर दी । आप लोग जानते हैं कि किस तरह से इन कांग्रेस के भाईयों ने पिछले 1 9 महीनों के दौरान, इस देश के कांस्टीच्यूशन को, इस देश की जो पुरानी रिवायात थीं, उनको समाप्त करके, डर और भय का माहौल पैदा करके देश को बरबाद किया ।

श्री शमशेर सिंह : आन ए प्वांयट आफ आर्डर । जब कल मैं बोल रहा था तो आपने मुझे प्वांयट आउट किया था कि आप बजट पर ही बोलिए । क्या यह बजट पर स्पीच कर रहे है (विघ्न) ––

श्री लछमन सिंह : आपने जो ऐलीगेशन्ज लगाए हैं, उनका जवाब तो मैंने देना है । मेरे दोस्त जो कांग्रेस का सहयोग करते थे, उनकी हिमायत किया करते थे, उन्हें भी यह मालूम नहीं था, या वे शायद यह भूल गए थे कि हमें हरेक एमएलए. या एमपी. को एक लिमिटिड अर्से के लिए चुनकर भेजा हुआ है । इसके बाद मे जनता के पास जाना है और उनके सामने जवाब देह होना है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, आप जानते है, कि लोग आज हल्दी घाटी को याद करते है, हरियाणा प्रताप को याद करते हैं मानसिंह को कोई याद नहीं करता । आज औरंगजेब को कोई याद नही कुरता, गुरु गोबिन्द सिंह और गुरु तेग बहादुर को सब याद करते हैं । अंग्रेजों ने कितने जुल्म किए, 'आज उनको कौन याद करता है लेकिन महात्मा गांधी को सब याद करते हैं । ये कांग्रेस के भाई भूल गए थे कि हम को जनता के दरबार में भी जाना है । गरीबी मिटाने के नारे देते रहे, लेकिन भ्रष्टाचार को बढावादेते रहे और अपनी जेबें भरते रहे । गरीबों के हमदर्द बनते रहे । लेकिन तीस साल तक उन गरीबों का खून ही चूसते रहे । इन गरीब हरिजनों को कितने नारे दिए । सब से पहले इलैक्शन

में मुरब्बा देने की घोषणा की उसके बाद जमीन देने का झांसा दियां और फिर कहा कि सीलिंग में जमीन आ जाएगी, वह दे देगे और आखिर में सौ गज के प्लाट पर आ गए लेकिन दिया कुछ नहीं । उस बेचारे गरीब हरिजन की नसबंदी– करके– छोड दिया । आज ये भाई जनता पार्टी के पर ऐलीगेशन लगाते हैं, मिनिस्टरों के पर ऐलीगेशन लगाते हैं, कि किसी का काम किया, क्रप्शन से पैसा लेकर कन्ट्रोल हटाया ।उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस हाउस केसामने श्री शिमशेरसिंह कोकहदा चाहता हूं कि वह किसी का नाम लेकर बताएं कि किसी मिनिस्टर ने या मेमबर ने पैसा खाया हो । मैं और जनता पार्टी के सारे सा थी आपके साथ होंगे । जनता पार्टो कोई ऐसी पार्टी नही एं, जिसके कोई सिद्धान्त न हों । उसने देश के अन्दर एक सही और ईमानदार सरकार देने का फैसला किया है । अगर हमारे अपोजीशन के भाई कोई कन्स्ट्रक्टिव किटिमिजम करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा–। दो– स्टेट्स में–अगर आपने इलैक्शन जीत लिया द्वुँ तो इतना गुमान–नही होना चाहिए । यह साउथ नहीं है जनता पार्टी की परफामैंस का अगर पहले से मुकाबला किया जाए, तो मैं कहूंगा कि वहां जनता पार्टी ने बहुतगेन किया है । आप, अपने मन से यह चीज निकाल दीजिए कि साउथ में कांग्रेस जीत गई है तो यहां भी वही हालत होगा । आप यह ध्यान मे रखिए कि यह हरियाणा. है । जब तक आप सही बात नही करेंने तब तक डु छ होने वाला नहीं है । आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी के सदस्य किस तरह से अपने मिनिस्टरों से सवाल करते है, किस तरह–से

सवालों. केदौरान उनका घेराव करते हैं । आपके अन्दर तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी । आप तो डिक्टेटर– शिप के अन्दर बन्द थे, आपको बोलने का अख्तियार नहीं था। लेकिन आज आपु देखें कि जनता पार्टी के मैंम्बर किस तरह से अपनी सरकार का क्रिटिसिज्म करते हैं, और मिनिस्टर साहिबान भी आज किस तरह से चौकस रहत्ए हैं । हमें पता हैकि हमें जनता के पास–जाना है, जनता के दरबार में हमकी हाजिर होना है । यहां वह– बात नही है कि इन्दिरा गांधी और सजय की खुशामद करो, उनकें सामने हाथ जोड़ा और इलैक्शन की टिकट ले लो । हमें तो बाबू जब प्रकाश नारायण का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी वजह से इस देश के लोगों को दुबारा वोट देने का अधिकार मिला है। मेरे अपोजीशन केएक भाई ने ला एंड आर्डर की बात कहि । इन्होंने बहुत ज्यादा ऐलीगेशन लगाए । मैं कहता हूं कि एक भी आदमी का नाम ले कर बलाएं, जिसको बगैर कसूर के बगैर वारन्ट के गिरफ्तार किया गया हो । आज तो हालत यह है कि गिरफ्तारी से पहले ही बेल हो जाती है । आज तो जुडिशियरी इतनी पावरफुल है कि वह कानून के अनुसार फैसला करती है। सरकार का कोई दखल उसके अन्दर नही है । मेरे कांग्रेसी भाई इतनी जल्दी भूल गए कि पहले क्या होता था । आज तो ला एंड आर्डर की कोई बात ही नही है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह : अम्बाला में–एक आदमी को सुप्रीम कोर्ट में बेल होंने के बाद भी गिरफ्तार किया गया– (व्यवधान) –

श्री लछमन सिह : ऐसी कोई बात नही है । आप उस जमाने की बात भूल गए । क्या आपने अपने पिता जी को कमी समझाया कि इतना जुल्म न करो । क्यू। एक चीफ मिनिस्टर को यह शोभा देता हए कि किसा बस ड्राइवर को मारे, किसी गरीब आदमी को गाली गलोच करे ।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह : आपको तो बोलनाही नही चाहिए । क्या यह ठीक है कि एक चीफ मिनिस्टर, अपनी कार से उतरकर के एक बस को तमाचे मारे । उस काग्रेस की सरकार में कितना जुल्म होता था, किस तरह से अखबारो को तंग किया जाता था । एमरजेंसी के अन्दर' कहीं हिन्द समाचार की बिजली बन्द कर दी और उनको अपने टैरक्टर से अपना अखबार छापना पड़ा । इण्डियन एक्सप्रैस की बिजली बन्द कर दी । आज आप बोलते हैं कि ला एंड आर्डर नहीं है । आपको तो अहसानमन्द झेना चाहिए । इस देश के लोगों का और जनता पार्टी का कि इस देश मै फिर डैमोकेसी आई है । यह देश गुलाम बन चुका था । बाबू. जय प्रकाश का अहसानमन्द होना चाहिए 'कि डैमोक्रेसी दुबारा जिन्दा हुई है । यह देश बिल्कुल गुनाम बन चुका था

श्री शमशेर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, आप इनको बजट पर बुलवाएं– (व्यवधान) –

श्री लछमन सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने ऐलीगेशन लगाए थे, मैं उनका जवाब दे रहा हू । बजट पर भी

बोलूंगा अभी तो ऐलीगेशन का जवाब दे रहा हू– (व्यवधान) । मैं बता रहा हु कि उस वक्त कानून. की क्या हालत थी औरआज क्या हालत है । इन्होंने बिना मुकरमें बना?! लोगों को जेलों में बन्द करदिया था । पोहल्लू जी भी 19 या बीस महीने जेल में रहे है । इन लोगों को यानी कांग्रेस वालों को तो जनता पार्टी का मशकूर होना चाहिएं कि अगर आज, वही कानून होते तो ये लोग भी जेल में सड़ रहे होते....

श्री सुरेन्द्र सिंह : आन ए प्वांयट आफ आर्डर, मैं दरखास्त करूंगा कि अपने उन. आदमियों के नाम भी बता दें जो जेल से माफी मांग कर आए थे ।

श्री लछमन सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, हर आदमी अपने बारे में बोल सक्ता है, मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि सरकार ने मुझे पैरोल दी थी कि मैंने वह भी ठुकरा दी थी । मैं अपनी ओर से' जनता पार्टी और इस सरकार को मुबारिकबाद देना हूं कि जिस तरीके से आजादाना तौर पर इस देश की सेवा की जा रही है उसके लिए वह मुबारिकबाद की मुस– तहक है । मेरे दोस्त को कुछ तकलीफ होती है कि मैं जनरल डिस्कशन क्यों कर रहा हूं । मैं आरकी इतना के लिए बता दू कि जहां तक ला एंड आर्डर का सवाल है, वह बहुत अच्छी है और काग्रेस के जमाने से भी बहुत अच्छी है । मेरे कांग्रेसी दोस्त तो कल पार्लियामैंट की बात भी यहां कर रहे थे लैकिन मैं अपने अपोजीशन के भाईयों को याद करा देना चाहता हूं कि जनता पार्टी की यह नियत है

और ईमानदाराना कोशिश है कि आप लोग अपोजीशन बैचिज पर. बैठें । हम नहीं चाहते किं आपके अन्दर कोई बाइफरक्रेशन हो । जनता पार्टी ने तो अपने मैनीफैस्टो में कहा है कि डैमोक्रेसी के अन्दर अपोजीशन का मजबूत होना बहुत आश्वयक है । जनता पार्टी तो अपोजीगन को मजबूत देखना चाहती है । बाकी जैसा कहा गया है यिय मुझे बजट पर वोलना चाहिए इसलिए डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं बजट पर बोलता हूं । डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार नें जो पहला बजट पेश किया है उसमें 27– 28 करोड़ का घाटा है । उस पर साढे तीन करोड़ रुपए के टैक्स लगाए है । और बाकी जो डेफिसिट है वह अनकवर्ड हए । मैं खुद मानता हूं कि डेफिसिट फाइनैंसिंग आगे नही ले जा सकती इसमें कोई शक नही है और इस बात कोएक, पढ़ा लिखा आदमी अच्छी तरह समझ सकता है लेकिन हमारे जो अपोजीशन के भाई हैं, वे हाउस के अन्दर कोई सजैशन नही देते । यह तो कहते है, कि कोई टैक्स न लगाए जाएं, फ्रे'। डांसिंग हो जाए, लेकिन सजंशन एक भी नहींदेते कि खर्च को कैसे पूरा किया जाय । सरकार ने फैसला किया है किइस सूबे कों जो कि हिन्दुस्तान की एक बहुत बड़ी इम्पोरटैन्ट स्टेट है उसके अन्दर पीने के पानी का प्रबन्ध किया जाये । यह एक बहुत अच्छी चीज है । जिस सूबे के लोगों को पीने का पानी ठीक नहीं मिलता, वहां के लोग और आने वाली औलादें बहुत ताकतवर नही हो सकतीं ।

इस सब से बड़े जरुरी कदम के पर जोकि सरकार ने उठाया हं, वह सचमुच ही धन्यवाद के लिए हकदार है । इससे आगे डिप्टी स्पीकर साहब, भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहना चाहता हू । भ्रष्टाचार बन्द तो अवश्य होना चाहिए पर मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब और दूसरे साथियों को यह बताना चाहता हू कि यह आसान काम नही है । हम क् तो सकते हैं, हमारे इरादे पाक हो सकते है, ईमानदार भी हो सकते हैं, नियत भी साफ हो सकती है लेकिन न ही त्रेता । न ही कलयुग और न ही रामराज के अन्दर यह रिश्वतखोरी बन्द हुई, चलती ही रही । इस लिए हम सब की यह कोशिश होनी चाहिए कि यह बन्द हो, खुदा करे यह बन्द हो जाए । आप देख लीजिए अमरीका जैसे महान् देश को वहाँ क्या हुआ सब कुछ अखबारों में आया है जापान का प्राइम मिनिस्टर करोड़ों डालर्ज के अन्दर इन्वालव है और आप अखबारों में पढ़ भी रहें हैं कि हमारे बड़े बड़े नेताओं के बाहर के मुल्कों में एका0टस हैं, यह सारी चीजे बन्द होनी चाहिए तभी भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है । हम यह दावा तो नही करते कि रिश्वत पूरी तरह से बन्द हो चुकी है, इस के बारे में तो सरकार ही बतायेगी, जहा तक रुले जाति तौर पर पता है, अमी तक हालात वैसे ही है । जैसे कि पहली सरकार के वक्त पर थे कोई फर्क नही पड़ा है और न ही हमें कोई फर्क पड़ने वाला दिखाई देता है । मैं अपनी पार्टी की तरफ से इन भाईयों को बता देना चाहता हूं जोकि नुकताचीनी करते है कि आप एलीगेशन के तौर पर नही, वैसे बताएं कि फलां आदमी ने करप्शन की है हम उस मामले में

आपका पूरा साथ देंगे लेकिन आप लोग सिवाये नुकताचीनी के कुछ नही कर रहे हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, इससे आगे मैं एजुकेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं आप सब लोगों को पता है कि जब काप्रेम पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो उस वक्त जो एम0एल0 ए0 चीफ मिनिस्टर के नजदीक हुआ करते थे, केवल उन्ही के हल्कों में ही स्कूलज अपग्रेड किये जाते थे लेकिन इस जनता पार्टी की ईमानदारी, इसका काम करने का तरीका आप लोगों के सामने है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने साफ साफ लडकों में कह दिया है कि हमारे बजट में इतनी गूजाइश नही कि हम स्टेट के सारे स्कूलों को अपग्रेड कर दें लेकिन हर हल्के का एक स्कूल अपग्रेड जरुर कर देंगे । सारा हरियाणा हमारा है, हमारे दिलों में यह बात नही है और न ही आयेगी कि यह फलां का हल्का है, यह **चौधरी** शमशेर सिंह का हल्का है, यह **चौधरी** सुरेन्द्र सिंह का हल्का है यहां स्क्लज अपग्रेड न किये जाएं । मैं सरकार से दुर्खास्त करुगा कि ऐसा ख्याल कमी भी हमारे मन में नही होना चाहिए, सब हमारे भाई है, सारा हरियाणा हमारा है, हमारी जनता सरकार ने तो यह सोच रखा है कि सारे के सारे हरियाणा की तरक्की,, मारे हरियाणा के काम करने हैं । हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब का यह फर्ज बनता है, यह डयूटी बनती है कि वे नभीं का एक सा ध्यान रखे । मुझे तो सिर्फ अगर गिला इऐ तो सिर्फ पी0 डब्ल्यू डी0 मिनिस्टर साहब से है क्योंकि वह हर बात कर यह कह देते हैं कि पैसा नहीं है और हम कहते है कि यह बात मत कहो कि पैसा नही पैसा

अवश्य आ सकता है । जब किसी आदमी का व्यापार फेल हो जाता है तो वह पैसे का इन्तजाम कहीं न कहीं से करता ही है । मेरी सरकार से गुजारिश है कि हम जानते है कि इन कांग्रेस भाईयों के समय में किस प्रकार से सरकार का दीवाला पिटा हुआ था एक पैसा भी नहीं था, कौड़ी भी नहीं थी सरकार के पर रिर्जव बैक का ओवर ड्राफट था, रिर्जव बैंक ने चारों तरफ से हरियाणा सरकार को जकड रखा था और हालत यहां तक पहुंच गई थी कि कर्मचारियों को तनख्वाहें भी नही दी जा सकती थी. इसलिए मरकर ने 37 करोड़ रुपया ओवर ड्राफट अदा किया अतः इसके लिए भी सरकार मुबारिक बाद की पात्र है । डिप्टी स्पीकर साहब, इतना बड़ा 200 करोड़ क प्लान है, इस समय पहली दफा बिजली और एग्रीकलचर पर 1 44 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है इससे हरियाणा के किसान पर एक आशा की झलक पडी है, उसको यह अहसास हुआ है कि पहली दफा यह जनता की सरकार आई है, जिसके दिल में किसानों के लिए 24 घण्टे दर्द रहता है । सर्दियों से यह बेचारा किसान नंगा धडंगा जो कि देश की रीढ की' हड्डी कहलाता है! जोकि मारे देश के लिए अनाज पैदा करता है और जिसने मुसीबतों थे, जंगों में अपनी छाती– पर गोलियां खाई हैं, पीठ पर नही खाई, उस किसान को आज इस जनता सरकार के आने पर काफी राहत मिंत्री है. जिसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं । लेकिन इसके साफ साथ एक चेतावनी भी देता हू कि बहुत सारे सज्जन पुरुष इस ब्यूरोक्रेसी के अन्दर ऐसे–ऐसे बैठे होने जो सरकार को उल्टी तरफ ले जाने की

कोशिश करेंगे, आप उनकी बात को न सुनिये! आप अपने मिशन में आगे ही बढते जाए और किसान की जितनी ज्यादा से ज्यादा सेवा हो सके, आप करे ।

डिप्टी स्पीकर साहब, जो टैक्स लगा है उसके मुताल्लिक हाउस के अन्दर बड़ी भारी रिजेन्टमेन्ट है । मैं सरकार से दर्खास्त करुंगा जब सरकार ने पहली दफा किसानों की, गरीबों की मदद करने की कोशिश की है, वहां यह जो आबयाना लगाया गया है, उसको विदा किया जाए, यह मेरी सरकार से अपील है । सरकार इस टैक्स के मुताल्लिक दोबारा सोचे । पैसे की कमी को किसी और तरह से भी पूरा किया जा सकता है जहां पर सरकार 26 करोड़ रुपये का गैप पूरा करेगी उसी तरह से इस गैप को भी पूरा करने में सरकार को कोई दिक्कत नही आयेगी । मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से एक दर्खास्त करुंगा कि इससे जो किसान के अन्दर घबराहट है, उससे किसान बुरी तरह से पिन रहा है, उस घबराहट को शीघ्र ही किसी न किसी तरीके से दूर किया जाए ।

इससे आगे एक और बात अम्बाला जिले के बारे में अवश्य कहूंगा उस जिले के साथ अन्याय हुआ है । यहां पर एक शूगर मिल है । जिसमें हड़ताल चल रही है, जिसके कारण जमींदार और किसान लोग पिस पे हैं, पता नही कब झगड़े का फैसला होगा यह मामला हो सकता है एक दो महीने चले भी पर उतनी देर तक गन्ने का रस खत्म हो जाएगा, जिससे किसान की करोड़ों रुपये की फसल बर्बाद हो जायेगी । मैं अपने चीफ

मिनिस्टर साहब कौएके सुझाव दूंगा कि अगर उस मिल को सरकार अपनें कब्जे में ले ले तो कानुनी तौर पर कोई दिक्कत नही होगी और अगर सरकार उसके कंपेन्सैशन के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस करेगी तो उसके लिंए हम घर–घर जाकर झोली फैली केर जो भी सरकार को कंपेन्सेर्शर्न 'देना पड़ेगा वेइहं हम जमीदारों से नोट इकट्टे करके देंगें । इस लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब को कहूंगा कि हम संब अधिक नाथ 'हैं, हमेशा के लिए यह जो कैन्सर बना हुआ है पालिंटिक्सं में डिस्टबैंस पैदा करता हे, समाज कौ भी डिस्टर्ब करता है, सोशल ऐंनीमी है, ऐन्टी सोशल काम भी करता है ऐसी चीजों को इस मौके पर निकाल दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। अगर इस काम को करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब देर करेंगे तो आफिसर लोग बहुत कायदे' कानूनों में पड़ेगे और उन लोगों की मदद करेंगे क्योंकि हर रोज स्कौच की बोतलें उडती है, वे लोग तो उनकी ही मदद करेंगे । आप अपनी तरफ से आर्डर पास कर दीजिए, चाहे आप इस पर वोट भी करवा लीजिए । चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी दर्खास्त है कि इतना ही कर दें कि बस इतना ही काफी दूँ, इमलें लिए आपके पर कोई इलजाम नहीं लगेगा । इससे आगे मैं कालका के मुताल्लिक जो कि बैकवर्ड है, पिछड़ा हुआ इलाका है, कुछ कहना चाहता हूं । आप अखबारों में पढते होंगे कि कमिशन बनने वाले हैं, पंजाबी स्पीकर वाले कहते है कि आप हमें दे दीजिए, हिमाचल वाले भी कई बार कई इलाकों गर दावा करते है, कल को तो यू 0पी0 वाले राजस्थान वाले भी आकर दावा करने लगेगे लेकिन मैं

इस हाउस को बता देता हूं कि जब तक मैं वहां पर एम0एल 0 ए 0 की हैसीयत में हूं एक इंच भूमि भी तब तक किसी दूसरी स्टेट को नही जाने दूंगा तमाम की तमाम हरियाणा में ही रहेगी' मुझे लोगों के इरादों का पता है, इसके लिए मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से बिनती करुंगा कि कालका को सबडिवीजन जरुर बना दिया जाए, इससे ज्यादा लोगों को तसर ली होगी, और वह महसूस करेंगे कि वाकई जनता सरकार ने लोगो की' मागो को उचित ठहराया है । डिप्टी स्पीकर साहब, एक तरफ चोटाला है, और एक तरफ कलका है, लोगों के दिलों में यह न आये कि मुख्य मन्त्री महोदय ने अपने हल्का को तो सब डिवीजन बना 'दिया है और कालक को छोड़ दिया गया है । इसलिए सरकार को इस तरफ पूरा– पूरा ध्यान देना चाहिए । दूसरा जो सरकार ने सड़कों का काम किया है और पीने के पानी की जो व्यवस्था सरकार ने की है, उसके लिए सरकार के लिए एक और मुबारिकबाद का पैगाम लेकर जनता आई है । इसके साथ मैं कहूंगा कि लोगो काम चाहते है, सिर्फ नारों से लोगों का पेट भरने वाला नहीं है । इसलिए अगर हम यह कहते जाएने कि पैसा नहीं है तो बहुत देर तक यह बात चलने वालो नहीं हैं, हमारे एफ 0 एम 0 साहब यहां पर नही बैठे हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि यह सरकार का फर्ज हैं कि वे पैसे का प्रबन्ध करे । अगर ऐसे मामले में सरकार को मुशकिलात पेश आ रही है तो सरकार हाउस को काफीडेन्स में ले सकती है इसके लिए एक कमेटी' बना सकती है, लोन, लिए जा सकतें हैं अगर सैन्ट्रल गर्वनमैन्ट से किसी प्रकार की 'मददकी

आवंश्यकता है तो हम सब भाई वहां जाकर उन से यह कह सकते हैं कि हम तालाबों का, और जोहडों का पानी पीते हैं, हमें इस काम के लिए पैसे की आवश्यकता है । सरकार को सड़कें बनाने के लिँए पैसे की जरूरत है वह कर्जा लेकर सउके बना सकती है । इसी. से आपका नाम हो जाएगा । यह कोई नही पूछता कि आप कहां से पै सा एते हैं । एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब आगे के लिए कोई टैक्स लगाया जा च. तो वह हाउस के जरिए लगाया जाए, न कि आर्डिनंन्स के जरिए । आर्डिनंन्स के जरिए जो टैक्स लगाए जाते हैं, उससे लोगों के मन में शिकवा होता है । यह बात अपोजीशन आये भी कहते है और अपनी जनता पार्टी के भाईयों से भी कहूंगा कि जा भी मैंबर बजट पर बोले, अगर वह मेरा भाई इसको ठीक समझता है. तो इस मामले पर अपने विचार जरूर रखे । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी नजर देख रहा हूं, इसलिए ज्यादा टाईम नहीं लूंगा और जल्दी ही वाईड आर करने की कोशिश करुंगा' । बहुत ज्यादा पैसा अलग अलग मदों में रखा गया है लेकिन जत्थ के अन्दर बहुत कम पैसा रखा गया है । कम पैसे की वजह से हैलथ मिनिस्टर साहब पर बहुत बोझ पड़ेगा । आप देख रहे हैं कि जिन इलाकों में फल्ड आया वहां के लोगों की दवाईयों की कितनी जरूरत है इसलिए हैल्थ की मद को सरकार फौरी तौर पररू रिवाइज करे ।

11.00 बजे

श्री शमशेर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब. मेरा प्वांयट आफ आर्डर है कि इस समय न तो चीफ मिनिस्टर साहब हाउस में हैं, और न हीं फाइनैम मिनिस्टर साहब हैं । उनके।. जवाब देने के लिए कुछ प्वांयट्स नोट करने होते हैं, तो वे जवाब कैसे देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे मिनिस्टर साहिबान बैठे है ।

श्री लछमन सिंह : उनके कमरों में माक्रोफोन लगे हुए हैं और वे डिस्कशन को वहीं सुन रहे हैं । तो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका तथा हाउस का धन्यवाद करता हू जिन्होने मेरी बात को गौर से सुना । मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि जब दूसरे भाई बोलेंगे, तो वे भी शुगर मिल के मसले पर, हैल्थ के मसले पर और आबियाने के मसले पर अपने अपने विचार रखेगे ।

चौधरी गंगा राम (गोहाना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं बजर पर बोलते हुए सब से पहने कृषि के सम्बन्ध में बोलना चाहूंगा । जैसे सरकार ने नए टैक्स लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपए के लगाए हैं और उसमें से किसान के पर जो कि सारी जनता के 80 प्रतिशत लोगों का पेट पालता है और उसके पास सारी दौलत का केवल 40 प्रतिशत हिस्सा है, के पर एक करोड़ रुपए के टैक्स लगाए गए हैं । मैं यह देख कर हैरान हू कि वे 20 प्रतिशत इन्सान जिसके पास सारे हरियाणा कौ सम्पत्ति का 60 प्रतिशत हिस्सा है, उस पर कुछ भी टैक्स नही लगाया गया है ।

(इस समय सभा पतियो की सूचि मे से एक सदस्य **चौधरी** खुरशीद अहमद पदासीन हुए ।)

इस सारे टैक्स को देखकर मैंने जो रिजल्ट निकाला है, वह यह है कि हमारा जो इस साल का टोटल प्लान है, उसका केवल 2प्रतिशत किसान के पर खर्च दिखाया गया है, जबकि हमारी सरकार का यह वायदा था कि किसान के पर 40 प्रतिशत खर्च किया जाएगा । इसके अलावा जो आबियाना बढ़ाया गया है, जो किसान के पर वाटरटैक्स बढ़ाए गए हैं, इ नसे कोई बात नहीं बनती, क्योंकि सरकार जे' हमारे पर खर्च करती है, वह 22 करोड़ 49 लाख बनता है और किसान जो. सरकार कों डायंरैक्ट लैण्ड से देता है वह 10 करोड़ 59 लाख रुपए देता है और लैछडरैवेन्यू 5 करोड़ 77 लाख रुपए देता है । इसके अलावा सेल्ज टैक्स, पैसेन्जर टैक्स डियूटी इलैक्ट्रिसिटी, डचूटी कोर्ट फीस वगैरह से सरकार को जो आय होती है, वह 123 करोड़ रुपये की होती है जिसमें आधी किसान देता है । इसके अलावा 84 करोड़ रुपया और जरियों से हम सरकार को देते हैं । इसके बाद सरकार को 20 करोड़ रुपए सालाना आमदनी देसी शराब से होती है । इस 20 करोडु रुपए में से लगभग 15 करोड़ रुपए की शराब की खपत देहातों में हो जाती है तो यह सारी बातें लेकर मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि हरियाणा का किसान जो है, व ह सरकार को 107 करोड़ 43 लाख रुपए सालाना दे रहा है और हमारे पर सरकार जो खर्चा करने जा रही है, वह 30 करोड़ रुपया सालाना

है । इसके अलावा हमें फल्ड से 100 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ है तो इन सारी बातों के।. देखकर मैं यह बता सकता हूं किं सरकार हमारे 0पर जो खर्च करती है, उससे फालतू 7 7करोड 43 लाख हमारे से ने रही है, इसलिए मैं ते'? यह कहूंगा कि हमारे पर जो एक करोड़ रुपए का टैक्स लगाया जा रहा है, इसको लगाने की जरूरत ही नही थी, क्योंकि हम तो पहले ही 77 करोड़ 43 लाख रुपया फालतू दे रहे हैं । मैं देखता हु कि जो बजट तैयार किया जाता हं, वह रटा रटाया होता है । पिछले 20 सात्र से कुछ आइटम्ज मुकर्रिर कर रखी हैं, और फाइनैस सैक्रेटरी बैठकर बजट तैयार कर देता है और फाइनैस मिनिस्टर का अंगूठा लगवा लिया जाता है है । फाइनैसं मिनिस्टर को बिल्कुल पता नही होता कि एग्रीकल्चरिस्ट सरकार को कितना देते हैं । कुछ आइटम्ज बना दिए जाते दैर और उन्हीं आइटम्ज पर टैक्स लगा दिए जाते है । कर्मा उसको बैटरमैंट लेवी का नाम दे दिया जाता है, तो कभी उसको आबयाने का और कभी कोई और नाम दे दिया जाता है । इस तरह से टैक्स लगाए जाते हैं । तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने जो वायदे किए थे, कि हमारी टोटल योजना का 40 प्रतिशत किसान के पर खर्च किया जाएगा, लेकिन वह इस बजट के अन्दर केवल 17 प्रतिशत किसान के पर खर्च किया हे । तो मैं सरकार से मांग करुंगा कि किसान के पर जो आबयाना लगाया गया है, इसको वापिस लिया जाए, और अभी मेरे एक भाई ने कहा था कि यह नही बताया जाता कि टैक्स कहां से इकट्ठा किया जाए । मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि

फरीदाबाद में सरमाएदारों के कारखाने हैं । इन सब कारखानों के जो हैड आफिसज हैं, वे दिल्ली के अन्दर बने हुए हैं । सारे हरियाणा की धरती की कमाई इन कारखानों पर लगाई जा रही है । इनको हरियाणा के पैसे से सड़क देते है, बिजली देते हैं, रॉ–मैटीरियल देते हैं, कारखाना लगाने केलिए जमीनें देते हैं 'लेकिन इन सब कारखानो की पैदावार की बिक्री दिल्ली 'में जोकर करते हैं और करोड़ों रुपए का सेल्ज टैक्स दिल्ली वालों को दिया जाता है । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी–फरीदाबाद के कारखाने हैं, उन के हैड आफिसिज हरियाणा के अन्दर होने चाहिए । ट्रू स तरह से करोड़। रुपया हरियाणा को मिल सकता है ।

इसके इलावा, मैं कहना चाहूंगा कि शराब और शादी दो ऐसी चीजें है, जिसने देहातों को बरबाद कर दिया है । अगर सरकार पैसा लेना चाहती है, तो शराब के पर 80 प्रतिशत टैक्स लगा दे । जहां तक शादियों का ताल्लुक है, मैंने दे खा है कि शादियों पर लाखों रुपए बरबाद किए जाते हैं । शहरों के अन्दर बैड–बाजे के पर 15–20 हजार रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, इन शादियों पर टैक्स लगाया जा सकता है और सरकार को लाखों रुपयों की आमदनी हो सकती है । ये इन्कम के साधन है?

जिस समय देश में पार्लियामैंट के चुनाव हुए थे, तो मैं जनता पार्टी के अन्दर था और उस समय हम कहा करते थे कि जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, उन चीजों पर टैक्स नही

लगेपा, उन साधनों पर टैक्स नही लगेगा जिनको किसान इस्तेमाल करता है । टैरक्टर की पैदावार जो कारखाने के अन्दर होती है वह किसान को नो प्रॉफिट नो लॉस पर दिया जाएगा. खाद किसान को नो प्रॉफिट नो लॉस पर दो जाएगी । इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करुंगा कि यह सरकार किसानों की सरकार है देहातियों की सरकार है और मजदूरों की सरकार है । किसान को जो नुकसान होता है चाहे फतह से होता एह चाहे ओलों से होता है उसको मुआ– व ना दिपा जाए । अगर कोई सरमाएदार का कारखाना जल जाए बिगड़ जाए किसी कारण से खत्म हो 'जाए तो सरकार उसको कम्पनसेट करती है मुआवजा देती है लेकिन किसान की करोड़ रुपए की सम्पत्ति बरबाद हो जाए तो सरकार कुछ नहीं देती । मैं सरकार से प्रार्थना करुंगा कि किसान को कर्जा मत दो, तकावी मत दो, बल्कि उसको कम्पनसेट करो । जो तकावी दी जाती हैवह कर्जे केरूप में नही दी जानी चाहिए और अगर देनी है तो इन्टैरस्ट की देनी चाहिए । हम लैण्ड मार्गेज बैंक से, को आप्रेटिव बैक से और दूसरे बैकों से जो खेती के लिए कर्जा लेते हैं, उस पर 16 और 17 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लिया जाता है । इतना ज्यादा ब्याज देकर किसान बरबाद होता जा रहा है । जो सरमाएदार हैं, पूजीपति हैं, अगर ये करोड़ों रुपए के कारखाने लगाना चाहें, तो सरकार उन से 3 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज चार्ज करती है, लेकिन किसान को 17 प्रतिशत पर पैसा दिया जाता है । मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूगा कि होता यदु चाहिए कि किसान को 2 प्रतिशत के हिसाब से दे और सरमाएदार

को 20 प्रतिशत के हिसाब से दे । जो पिछली सरकार नें गल्तियां की, वह इस सरकार को नही करनी तो चाहिए । सरकार शायद यह समझती हो कि बड़े–बड़े कारखानेदारों से देश का सुधार होगा–, यह बिल्कुल इम्पौसिबल हए । मैं कहना चाहूंगा कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, इस देश का जो खून है, इस देश की जो जान है, वह देहात के खूडों के अन्दर है । यह देश किसानों का है और इस राज के अन्दर सारी सहूलियतें किसान को मिलनी चाहिएं । आज किसान का गन्ना 6 रुपए और 8 रुपए क्विटल के हिसाब से लिया जा रहा है । मन्त्री महोदय ने लाचारी जाहिर की कि शूगर मिलों के मालिक कन्ट्रैक्ट को तोड देते हैं, वायोलेशन करते हैं, एग्रीमेंट को तोड़ देतें हैं, और शूगर मिलों के मालिकों को कम्पैल नही कर सकतें कि फलां भाव पर गन्ना लो। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि अगर चन्द दो चार मिल मालिक मिल कर फैसला कर लें, कि हम 3 रुपए क्विटल के भाव से लेंगे तो किसान को ये एक दिन खत्म कर देंगे । मैं कहना चाहूंगा कि पहली सरकार ने किसान के गेहूं को बेचा है, मुझे इस बात का दुख है । इस सरकार में ऐसे? कभी नहीं किया, क्योंकि यह किसानों की सरकार है । लेकिन इलसे पहले जितनी सरकारें आई । उन्हींने किसान के घर से जबरदस्ती गेहूं निकाला, किसान के कोहलू को नही चलने दिया और किसान की फसल पर उसका अपना भाव नहीं लगने दिया । इसके दूमरी तरफ मिल मालिक जबरदस्ती कर रहे हैं । मर वैवल के जमाने मे सर छोटूराम ने कहा था कि हम गेहूं कों दो रुपए, चार रुपए में नहीं बेचने देंगे,

खड़ी फसल को जला देंगे उस समय दो चार रुपए का भाव मुकरर्र किया था और **चौधरी** छोटू राम ने कहा था कि हम फसल कौ आग लगा देंगे, मगर इस भाव पर बेचने नहीं देगे । इसी तरह ये फैक्ट्रिया जो किसान को हमेशा लूटती हैं, उनकी लुटाई बन्द होनी चाहिए, इनको आग बेशक लगा देनी चाहिए ।

इसके अलावा मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमने अपने मैनीफैस्टो के अन्दर, जिस समय देश में इलैक्शन लड़े जा रहे थे, एक बात कही थी किसवा छ एकड़ जमीन के मालिक जो हमारे भाई है, उनकी उगाही माफ की जाएगी । सरकार ने किसानों से जो वायदा किया है. उसको निभाए और सवा छ एकड़ के मालिक किसानों की उगाही माफ की जाए ।

चेयरमैन साहब, हरियाणा के अन्दर बड़े फ्लड आए, और मैं सरकार की बड़ी सराहना करता हू जिसने फलड के इस कठिन समय पर काम किया । जो काम इस सरकार ने किया वह आज तक किसी सरकार ने नही किया. लेकिन मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा जैसा हमे पिछले अनुभव से पता है कि हमारे जितने प्लान हैं, जितने फ्लड कन्ट्रोल के प्लान है, उनको महकमा जून और जुलाई में शुरु करता है । मैं आज भी देख रहा हूं कि जो ड्रेनज खोदनी थी अब तक उनका नाईट तक नहीं देखा गया, कोई जमीन एक्वायर नही की गई, महकमे का कोई आदमी डप्यूट नहीं किया गया । मुझे डर है कि अब काम जून और जुलाई में शुरु न हो । इसलिए मैं प्रार्थना करुंगा कि किसान को बचाने के

लिए फौरन पैसा लगाना शुरु किया जाए और सारी स्कीम को अभी से चालू किया जाए.

श्री वीरेन्द्र सिंह : तीन महीने से शुरु है ।

चौधरी गंगा राम : चेयरमैन साहब, शिक्षा के साथ हरियाणा के अन्दर खिलवाड़ हो रहा हए । हर शहर के अन्दर हम देखते है कि जगह–जगह शिक्षा के केन्द्र बने हुए है, प्राइवेट मकानों में दुकाने बन गई हैं और कमाई के साधन –बना लिए गए है । कहीं जेबी. टी. की ट्रेनिग. कहीं आर्ट एड क्राफ्ट की ट्रेनिंग, कही टाईपिस्टों की ट्रेनिंग हो रही हैऔर इस तरह से लाखों रुपया कमाया जा रहा है और ये शिक्षा केन्द्र, शिक्षा केन्द्र न रहकर भ्रष्टाचार के गढ़ बने हुए है । पिछले दिनों गोहाना मे हड़ताल हुई, एक शिक्षा केन्द्र है, मैं नाम नही लेना चाहता, 30 लड़कियां अपनी इज्जत बचाने के लिए । एक डाक्टर की कोठी में घुस गयीं । इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करुंगा कि जो शिक्षा की प्राइवेट संस्थाए हैं, हरियाणा के –अन्दर उनका सरकारीकरण होना चाहिए । वे प्राइवेट संस्थाएं, जो ठीक तरह से नहीं चल रहीं, उनके बारे में सरकार को ठोस नीति अपनानी चहिए ।

इसके अलावा, मुझे आज एक बात पर बड़ी हैरानगी है, मै सभी के बारे में नहीं कह सकता, अच्छे और बुरे सभी जगह होते हैं । कुछ अफसर साहिबान को–आपट नहीं कर रहे । एक काम जो चार दिनों के अन्दर होना चाहिए, वह तीन महीने के

अन्दर नहीं होता । इसी वजह से जनता परेशान है । मुझे इस बात की हैरानी है

श्री सभापति : आपु टाईम का भी ख्याल रखे । (व्यवधान)

चौधरी गंगा राम : चौधरी शमशेर सिंह ने 50 मिनट लिए थे –(व्यवधान)

ये तीन आदमियों के लीडर हैं जबकि मैं पांच आदमियों का लीडर हूं । –– (विध्न)–

श्री सभापति : फिर भी आप टाईम का ख्याल रखिये ।

चौधरी गंगा राम : चेयरमैन साहब, आज मैं एक बात पर बड़ा हैरान हुआ । हमारे यहां 9 आदमियों का, 9 रत्नों का एक गठजोड़ बना है और उसमें मेरा नाम भी शामिल कर लिया गया है । पता नहीं यह पंजाब केसरी अखबार है या कोई अखवार है उसमें यह बात आई है लेकिन लगता है कि शायद मांगे राम की. जगह या किसी और की जगह गंगा राम का नाम जोड़ दिया गया है । इसलिए मै हाउस को और प्रैस वालों को बताना चाहता हूं कि बंसी लाल के और सुरेन्द्र सिंह के नौ रत्नो मे मेरा नॉम बिल्कुल नहीं है । – (विध्न) – मैं तो यह कहता हू कि पोहलू का, असली किसान का भला इन्दिरा काग्रेस के हाथों नही हो सकता । इसलिए काग्रेस (आई.) मेरा नाम अपनी लिस्ट में नहीं

लिखवा सकती । अगर तुम्हारा नाम हो, तो तुम कटवा लेना । –– (विध्न) ––

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : मैं तो विशाल हरियाणा पार्टी से हूं ।

चौधरी गंगा राम : विशाल हरियाणा पार्टी के बारे में तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इन देश के अन्दर एमरजेंसी के दिनों में इन्दिरा और बसी लाल के राज का नंगा नाच चल रहा था–– (विघ्न) –

Chaudhari Jagjit Singh Pohloo : There should be no attack on the party at all.

चौधरी गंगा राम : मैं पार्टी के पर अटैक नही कर रहा हूं । मैं तो यह बता रहा हूं कि एमरजेंसी के अन्दर जब इन्दिरा अरि बंसी लाल 'के राज का नंगा नाच चल रहा था, तो यह पार्टी भी उसमें हिस्सेदार थी । – (विंघ्न)

श्री शमशेर सिंह : चेयरमैन साहब, कृपया इन्हे बोलना सिखा दीजिए कि कैसे बोलते है, कैसे नाम लेते हैं ।

चौधरी गंगा राम : चैयरमैन साहब, ये हाई कोर्ट में बैठे हुए ज्यादा लूट करते हैं, जबकि मैं लोअर कोर्ट से बैठा । ये मुझे क्या बोलना सिखाएंगे?

श्री सभापति : जबान दोनों की सही होनी चाहिए ।

चौधरी गंगा राम : हां, तो चेयरमैन साहब.....

श्री सभापति : आप वाइन्ड अप कीजिए, क्योंकि टाईम बहुत हो गया है ।

चौधरी गंगा राम : चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि यह जो पैसेन्जर टैक्स बढ़ाया हैय इसका ज्यदातर बोझ जो है, वह गरीब जनता के पर आकर पड़ता है, क्योंकि टैक्सी और कारों में तो पैसे वाले चलते हैं, बाकी जितना गरीब तबका है, वह बसों के अन्दर चलता है । इसीलए मैं तो यह कर्का चाहूंगा कि अगर टैक्स लगाना हैंतो शहरों के अन्दर जो आदमी दस– दस हजार गज के प्लाट लिए बैठे हैं, उनके पर लगाए । इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जौ –जमीन की सीलिंग की जाती है, यह भी गलत बात है । – (विध्न)– मैं हर देहात के अन्दर फिरा हूं । किसान जमीन की सीलिंग का विरोध नही करता, हम भी नही करते लेकिन मैं इस सरकार से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप जमीन लेना चाहते हैं, तो ले ले मगर हम कारखाने भी चाहते हैं, हम फैक्ट्रीज भी चाहते हैं, हम बिरला, टाटा, डाली–मया और हरियाणा के सरमाएदारों के हवाई जहाज भी चाहते हैं । आप इनको भी लें इसलिए अगर यह सरकार जमीन का बंटवा रा करती है, तो दूसरी धन सम्पत्ति और कारखानों आदि का भी बंटवारा होना चाहिए । चेयरमैन साहब, आप देखेंगे कि जितने भी पैसे वाले, सर– माएदार लोग हरियाणा के अन्दर वैठे हुए हैं, उनके पर एक पैसे का भी टैक्स नहीं लगा है । जब ऐसी बात है तो मैं बड़ा

हैरान हूं कि किसान के पर क्यों टैक्स लगाया गया? इसके अलावा चेयरमैन साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं सारे बजट को मैंने पढ़ा है, सारी बजट स्पीच मैंने देखी है, लेकिन बड़े अफ्सोस की बात है कि इसमें बैकवर्ड क्लास का कोई नाम नही है, उसको कोई रियायत नहीं है, कोई कनसैशन नही है, कोई कर्जा नहों है, कोई पैसा नही है । सारे का सारा औसा दूसरो कम्युनिटीज को दिया गया है । मैं अनुसूचित जातियों का विरोध नहीं करता, मैं हरिजनों का विरोध नहीं करता, उनको जो कनसैशन है, वह उनको मिलना ही चाहिए लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि बैकवर्ड बलास के लोगों ने बसा लील सरकार को नही जनता पार्टी को वोट दिए हैं । –– (विध्न) –– पांच लाख उन्हत्तर हजार के कर्ज में से बैकवर्ड क्लास के हिस्से बड़ी मुश्किल से 11 हजार रुपया आता है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पंजाब के अन्दर, हिमाचल के अन्दर बैकवर्ड क्लासिज को रियायते दी जाती हैं, हरियाणा में भी दी जानी चाहिएं ।

इसके अलावा, चेयरमैन साहब, हरियाणा की सर्विसिज के मामले में मैं यह कहना चाहूंगा कि उच्च कोटि की जो कुर्सियां हैं, उनके पर आज भी बसा लाल के लगाए हुए, बंसी साल के चहेते बैठे हुए हैं जो रकम कमाकर बंसी लाल को पैसा दे रहे हैं । मैं इस बात को साबित कर सकता हूं । (विध्न)

Shri Verendar Singh : Officers should not be discussed.

चौधरी गंगा राम : मैं आफिसर्ज को कंडैम नहीं कर रहा हूं! मैं तो यह कहना चाहता था कि जनता पार्टी को हम भी चलाना चाहतें हैं, हम भी जनता पार्टी के हमदर्द हैं, लेकिन हमारे साथ तो वह बात हो रही है जैंसे एक बुढिया के साथ होती है । आपको पता है, चेयरमैन साहब कि एक नौजवान लड़का अपनी बुढिया मां को बेशक धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दे, लेकिन वह फिर भी उसके साथ हमदर्दी रखती हए । (विघन)इसलिए चेयरमैन साहब, मैं तो एक हकीकत कहना चाहूंगा कि आज इस ढाचे के खिलाफ सारी जगह रिजैन्टमैट है । यदु नहीं कि दोष हमारा है, लेकिन आपके जो कानुन है, अ। पके जो आर्डर्ज हैं, उनकी इम्प्ली– मैंटेशन नहीं हो रही है । व्यर्थ के ऑब्जैकशन्ज लगा दिए रू. ते हैं । चेयरमैन सा हब कई मन्वियों की हालत तो यह है कि अगर उन्होंने पेशाब करने भी जागी हो, तो वे अपने सैक्रेटरी से कहते हैं कि किताब लाओ, और देखे कि उसमें पेशाब करने का प्रोविजन है या नही । –– (हसी) –– यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने आपसे कुछ करवाना है, किस.। न– के हक को बात करवानी है । आबजेवशन क्या होता है? ऑब्जैक्शन. कुछ नहीं होता । ऑब्जैक्शन को दूर करना एक मिनट की बात हए. । कानून गरीबों के हक का बनना चाहिए । लोकतन्त्र में तो जो मिनिस्टर साहिबान कहते हैं, वही कानून होता हुँ. बाकी कानून तो बदलते रहते हैं ।

श्री सभापति : अब आप खत्म कीजिए ।,

चौधरी गंगा राम : अभी तो कुछ भी नही हु जा । कल **चौधरी** शमशेर सिंह जी ने 50 मिनट लिए थे ।

श्री सभापति : 25 मिनट तो आप भी ले चुके ।

चौधरी गंगा राम : चौयरमैन साहब मैं अपनी सरकार को आगाह करना चाहूंगा कि कांग्रेस का भट्ठा लग बिठाने वाले केवल चन्द व्यक्ति थे, जो लूट करते थे, जिन्होंने सिविल लिबर्टी का खात्मा कर दिया– था । आज ये चिल्लाते है सारी स्टेट में दो चार सीटे लेकर । मैं इन्हें एक बात साफ लफ्जो में कहना चाहूंगा कि यदि यहां जनता पार्टी नही चल पाई, तो हरिया या। की जनता भले कुएं में पड़ जाए मगर इन्दिरा कांग्रेस यहां नही आ सकती । कई भाई समझते हैं कि मैं तो आंखें मीच कर चौधरों देवी लाल की स्पोर्ट ये लगा रहता हू, लेकिन मैं अखबार वालों को और इस हाउस को बता देना चा हत) हू कि हम कडीशनल स्पोर्ट देंगे । जहां कन्डेम करने की बात होगी, वहां छक कर कन्डैम करेंगे । –– (विध्न) ––

श्री सभापति : एक–एक चीज को आप तीन तीन बार रिपीट कर चुके हैं । आप तशरीफ रखिए ।

चौधसे गंगा राम : चेयरमैन साहब, मैं हाउस के सानने यह बात रखना चाहता हूं कि आबियाना खत्म किया जारा । मेरे उधर बैठे भाई डिस्पिलिन के कारण बोल नहीं सकते, लेकिन अगर आप हाथ उठवा कर देखो । तो 75 के 75 इसके विरोध में हाथ

उठाएंगे । और कहेंगे कि अ। बियान। खत्म होना चाहिए, यह बिल्कुल नहीं लगना चाहिए । –– (शोर) ––

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

चौधरी गंगा राम : तो मेरी यह मांग है कि यह जो वाटर टे रस लगाया गया है, यह वापिस लिया जाना' चाहिए ।

श्री सभापति : सभी मैंबर साहिबान से मेरी दरखास्त है कि जब माइक उनके हाथ में आ जाता है, तो बोलते ही रहते हैं । दूसरे मैंबर साहिबान भी बोलना चाहते हैं, इसलिए जो भी मैंबर बोलना शुरू करे, वह थोड़ा टाईम ले, ।

कामरेड शंकर लाल : चेयरमैन साहब, मैं बजट परे बोलना' चौका हूं?

चौधरी लाल सिंह : चेयरमैन साहब, मुझे भी बोलेने का टाईम मिलना चाहिए ।

श्री सभापति : जब आपको टाईम मिलेगा तव आप याँसे । अभी आप बैटिए ।

चौधरी लाल सिंह : चेयरमैन साहब, मैंने चिट भेजी थी ।

श्री सभापति : चिट तो हरेक मैंबर ने भेजी है ।

चौधरी लाल सिंह : चेयरमैन साहब, मुझे गवर्नर एड्रैस पर भी नही बोलने दिया । मेरा हक हे । मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए ।

श्री सभापति : आप दूसरों के टाईम में बोल लेते है । आपको अपना टाईम लेने की क्या जरूरत है । आप का भी ख्याल रखा जाएगा ।

कामरेड शंकर लाल' (सिरसा) : चेयरमैन साहब, आज मुझे बजट पर बोलने का मौका मिला है । चेयरमैन साहब आपके माध्यम से मैं इस हाउस में इस बजट के अनुसार जो बातें हैं वे कहना चाहता हूं । हरियाणा का बजट आज हमारे हाउस के सामने आया है । बजट के अन्दर जो बाते ठीक है, उनको अई मानेंगे लेकिन जो गलत बात है उन्को गलत मानेंगे । इस बजट के अन्दर जो टैक्म लगाये गये हैं चाहे वह आवियाने का टैक्स है जो किसानों पर लगा है या किसी और पर दूसरे टैक्स लगे हैं वे ठीक नहीं लगे । आबियाने में दस फीसदी की– बढ़ौतरी की है और पैसेन्जर टैक्स में भी दस फीसदी. की बढोतरी– की है । मैं यह कहूंगा कि यह जनता विरोधी टैक्स है, जन विरोधी टैक्स है । मै यह बात सारे हाउस के सामने कहूंगा कि यह बजट पास होगा और हम सब लोग हारुन के साथ वोट देने क्योंकि हम लोग एक अनुशासन में, डिस्पिलिन में बन्धे हुए हैं इसलिए हम हक में बोट देंगे लेकिन यह जो टैक्स लगा है यह जनता विरोधी टैक्स है । इसमें कोई दो राय नही हो सकती ।

दूसरी बात कर्मचारियों के विषय में है । जब सरकार के सामने कर्मचारियो का मसला आया तो उनको सितम्बर 1977 से किस्त की बजाए जनवरी से दी गई है (यह कर्मचारियों के पर बहुत बड़ी मार है । हरियाणा के दूसरी तीसरी और चौथी – श्रेणी के कर्मचारी इस वक्त बहुत ही मायूस हैं वे चाहते है कि हमें ज्यादा पैसा मिले, उनको वहुत थोड़ा पैसा मिला हू और टैक्स उन लोगों पर बहूत ज्यादा बढ़ा है ।

चेयरमैन साहब, मैं ज्यादा नही बोलूगा, हाउस का बहूत थोड़ा सुख लूगा। एक बात मैं यह भी कहूंगा कि जहां टैक्स जनता की इच्छाओ के खिलाफ है, जनता इनसे दबेगी. किसान दबेगा तो वह हमारी पार्टी का विरोध करेगा ।

चेयरमैन साहब किसानों के लिए हमने जो एक संघर्ष समिति बनायी थी ' जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी शामिल थे । 'वे उस समिति के 'अध्यक्ष थे । उस वक्त' हमने फैसला किया था कि किसानों का लैन्ड टैक्स खत्म करेंगे, हमने कहा था कि हम भी आपके साथ हैं । मैं भी उस वक्त उस वरकिंग कमेटी का मैम्बर था । हम बड़ी बडी सभाओं में बोलते थे लेकिन आज वह बात गलत मिड होती दिखायी दे रहो है । अभी पिछले दिनों भट्ठु के अन्दर पहली सभा चीफ मिनिस्टर साहब की हुई, तो उसके अन्दर चीफ मिनिस्टर साहब ने जनता से यह वचन किया था कि किसानों पर कोई टैक्स नही लगेगा और सवा छ एकड़ का मालिया भी माफ होगा । ये लफ्ज **चौधरी** देवी लाल के हैं ।

उन्होंने यह भी कहा था कि ये मालायें और ये थैलियां सब बन्द होंगी । यह भी कहा था कि यह हमारे राज के अन्दर नही चलेगी लेकिन ये आज चल रही है ।

चौधरी संत कंवर : चौयरमैन साहब मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । बजट पर बहस चल रही है लेकिन वे चन्दे की बात कर रहे हैं ।

श्री सभापति : यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नही है ।

कामरेड शंकर लाल : चेयरमैन साहब मैं आपके जरिए हाउस मे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि थैलियां बिना रसीद के हरियाणा से इकट्ठी की जा रही हैं चाहे वे कुरक्षेत्र के अन्दर से इकट्ठी की जा रही है, चाहे वे हिसार से की जा रही है, चाहें चुटाला से की जा रही हैं, चाहे रोहतक से की जा रही है । यह बड़ी भारी गलत बात है। बिना रसीद के थैलियां ली जा रही है, यह भ्रष्टाचार नही है तो और क्या है? मैं यह चाहूगा कि जनता पार्टी ने जो आदर्श रखा है वह ठीक तरह से पेश कर रही है या नही । अगर हम जनता के सामने अपने आदर्श नही रख सकेंगें तो आगे बोल नहीं सकते । जनता पांच साल के बाद हमें यहां से फटकार देगी ।

चेयरमैन साहब एक बात मैं यह भी कहना चाहता हू कि सरकर अपने वजीर. लोगों के, चीफ मिनिस्टर साहब के अपने जो निजी खर्चे हैं, सरकारी दौरे हैं, ऐशो–आराम के खर्चे हैं उनको

घटाये, कम करे । हमारे प्रधान मंत्री श्री मुरार जी देसाई ने भी' दिल्ली के अन्दर एलान किया था कि जनता सरकार सादगी पर विश्वास करती है । गांधी जी की यह पार्टी है, श्री जय प्रकाश नारायण जी के आदर्शों पर बनी है, उनके हम लोग शिष्य हैं, उन्होंने भी कुछ नियम रखे हैं जिनसे आज हम लोग दूर हो रहे हैं । यहां से हवाई जहाज सिरस जाता है, पीछे तीन कारे खॉली सिरसा जाती हैं वहां से हवाई जहाज दो दिन' के बाद वापिस चंडीगढ़ आता है, खा नी कारें फिर पीछे आती हैं । यह फिजूल खर्चा है । जनता के बजट के पर बोझा है 'यह जो खर्चा है, इसको समाप्त किया जाना चाहिये । (विध्न) यह जलता पार्टी के खिलाफ है, यह जनता पार्टी के असूलो के खिलाफ है । मै यही कहना चाहता हूं । अगर आप नाराज हैं तो मैं इतना ही कह कर बैठ जाता हूं । मैं आपसे एक बात और कहता हू कि यह टैक्स जन विरोधी हैं हम इसको पास करेंगे । हाथ मेरा भी आपके साथ उठेगा । मैं भी यस. करूंगा । (विघन) जो वाटर टैक्स बढाया गया है यह किसानों के पर बहुत बडा बोझा है । पैसेन्जर टैक्स जो है, आम गरीब लोगों के पर बहुत ज्यादा है । (विध्न)

श्री सभापति : आप दोहरा रहे हैं आप पहले ये बातें बोल चुके है ।

कामरेड शंकर लाल : मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर. जो बड़ी–बडी सैरगाहें बन रही हैं, कौन सी सैरगाह हैं, यह जो अबूब शहर में बन रही हैं, जहां पर बाहर से सैलानी आते हैं,

यह सब फजूल खर्च है । ऐसे खर्चों को बन्द करो । गरीबों के पर टैक्स कम करो । यही मेरी आपसे प्रार्थना है वरना आप लोग भी बदनाम हो जाओगे, आप लोगों को भी जनता माफ नही करेगी जिस तरह से कांग्रेसियों को जनता ने माफ नही किया । मेरे सामने कांग्रेसी लोग बैठे हैं, इनको जनता ने माफ नहीं किया आपको भी जनता माफ नहीं करेगी अगर जनता की आवाज को आप नहीं सुनोगे । गै यही बात कहना चाहता हूं । मैं अपने कांग्रेसी भाइयों से यह कहना चाहता हू कि आप किस बल पर बोल रहे हो? हमें याद है, हरियाणा को याद है. सारे देश को याद है', बंसी लाल का वह जमाना लोगों को भूलता नहीं है । हमारे को याद है, जनता को याद है । तुम्हारी बातों का लोगों पर कोई असर नहीं होता । मेरी बाते मेरी पार्टी को ठीक करने के लिये हैं ताकि मेरी पार्टी सही रास्ते पर चले, मेरी पार्टी जनता की भलाई के लिय' काम शुरू करे । धन्यवाद ।

Mr. Chairman : Shri Mool Chand Jain.

Shri Shamsher Singh : On a Point of Order, Sir. (At this stage several Hon. Members rose to speak.)

Mr. Chairman : If you will speak like this then no body can be heard. Chaudhri Shamsher Singh wants to raise a Point of Order. I would, therefore, request the other Hon. Members to please take their seats.(Interruptions) कोशिश यही हो रही है कि सब – टाईम दिया जाये लेकिन इस तरह टाईम भी आप अपना नही ले रहे हैं और हाउस का सारा टाईम भी इसी

तरह से निकल जाएगा (विघ्न)

श्री शमशेर सिंह : हम 9 आदमियों का जौ एक ग्रुप हैय हमने आज सुबह स्पीकर साहब को और आपको भी दो आदमियों के नाम सिख–कर. दिये हैं..,.

Mr. Chairman : I have received the names of two persons. But you would be allotted time according to the quota of your members.

श्री शमशेर सिंह : वह तो दुरुस्त है । हम यह चाहते हैं कि दो आदमियों को आज टाईम मिल जाए और दो आदमियों को परसों टाईम मिल जाये क्योंकि आज हमारे आदमी....

Mr. Chairman : According to your strength you would get the time.

Shri Shamsher Singh : Two of our members may be given time today...

श्री सभापती : नही इस तरह से नहीं हो सकता ।You areonly one-sixth of the membership on the other side of the House.

Shri Surrender Singh : ***********

Mr . Chairman : Please do not interrupt when there is already a Point of Order. Mr. Surrender Singh, I would ask you not to interrupt. Please take your seat

Shri Surrender Singh : *************

Mr. Chairman : Without my permission you are addressing the House.

श्री सुरेन्द्र सिंह : ..... (विघ्न)

Mr. Chairman : Not without my permission. First you take your seat.

Shri Surrender Singh :

Mr. Chairman : All, whatever Mr. Surrender Singh has uttered, should be expunged.

Shri Surrender Singh : I will sit down. But you should take notice of the Hon. Speaker's Ruling that those Hon. Members who have spo-

ken on the Governor's Address

Mr. Chairman : I have taken notice of every ruling. You first take your seat.

(At this stage Shri Surrender Singh resumed his seat.)

श्री शमशेर सिंह : चेयरमैन साहब, मेरा प्वाएंट आफ आर्डर यह है और मैं आपसे यह मुअदबाना गुजारिश करूंगा हम यह जानते हैं कि हमने जो लिखकर दिया है कि हमारे आदमियों को टाईम मिले, आया आज आप उनको 'टाईम दे सकेगे या नहीं?

श्री सभापती : मैं अभी आपको जवाब देता हूं । देखिये हाउस की स्ट्रैन्थ के हिसाब से टाईम देना पड़ता है । एक तरफ

तो 75 और एक तरफ 1 5, तो आपका जो शेयर बनता है वह आप देख लें । 50 मिनट कल आपने लें लिए हैं । कुछ समय हमारे पोहलू साहब ने लिया है और कुछ समय गंगा राम जी ने लिया है । जो भी आपका शेयर बनेगा, उसके मुताबिक आपका एक स्पीकर बोल सकता है या दो बोल सकते हैं

You would definitely get the time. Babu Mool Gland ji, before you start, I would request you to kindly take as little time as you can. You have already 'spoken several times.

श्री मूल चन्द जैन (समालखा) : चेयरमैन साहब, मैंने तो गवर्नर साहब के एड्रैस पर बोला हूं और न ही बजट पर पहले बोला हूं । इसलिए मैं बजट स्पीच के पर बोलना चाहता हू । आप जितना भी टाईम देंगे, मैं उतना ही लूं गा ।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

डिप्टी स्पीकर साहब, आज बजट के पर बहस हो रही है । बजट किसी भी स्टेट के लिए या किसी सरकार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है । यह महत्वपूर्ण घटना इसलिये है कि बजट से सरकार की नीतियाँ पता लगती हैं तथा खास तौर पर आर्थिक नीतियां पता लगती हैं । अगर वह यूनियन गवर्नमैट का बजट है तो सारे राष्ट्र पर और अगर किसी प्रान्त का बजट है तो उस प्रान्त के लोगों पर बजट का असर पड़ता है और लोग यह देखते हैं कि हमारी दशा और सुधारी जा रही है या हमारे पर कुछ और ज्यादा बोझा डाला जा रहा है । बजट को परखने के

लिए कुछ कसौटियां हैं, उन कसौटियों पर अगर हम इस बजट को परखें तो मैं समझता हूं कि हम इससे लोगों की हालत को कुछ सुधारने में, उसको इम्प्रूवमैट करने में कुछ योगदान देंगे ।

मेरी नाकिस राय में बजट को परखने की पहली कसौटी तो यह है कि आया इस बजट से हमारे प्रान्त की पैदावार को, हमारे प्रान्त की धन सम्पत्ति को बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा या नुकसान होगा । दूसरी कसौटी यह है कि आया यह बजट प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है या यह बजट रिएक्शनरी है, प्रतिक्रियावादी है, पीछे की ओर ले जाने वाला है । एक कसौटी और है आया इस बजट में उन गरीब लोगों, उन कमजोर तथा पिछड़े हुए लोगों की तरक्की के लिए, माली हालत सुधारने के लिए कुछ रुपया रखा गया है । एक और कसौटी है कि पिछली सरकार की जो गलत नीतियां थीं, उस सरकार की गलत आर्थिक नीतियां थीं, गलत पालिसीज थी उनको सुधारने के लिए क्या बजट में खासतौर पर बदली हुई सरकार की गल्त नीतियों को सुधारने की कोशिश की गई है या नही । एक और कसौटी है और वह यह है कि आया मुखतलिफ मदों के लिए जो यह सरकार रुपया मांग रही है क्या उस रुपए का खर्चा स्टेट के मुखतलिफ हिस्सो के लिए न्यायपूर्ण. रखा गया है या पहली कांग्रेसी सरकार की तरह बन्दरबांट की गई कुए । उपाध्यक्ष महोदय, यह कुछ कसौटिया बजट को परखने की हैं । मैं समझता हूं कि अगर हमारे कांग्रेस (आई) के नेता श्री शमशेर सिंह इन कसौटियों को

सामने रखते हुए कुछ बाते कहते तो अच्छा रहता । मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारी स्टेट तथा देश के सामने बेरोजगारी की बहुत गम्भीर समस्या है । इस देश में करोड़ों लोग गरीबी के स्तर से भी नीचे रहते हैं और यह आर्थिक 0ंच और नीच की खाई बढ्ती ही जाती है। । पिछले साल के मुकाबले 12 प्रतिशत पढ़े लिए नौजबानों के नाम आज बेरोजगारी के रजिस्टरों में ज्यादा हैं और अन्दाजा यह है कि चार करोड़ के करीब बेरोजगार हमारे देश में बैठे हैं और कल शायद किसी माननीय सदस्य ने हरियाणा के आंकड़े भी बताए थे और यह तब है जब रजिस्टर में बहुत कम नोजवानो अपना नाम लिखवाते है । क्या उन सारी समस्याओं को हल करने के बारे में हमें इस बजट में कोई झलक मिलती है या नहीं यह देखने वाली बात है । जैसे मैने पहले कहा कि अगर काग्रेंस (आई) के नेता इस चीज पर विचार करते और खासतौर पर इस बात का ध्यान रखते कि जो बजट है वह कोई क्लीन स्लेट पर नहीं लिखा जाता और न हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ने इसको क्लीन स्लेट पर लिखा है । जो चीज हमें पिछली सरकार से विरासत में मिंत्री है वह ठीक है या नही है यह बात श्री शमशेर सिंह जी को सामने रखनी चाहिए थी । कही कोई ऐसी चीज तो हमें विरासत में नहीं मिंत्री, कोई भूरे हाथी तो श्री वैसी लाल या गुप्ता जी जो चीफ मिनिस्टर थे, नही बांध गए । कहीं ऐसा तो नही है कि वह कांग्रेसी सरकार कोई भूरे हाथी बांध गई हो और उन भूरे हाथियों को यह सरकार भुगत रही हो और उनसे हमारी स्टेट को कोई फायदा न हो रहा हो और इसी कारण

इस सरकार को टैक्स लगाने पड़ रहे हों,? इस बारे में मैं हरक–दों उदाहरण दूंगा । मिसाल. के तौर पर लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम है । डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने जो आंकडे दिए हैं उनके मुताबिक 84 करोड़ रुपया तो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पर खर्च हो चुका हए और आठ करोड़ रुपया पानी को पर ले जाने के लिए यानी पम्प लगाने पर खर्व किए । इस प्रकार 92 करोड़ रुपया खर्च हो गया और फायदा क्या हुआ, इसके बारे में आज ही एक सवाल के जवाब में पता लगा है । इस बजट में भी जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पर साढ़े बारह करोड़ रुपया रखा गया है । इन स्कीमों से फायदा क्या हुआ वह आप देख लीजिए । 197 4–7 5 में सावनी की फसल में सात हजार हैक्टेयर रक्बे की सिंचाई हुई । एक हैक्टेयर में अढ़ाई किल्ले होते है । इसका मतलब' यह है कि सोलह–सत्रह हजार एकड़ जमीन में खरीफ बोयी गयी और ज्यादातर बाजरा बोया गया । मैं तो समझता हू कि जो छोटी मोटी बारिश हुई उसके कोरता बाजरा बोया गया । सिंचाई का तो बहाना लिया गया है । वह तो बारिश से पैदा हो गया । आषाढ़ी की फसल के लिए 1 5, 499 हैक्टेयर रक्बा सैराब हुआ और उससे 7, 45 4 टन अनाज पैदा हुआ और इस अनाज में ज्यादातर चना है । उस इलाके में अगर थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो चना काफी पैदा हो जाता है । 197 5–7 8 में सावनी की फसल 7, 107 हैक्टेयर में सिंचाई की गई और अषाढी की फसल के लिए 21,153 हैक्टेयर में सिंचाई की गई । 1978–77 में सावनी की फसल के लिए 5, 177 हैक्टेयर मैं सिंचाई

की गई और आषाढ़ी की फसल के लिए 2 1, 610 हेक्टेयर में सिंचाई की गई । सावनी की फसल मैं ज्यादातर बाजरा बोया गया और आषाढ़ी की फसल में ज्यादातर चना बोया गया । उपाध्यक्ष– महोदय, 92 करोड़ रुपए लगाकर यह मामूली फायदा हुआ है इसके मुकाबले में तो अगर इस रुपए को वहां पर सबसिडी के तौर पर किसानों को या वहां लोगों को देते या कोई ट्रस्ट बनाकर वहाँके लोगों के बच्चों को' –वजीफे देते या वहां पर कोई स्माल स्केल इंडस्ट्री चलाते तो बहुत फायदा हो सकता था । इन स्कीमों का यह नतीजा हुआ कि सन् 1975 में हरियाणा के किसानों पर अढाई गुणा से लेकर पांच गुणा तक आबियाना बढ़ाया गया । यह 1975 में हुआ कांग्रेसी सरकार के जमाने में । गन्ने की फसल पर अढ़ाई गुणा से ज्यादा हुआ और चने की फसल पर भी बढ़ाया गया । मेरे पास सब कुछ त्रिखा हुआ है लेकिन टाईम थोड़ा है, हे तफसील में नही जाना चाहता । लेकिन मोटे तौर पर कह सकता हूं कि अढ़ाईगुणा से लेकर पांच गुणा तक काग्रेसी सरकार ने आबियाना बढ़ाया और यह भूरा हाथी हमारे जिम्मे बन्ध गया । इसके कारण हमारे सिंचाई विभाग के जो वर्किंग ऐक्पेन्सिज थे वे पूरे नही होते क्योकि जो पूंजी लगती है उसका ब्याज चाहिए, जो मैन्टीनेन्स है, जो सरकारी कर्मचारी है उनकी तनखाह चाहिए । इम तरह सन् 1974 में आठ करोड़ सालाना का घाटा था और उसके बाद यह अढाई गुणा से चार या पाच गुणा टैक्स लगा । लेकिन फिर भी घाटा रहा और उसका नतीजा यह हुआ कि सिंचाई विभाग के घाटे को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने

दस प्रतिशत आबियाना बढ़ाने का ऐलान किया । मैं यह चाहता हूं और इसमे कोई सेन्टीमेन्ट की बात नही है । हमारी सरकार को इस बात को ठंडे दिल से और बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जिसकी लागत 108 करोड़ रुपए हो जाएगी और अगले साल यह लागत और अधिक हो जाएगी उससे फायदा कितना होता है । अभी तक ज्यादा से ज्यादा 21, 610 हैक्टेयर रक्बे की सिंचाई हुई है । इतने थोड़े रक्बे की सैराबी के लिए इतने करोडु रुपए की लागत आ जाए और उस पर दस– बारह करोड़ रुपए सालाना का खर्चा हो यह कोई उचित बात नहीं है । यह सोचना पड़ेगा कि क्या यह रैकलैस ऐक्सपेन्डीचर हुआ है । क्या हम इसरेक्लैस ऐक्सपेन्डीचर को जारी रखे । यही खर्चा है जो भाखडा की कैनाल है, जो वैस्टर्न जमुना कैनाल– है, जो सरकारी ट्यूबवैल से इरिगेशन होती है इन सब में शामिल करके इतना बड़ा खर्च बढ़ जाता है कि जिसके कारण यह दस प्रतिशत आबियाना बढ़ाया गया । मैं इस दस प्रतिशत आबियाना को पसन्द नहीं करता और (व्यवधान) मैं इसका विरोध करता हू । मैं इरि– गेशन मन्त्री से यह कहना चाहता हूं कि वे कम से कम जब मैं कोई बात कहूं तो कोई मजाक न समझे हो सकता है कि मैं कोई गलत बात कह द् लेकिन मैं नेकनियती से हरियाणा के फायदे के लिए और सारे देश के फायदे के लिए सोचता हूं और यह सेन्टीमेंट की बात नही है । आपको सोचना है कि 106 करोड़ रुपए लगाकर आपको कितना फायदा होता है । मुझे भिवानी के लोगो से या जहां लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, पांच सौ फुट पर

पानी ले गए हैं, मुझे उनसे किसी किस्म की चिढ़ नहीं है । मैं तो चाहता हू कि उनके खेत सैराब हों लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि आपका जो खर्चा हो वह रैकलैस न हो । वह ऐसा होना चाहिए जैसे कि एक व्यवहारी आदमी का होता है । उस खर्चे की वजह से स्टेट के लोग इतना न भुगते जितना वह भुगत रहे है । इसी बजट में सरकार एक और बात करं रही है । शायद वह पिछली सरकार की पैरवी करने की कोशिश कर रही है एक स्कीम बनाई है कि हम पानी छिडकेंगे, 0ंचे 0ंचे टीलों पर और उसके लिये 100 स्प्रिंक्लर्ज मंगवाये हैं । मुझे तो डिप्टी स्पीकर साहब यह स्कीम भी रंकलैंस ही मालूम होती है जैसी कि यह लिफट इरीगेशन की स्कीम है ।

12.00 बजे

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल) : आप को पता नही ।

श्री मूल चन्द जैन : ही ठीक है जैसे बंसीलाल को पता था और बाकियों को पता नहीं था वैसे मुझे मालूम होता है कि आपको मालूम है, हमें मालूम नहीं है । मैं यह चाहता हू कि हमारी सरकार इन स्कीमों पर ठण्डे दिल से विचार करे । आखिर यह जो बजट है यह सारा स्टेट का फण्ड है, यह किसी की जाति जागीर नही है, यह किसी एक की प्रापर्टी तो नही है । यह जो कंसोलीडेटिड फण्ड है यह लोगों के सांझे फायदे के लिये खर्व होना चाहिये । अगर लोग किसी भी क्षेत्र ये बैठे हुये हैं तो उनकी

हर तरह से मदद की जाए, उनको मदद की जरूरत है लेकिन यह मदद इस ढंग से की जाये जिससे कि उसको फिजूल खर्ची न कही जा सके । तो मैं कह रहा था कि हमारी जनता पार्टी की सरकार को विरासत में यह स्कीमें मिंत्री हैं जिमके कारण आज हम भुगत रहे है और फिर उन स्कीमों को चालू करने की भी कोशिश की जा रही है इसलिये इन स्कीमों के बारे में सरकार ठण्डे दिल से सोचे ।

इमरी मिसाल मैं देना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने हरियाणा भवन दिल्ली में बनाया, इतनी बड़ी बिलडिंग है पर उसमें ऐकोमोडेशन नहीं मिलती और दिल्ली मै बड़े– बड़े होटल भी खुले हुयें हैं । मैं समझता था कि यह भी एक तरह से होटल खुला होगा और इससे सरकार को बडी आमदनी होनी चाहिए पर पता चला कि 37 लाख रुपये हरियाणा भवन बनने के पर खर्च आया । यह **चौधरी** शमशेर सिंह की मोतियों वाली सरकार का काम था । 37 लाख रुपये के खर्चे के बाद क्या हुआ कि आये साल उस हरियाणा भवन की मेन्टीनेन्स के कारण उस के पर 5–4 लाख रुपये का घाटा शुरू हो गया । 1 972–73 में साढ़े चार लाख रुपये, 197 4–7 5 मे साढ़े चार लाख, 197 5–7 6 में 5 लाख और 1 976–7 7 में पौने सात लाख रुपये का घाटा दिखाया 'गया है । और दूसरी तरफ गरीब किसानों पर, यात्रियों पर टैक्स का बोझा लादा जा रहा हए । यात्रियों पर टैक्स लगाया जा पा है जबकि पहले ही दोहरा किराया है 50 परसेन्ट यात्री टैक्स और

उस पर 10 परसेन्ट' और टैक्स लगेगा । और यहां क्य किसी मेरे दोस्त ने कहं दिया कि अमीर आदमी तो कारों में सफर केरते हैं पर छोटे किसान बसों मे सफर करसे हैंय एक तरफ तो गरीब लोगों पर टैक्स बढ़ाएं और दूसरी तरफ आप देखें कि हरियाणा भवन– में कौन ठहरते हैं, एम. एल एज, सरकारी– कर्मचारी और उसका किराया है दो रुपये 4 रुपये । इसमें सरकार का कसूर वही है कसूर तो पिछली सरकार का है लेकिन दुख की बात है कि हमारी सरकार उस गलती को बराबर जारी रखे हुये है । अगर 5–6 आध रुपये का सालाना खर्व पड़े तो उस हरियाणा भवन को चालू रख्ने का कोई फायदा नही है । यह तो मैंने आपको घाटा बताया है मेनटीनेन्स का अगर उस 37 ला ख के खर्चे का व्याज जोड़ा जाए तो घाटा और भी बढ़ जाएगा ।

चौधरी देवी लाल :. सुझाव भी दो कोई ।

श्री मूल चन्द जैन : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको बताता' हूं कि पिछली सरकार ने रैस्ट हाउसिज बना दिये, आलीशन फर्नीचर वहा लगा दिया....

श्री उपाध्यक्ष : जैन साहब जरा टाइम का भी ध्यान रखें ।

श्री मूल' चन्द जैन : तो डिप्टी स्पीकर साहब, अगर यह चीज हमारे बजट ने...

चौधरी देवी लाल : सुझाव भी दे रहे हो कोई?

श्री मूल चन्द जैन : सुझाव भी साथ साथ दे रहा है । चलो आप एक बिजली बोर्ड को ही पहले ले लीजिये, उसमें जितनी पिछली सरकार ने गडबड़ की है और अगर उस की गहराई में जाएं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है । मैं यह नहीं समझता कि **चौधरी** शमशेर सिंह अपनी पिछली सरकार की गलती को क्यों नही मानते, वह तो अब उस अपनी पार्टी की रहनुमाई करते हैं जिस पार्टी की सरकार पहले यहां काम कर गयी है । बिजली बोर्ड का क्या हाल है उसकी एक–एक संपत्ति गिरवी पड़ी हुई है, पावर हाउस गिरवी है, बोर्ड की सारी मशीनरी गिरवी पड़ी हुई है, उसका बाल बाल गिरवी है, यहां तक कि सरकारी कर्मचारी जो है उनको तनख्वाहें भी नहीं दे सके, जब हम जेल में थे तो सुना करते थे कि बिजली बोर्ड के पर बहुत कर्जा है । दुकानदारों पर ट्यूबवैल्ज वालों पर, व्यापारियों पर दबाव डाला जा रहा था कि 5 हजार 10 हजार बिजली बोर्ड के लिये कर्जा दो । जब बोर्ड का इन कर्जों से भी काम न चला तो स्टेट गवर्नमैंट उसकी जामिन बनी' । अरबों रुपया स्टेट गवर्नमैंट की जमानत पर स्टेट बिजली बोर्ड को दिया गया । और इस बजट में जिकर किया कि एक करोड़ 40 लाख रुपया वह है जो हरियाणा सरकार को बिजली बोर्ड ने सूद के रूप में वापिस करना था । उस रुपये को बिजली बोर्ड वापिस नहीं कर सका । जो कांग्रेस सरकार के जमाने ये घाटे में जा रहा था, वह बोर्ड आज. भी घाटे में जा रहा है । मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब और फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से यह कहूंगा कि मुझे खुशी है कि इस हाउस में एक पब्लिक

अन्डर टेकिंग को संभालने के बारे में एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है, वह स्टेडिग कमेटी है वह सरकर को सुझाव दे जिससे घाटे की अन्डर टेकिंग जो है वह मुनाफा की बन सके, और बिजली बोर्ड को खासतौर पर देखा जाए । इसके साथ साथ मैं क्हूंगा कि बहुत सी ऐसी बाते हैं जोकि पिछली सरकार ने की हैं और लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ 'है, अगर उनको गिनाने लगू तो डिप्टी स्पीकर साहब, आपने रमलूं की कहानी सुनी होगी'' । भाई कहा

कहा काग्रेस सरकार की करतूतों को रोएं जैसा कि उसने जूडिशिथरी के साथ बदसलूकी? की उसके बारे. में यहां हाउस में सिकर आया, मारकीटिग कमेटियों के चुनाव कराने की बजाये नामजदकी की गयी । उसको अब हम ठीक करने जा रहे हैं । और भी बहुत गलितयां हैं और वह गल्लियां ऐसी हैं जो दीवार पर लिखी नजर आती 'हैं, उनको दूर करने में आप देरी न करे । उनको टूर करने में अगर आपको हमारा सहयोग चाहिये तो हमारा सहयोग मद। वी आपके साथ रहेगा । आप हमें आवाज देंगे तो हम दौड़ कर आपके पास आएंगे । लेकिन अगर आपै उन गल्लियों को दूर करने में देरी करेंगे तो मुझे भी जैसा कि लोग कहते जैं उनकी ताईद करनी पड़ेगी । जैसे मैंने अभी कहा कि हमारी सरकार ने बहुत सी पुरानी गल्तियों को ठीक किया लेकिन इसके साथ साथ कई गल्तियां जो कांग्रेस सरकार ने की थी उन्हें हमारी सरकार दुहरा रही है । **चौधरी** –शमशेर सिंह जी ने जो बाते कहीं

मैं यह नहीं कहता कि सब गलत है बल्कि उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी सरकार अब भी कर रही है । गलितयों के कारण कांग्रेस सरकार को नुकसान पहुंचा था और अगर हमारी सरकार ने भी उन गलितयों को जारी रखा तो इसको भी नुकसान पहुंच सकता है । मिसाल के तौर पर उन गलितयों में एक गलती तो यह है कि विधायकों को जो कार्पोरेशंज का चेयरमैन बनाया जाता है यह बिल्कुल गलत बात है । इसी तरह से इम्प्रूवमैंट ट्रस्टम पहली सरकार ने नामिनेट किये थे और हमारी सरकार ने भी कर दिये है । फिर जो नामिनेट किये हैं उनमें भी किसी हरिजन को, किसी माइनारिटी तबके को या बैकवर्ड क्लास को कोई नुमायदगी नहीं दी गई । ऐसी बाते करने से जनता पार्टी का इमेज लोगों में खराब होता है । इसी तरह से स्माल सेविंग और चन्दे इकट्ठे करने को बात है । मुझे याद है कि हमारी पार्टी के नेता ने यह एलान किया था कि हम सरकारी कर्मचारियो द्वारा चन्दा इकट्ठा नहीं करवाएंगे लेकिन मुझे भी पता है और लोगों को भी पता है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा चन्दा इकट्ठा होना शुरू हो गया है । तो यह बात ठीक नहीं है । मैं यह चाहूंगा कि पार्टी के आदमी खुद चन्दा इकट्ठा करें । इसी बहाने वे लोगों के पास भी जा सकेगे और उनकी तकलीफों को सुन सकेंगे तथा लोगों का गिला शिकवा भी एम. एल.एज. के सामने आएगा । इसलिये हमारी सरकार को इस तरफ– भी ध्यान देना चाहिये । इसके बाद कोयले के स्कैडल की जो बात थी वह आपके सामने है । पुरानी सरकार के कोयले के स्कैडल की 'जांच हो रही है लेकिन वह तस्वीर

हमारे सामने नही है कि वह किस स्टेज पर है । अभी हाउस मैं ईंटों की मंहगाई के बारे में सवाल आया । हमारी सरकार ने ईटों पर से कन्ट्रोल हटा लिया है और उससे एक दम 3 0— 40 रुपये प्रति हजार ईटों की कीमतें बढ़ गई । इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है? इसकी तस्वीर भी हमारे सामने नहीं आई । इसके अलावा सरकार ने कोयला कन्ट्रोल आर्डर लागू किया और कुछ एजेंटस कोयला सप्लाई करने के लिये मुकर्रर किये । वे एजेटंस कलकत्ते में बैठे हैं और कोयला भेजो। में कोई दिलचस्पी नही ले रहे हैं । इसका नतीजा यी हुआ 'है कि आज कोयले का कन्ट्रोल भाव जहां 200 रुपये टन है. वहां भट्ठे वालों को 400 रुपये टन कोयला मिल रहा है । इस मामले में सरकर को तुरन्त ध्यान देना चाहिये ।

इसी तरीके का एक और चावल की पालिश का आर्डर है । इस पालिश पर और किसी भी स्टेट में कन्ट्रोल वहीं है 'लेकिन हमारे यहां' पता' नहीं क्यों 'लगाया गया है । हमारी स्टेट ' में वह पालिश 30 हजार टन पैदा होता है लेकिन मुर्गीखाने वालों की जरूरत का यहा कोई रिकार्ड 'नही है क्योंकि यह पालिश मुर्गीखाने वालों के काम भी आती है इसील्ये इसका भी पता लगाना चाहिये था कि उनकी खपत कितना है । लेकिन मुझे पता चला है कि मुर्गीखाने वालों की दो हजार टन से ज्यादा जरूरत नहीं है । इसके साथ ही मैं बता 'दूं कि उबले हुए चावल की. पालिश की कीमत 100 रुपये क्विंटल के हिसाब से थी और

दूसरे' चावल की पालिश की कीमत 80 रुपये के हिसाब से थी । तो पता ही 35 रुपये– के हिसाब' सें करने का किस अफसरं का ध्यान चला गया । इस पर कन्ट्रोल करने का नतीजा यह हुआ कि मुर्गीखाने वाले अपनी जरूरत से कही ज्यादा पालिश खरीद क्र उसे ब्लैक में बेचने लग गये । मैं पूछना चाहता हूं कि जब जीरी पर कोई पाबन्दी नही है और उसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाया जा सकता है तो इस पालिश पर कन्ट्रोल के क्या मायने हैं? इस से किसान को भी हानि होगी किसान किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है इसी–लये हमें उसकी. भलाई के लिये सोचना चाहिये । अगर खुशहाल खुशहाल है तो वकील भी खुशहाल होगा, दुकानदार भी खुशहाल होगा, डाक्टर भी' खुशहाल होगा, लेबर करने वाला मजदूर भी खुशहाल होगा, यानी सभी खुशहाल होंगे । लेविन इस पालिश के कन्ट्रोल आर्डर को देखते हुए व्यापारियों ने जीरी कन्ट्रोल कीमत से फालतू खरीदनी बन्द कर दी हैं क्योंकि उन्होंने सोचा कि सरकार का कोई भरोसा नहीं किं किस टाईम किसी चीज का कन्ट्रोल करके उसके भाव घटा दे और उन्हें घाटा उठाना पड़े । यह जो आर्डर लागू किया गया है इससे किसानों को बहुत नुकसान होगा क्योकि इस साल पालिश की कीमत कम हो गई है, तो अगरने साल व्यापारी ज्यादा कीमत पर माल. नही खरीदेंगे । तो डिप्टी स्पीकर साहब, इस तरह से यह सरकार खेती क्रने वालों के फायदे की बातें कर रही है । अब आखिर में दो तीन बातें रह गई है इनको क्ह कर मैं बैठ जा0ंगा । पहली बात तो यह है कि हमारी स्टेट में जो गरीब से गरीब

लोग बसते हैं उनके लिये इस बजट में क्या किया गया हैं? प्लानिंग बोर्ड में इस मामले पर काफी चर्चा हुई थी । यह बात ठीक है कि अगर खेती करने वाले की माली हालत अच्छे' होती है तो उससे देहात में बसने वाले सभी लोगों को कुछ न कुछ फायदा होता हैं स लेकिन आज बेजमीन किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है । अगर हम ऐसे किसान. की. हालत सुधारना चाहते हैं तो इसके लिये जरूरी है कि इलैक्शन के टाइम पर जो हमने मैनिफैस्टो रखा था या जनता पार्टी की जो आर्थिक पालिसी थी उस पर गौर करे । उसमे कहा गया था कि खेती के लिये खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा । मैं चीफ. मिनिस्टर साहब, तथा फाइनैसं मिनिस्टर साहब का ध्यान खास तौर पर दिलाना चाहता हूं कि उसमें जहां यह भी कहा गया है कि सैट्रल बजट में कम से कम 40 प्रतिशत खेती के लिये दिया जाए, वहां साथ यह भी कहा है कि गरीब आदमियों को घरेलू दस्तकारी चलाने कें लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया रखा जाए । उन्होंने जूता, साबुन तथा कपड़े का नाम खास तौर पर लिया है जिमको किं आम आदमी रोजे इस्तेमाल करता हैं । उन्होने कहा है कि इन चीजों कौ बड़े कारखानों से निकाल कर छोटे दस्तकारों द्वारा बनाया जाए लेकिन इस बजट में इस चीज कीतरफ भी कोई इशारा नहीं है । मैं सरकार से पुरजोर ' अनुरोध करूंगा किं वह इस ओर ध्यान दे । हरियाणा प्लानिंग बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया था कि एक करोड़ रुपया इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट कों फालतू दिया जाए ताकि वहं सारे का सारी रुपया खादी बोर्ड हरियाणा को मिले और

खादी बोर्ड वह पैसा छोटे दस्तकारों जैसे लुहारों को, कुम्हारों को तथा और बैकवर्ड क्लासिज के छोटे–छोटे दस्ताकारों को बांटे । किसी वक्त ये गरीब लोग अपने पैरों पर खड़े थे और अपना गुजारा करते थे लेकिन इव मशीन के युग ने उनको बेकार कर दिया है इसलिये उनकी सहायता करना बहुत ही जरूरी है । लेकिन एक करोड़ की रकम जो हरियाणा के प्लानिंग बोर्ड ने मंजूर की थी वह आगे मंजूर नही हुई । 217 करोड़ रुपये का प्लान बनाया गया था लेकिन उसमें से 210 करोड़ रुपये का प्लान मंजूर हुआ है । तो मै कहना चाहता हू कि यह जो कटौती हुई है वह गरीब आदमियों के भले के कामों के बजट पर ही क्यों हुई है? डिप्टी स्पीकर साहब, समय कम है वरना मैं बता सकता था कि 210 करोड़ रु पये में से कहा कहां पर खर्च करने की जरूरत नहीं थी । हमारी स्टेट में उन लोगों की 30 प्रतिशत आबादी है जिनको गरीब तपा गरीबी की लाइन से नीचे कहा जा सकता है लेकिन उनके 'लिये पिछले साल के बजट के मुकाबिले में कोई ज्यादा पैसा नहीरू रखा गया है । जहां तक इंडस्ट्रीज डिपार्ट– मैं–प्र का ताल्लुक है इसके लिये पांच वर्षीय योजना में जितना रुपया रखा गया था वह मारा रुपया खर्च नहीं किया गया है । इसलिये अगर यह एक करोड़ रुपया जो प्लानिंग बोर्ड ने मंजूर किया था इसको भी खर्च में शामिल कर लेते तो भी यह खर्चा पूरा नहीं बनता था । इसलिये अच्छा होता अगर उस खर्चे को भी शामिल कर लिया जाता । मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि वह इस तरफ खास तौर पर ध्यान दे । अब मैं आखरी बात

जोकि ट्रेडर्ज के बारे में है कहना चाहता हूं । हमारी सरकार ने इस बजट में एक कदम उठाया कि सरचार्ज 15 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया । इससे कुछ रिलीफ, कुछ फायदा लोगों को होगा । हमारी जो बार्डर एरिए की मंडियां हैं, उनका एक मुतालबा था, उनकी कुछ डिमाड्ज थी उनको गवर्नमैंट ने मान लिया है । मार्केट कमेटियों की जो फीस बढ़ाई थी दो से तीन परसेंट उसको कब कम किया जावे । डिप्टी स्पीकर साहब, कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं । मेरा इस मामले में जोर रहा है, पहले भी जोर देता रहा हूं कि सरकार अगर किसी सैक्शन पर टैक्स लगाए तो वह टैक्स पड़ौसी स्टेट के इला कों से ज्यादा नहीं होना चाहिए । अगर यहां बिक्री टैक्स ज्यादा होगा तो इसका नतीजा यह होगा कि दिल्ली के मुकाबले में, राजस्थान के मुकाबले में, पंजाब केमुकाबले में इन सरहदी मण्डियों में व्यापार नही रहेगा । अगर चीफ मिनिस्टर साहब इसका नतीजा देखना चाहे तो सोनीपत की मंडी की हालत देख ले और दूसरी जो सरहदी मण्डियां हैं उनको देख लें । यहां की टेरड पड़ौसी स्टेट्स की मण्डियों में चली गई है । जो. ट्रेडर्ज की मांगें थीं, सुझाव थे उन पर सरकार ने अमल किया है, लेकिन एक सुझावरू पर अमल नही हुआ है । श्री गंगा राम ने सुझाव दिया है उस पर गौर करें । मैं सारी चीज को दोहराना नही चाहता । फरीदाबाद में कारखाने लगे हुए हैं, जिस जमीन पर वे कारखाने लगे हैं वह जमीन हमारी है, कच्चा माल हमारा है, बिजली की हम उनको सहूलियत देते हैं,. लेकिन उन कारखाने– दारों ने अपने हैड–आफिसिज दिल्ली में

बनाए हुए हैं । उनका बिक्री टैक्स बाहर जाता है या वे हड़प कर जाते हैं । बिक्री टैक्स भी हरियाणा के पास नहीं आता । जब हरियाणा में कारखाना है तो सेल्ज टैक्स हरियाणा को मिलना चाहिए । हरियाणा की जमीन एक्वायर हो और उस जमीन पर कारखाने माल पैदा करें । उस माल की बिक्री हो और जो बिक्री टैक्स आता है उनका हम फायदा न उठाएं तो कितनी बुरी बात है। मैं सरकार को बहुत कंक्रीट सुझाव दे सकता हूं पर मोटी–मोटी बातें कर सकता हूं क्योंकि समय कम है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने शराब पर टैक्स बढ़ाया है और आबियाने पर टैक्स बढ़ाकर एक करोड़ रुपया लेना चाहती है । क्यों न शराब पर और ज्यादा टैक्स लगा देते । इससे पैना ज्यादा .आ जाएगा और आबियाने पर टैक्स लगाने से पिंड छटेगा । जो गांधी जी की नीति रही है, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि देश में नशाबन्दी लागू हो, उस नीति को क्यो नही अपनाते । इसलिए शराब पर टैक्स और ज्यादा बढा दे । मै यह भी कहना चाहूंगा कि नशाबन्दी के मामले में इस बजट में कोई इशारा नही मिलता कि हमारी सरकार नशाबन्दी की ओर बढ़ रही है । पिछले साल 24.6 करोड रुपये शराब से आमदनी हुई थी और इस साल 26 करोड़ की आमदनी दिखाई है । इस साल और भी बढ़ गई । यह कैसे बढ़ेगी, क्या सरकार ठेके के नीलाम करेगी? जैसे कि सरकार की योजना है सारे देश में नशाबन्दी लागू हो जाए, इसके लिए जरूरी हैं कि सरकार मुअस्वर कदम, कोई प्रभावशाली कदम

उठाए जिससे नशाबन्दी लागू हो । शराब के नुक्सान क्या है, मुझे इस में जाने की जरूरत नहीं, सब लोग जानते है कि किम तरह से लोग लुटते हैं, किस तरह कुनबे पिछड़ने हए, किम तरह से पैसा बरबाद करते है, ये सारी' नियामते शराब की है । डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने खासा समय लिया है । इन शब्दो के साथ मैं आपका आभारी हूं और अन्त में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आखिरी बात करना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : समय तो आपका पूरा हो चुका .हंऐं ।

श्री मूल चन्द जैन : मैं एडमिनिस्ट्रेशन– का जिक्र करना चाहता हूं, थोड़ा ही टाईम लूंगा । श्री गंगा राम ने इसका जिक्र किया है, इससे पहले भी कई मैम्बर बोल चुके हैं । एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एक नाजुक मशीनरी है । कोई भी सरकार, कोई भी एम. एल. ए. अगर इसको गलत तरीके से छेडेगा तो यह मशीनरी डैमेज हो जाएगी । इतनी डैमेज हो जाएगी कि उसका असर, उसकी प्रतिक्रिया उस पार्टी पर पड़ेगी, उस सरकार पर पड़ेगी जो इसके माथ गलत व्यवहार कर रही है । मैं दुर्व्यवहार की मिसालें नही देना चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा किं इम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में देहातों के कितने लोग हैं? बहुत कम हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है । हमारी हिस्ट्री बताती है कि पहले देहातों के लोग पढ़ते ही नहीं थे, फिर कर. एल. बी. आई. ए. एस. कौन बने? इस वक्त यह एक हकीकत है कि जो आई. ए. एम. और एच. सी. एस. लोग हैं ये हमारी स्टेट की क्रीम

हैं । ये लोग पढ़ाई के क्षेत्र में आगे हैं और कम्पीटीशन –से. आई. ए. एस. बनकर आए हैं और ये देश की क्रीम होते हैं, इनका नाजुक स्वभाव होता हैं । इनको रफ्ली टूटि न करें जैसे जूनियर को सीनियर कर दिया और सीनियर को जूनियर कर दिया । अगर आप एंप्वायंटमैंट' करतै वक्त, ट्रांसफर करते वक्त ऐसा करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं चलेगा । हमारी सरकार इस तरीके से नाजुक मशीनरी से गलत व्यवहार करेगा तो स्टेट का काम ठीक नहीं चलेगा.... (व्यवधान) मेरे नौजवान साथियों को अभी बहुत कुछ सीखना है..... (व्यवधान) ।

श्री दीप चन्द भाटिया : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । श्री मूल चन्द जैन जी को रोन एक घंटा, दो घंटे टाईम मिलता. है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब मैम्बरों को टाईम मिलना चाहिए (. व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैन : इसके इलावा डिप्टी स्पीकर साहब, पिछली सरकार के जो गलत कारनामे चल रहे थे, उन में से कुछ को हमारी सरकार ने ठीक किया है । कुछ पौलिसीज ऐसी थीं जैसे पुलिस के एसपी. की कान्फिडैंशियल रिपोर्ट डीसी. लिखता था लेकिन अब वह रिपोर्ट पुलिस के अधिकारी डीआईजी. वगैरा लिखते हैं और यह सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है । इसी तरीके से दूसरे महकमें हैं, इंजीनियरिंग का महकमा है । और इंजीनियर की रिपोर्ट डीसी. लिखे तो आप बताए कि डीसी. को इंजीनियरिंग का क्या पता है (व्यवधान) इंजीनियर की रिपोर्ट एस.

ई. लिखे तो ठीक रहेगा । डिप्टी स्पीकर साहब, सरकारी मशीनरी अगर ठीक तरीके से काम नहीं करेगी तो यह सारा बजट धरे का धरा रह जाएगा..... श्री उपाध्यक्ष रू इसकी चर्चा तो कर चुके हैं आप!

श्री मूल चन्द जैन : इसी तरीके से पिछली सरकार ने किया कि टैक्नीकल डिपार्ट– मैंट्स जैसे मैडीकल डिपार्टमैंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमैंट इनका एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर एच.सी.एस. आफिसर को लगा दिया । कितने अफसोस की बात हए कि इंजीनियरिंग डिपार्ट– मैंट के कर्मचारियों की ट्रांसफर और मैडिकल डिपार्टमैंट के कर्मचारियों की ट्रांसफर पर एच सी.एस. अफसरों का कंट्रोल है, यह बिल्कुल गलत बात है । हमारी सरकारी मशीनरी के साथ, पिछली सरकार ने जो अन्याय किया है, वह अन्याय अब भी किसी हद तक जारी है और इस अन्याय को बन्द करें.....

चौधरी गंगा राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर । मेरी आपसे प्रार्थना है कि हाउस के अन्दर बजट पर बहस होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी की, सुपरक्रेसी की बात यहां नही. होनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, मैम्बर साहिबान इस बात का ध्यान रखे ।

श्री मूल चन्द जैन : सरकारी मशीनरी ठीक काम करे तो बजट ठीक– इस्तेमाल. होगा इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने समय दिया।

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)

चौधरी संत कंवर : डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत से मैम्बर बोलना चाहते है, इसलिए समय बढा दिया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : अपि बैठिए । हाउस की सैंस देखते हए कोई मैम्बर 15 मिनट से अधिक समय न ले । (व्यवधान)

बहिर्गमन

श्री शमशेर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे 9 मैम्बरान में से कोई भी मैम्बर आन नहीं बोला । मैंने सुबह भी स्पीकर साहब को एक चिट भेजी थी कि कम से कम हमारे दो आदमियों को ओज बोलने का टाईम दिया जाए । चेयरमैन साहब से भी मैंने यही रिक्वैस्ट की वी और आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन ऐसा लगता है कि हमें जानबूझकर टाईम नहीं दिया जा रहा है । इसलिए हम प्रोटैस्ट के तौर पर वीक आउट करते हैं । (शोर).

श्री उपाध्यक्ष : आप लोग एक घंटा बीस मिनट बोल चुके हैं । (शोर)

(इस समय सर्वश्री शमशेर सिंह, दलीप सिंह, बीरेन्द्र सिंह, जगजीत सिंह पोहलू, मांगे राम गुप्ता, सुरेन्द्र सिंह और नारायण सिंह सदन से बाहर चले गए ।)

चौधरी संत कंवर : डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने आपकी रूलिंग चाही थी जब हाउस चाहता है कि सबको बोलने का मौका दिया जाए तो आप टाईम क्यों नही बड़ा देते?

श्री उपाध्यक्ष : अभी दो दिन का समय है । अगर जरूरत हुई तो टाईम बढ़ जाएगा ।

वर्ष 1978–79 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष महोदय) 3 मार्च को वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया था मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इससे पहले कि मैं अपने सुझाव सदन में रखू, हमारे विधायक श्री शंकर लाल जी ने जो बड़ी कड़ी भाषा में, अनुचित शब्दों में, मुख्य मंत्री जी के खिलाफ निहायत ही गलत और झूठे आरोप लगाए हैं, मैं उनका खंडन करना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, जो बात उन्होंने कही कि लाखों रुपये की थैलियां इकट्ठी की गई हैं, वह ठीक नहीं है । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश में किसान समिति को, किसान सभा को, जो कि एक सोशल आर्गेनाइजेशन है, चन्दा इकट्ठा करने के लिए औथोराइज किया गया है । इस संस्था का जनता सरकार या जनता पार्टी से कोई

खास सम्बन्ध नहीं है । यह आनें– नाइजेशन दिल्ली में एक किसान भवन बना रहा है और अपनी एकं अखबार शुरू करने जा रहा है । उसके लिए यह संस्था हरेक गांव से, हरेक घर सेएक–एके' रुपयाय दो–दो रुपये, पाच–पांच रुपये या दस–दस रुपये, श्रद्धा के अनुसार इकट्ठे– कर रही है । यह पैसा संस्था के प्रधान श्री रामनारायण जी के पास जमा कराया जाता है जिसकी बाकायदा रसीद दी जाती है और अकांउट रखा जाता है । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का वेग इलजाम लगाना निहायत ही बुरी बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज जो उन्होंने कही वह यह थी कि मुख्य मंखय मन्त्री जी हवाई जहाज से आते जाते हैं । यह भी कोई ठीक बात नही है. । **चौधरी** देवी. लाल जी हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं । जो उनकी हैसियत है, जो उनकी जिम्मेवारी है, उसको निभाने के लिए अगर उनका कीमन्त्री समय हवाई जहाज से आने जाने से बच जाए और वही समय किसी और काम में इस्तेमाल हो जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है और दुरुपयोग की बात नहों हूं । इस किस्म की बातें हमारे साथी को नहीं करनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बजट की तरफ आता हूं 1 इसमें सबसे पहले तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पिछले साल बाढ़ के कारण 6 छ लाख एकड़ भूमि में बोई हुई फसलों को नुकसान दुआ जिसकी राशि लगभग 60 करोड़ रुपयें बनती है और

इस साल ओले गिरने से लगभग 2 0—2 5 करोड़ रुपये की फसल का नुकसान हुआ । इसलिए मेरा सुझाव अपनी सरकार को यह है कि हर फसल की लाजमी तौर पर इंश्योरैन्स होनी चाहिए । इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी । इसकेलिए कोई सैपरेट स्टाफ क्रिएट नही करना पड़ेगा बल्कि जो हमारा माल का महकमा है, इसमें जो पटवारी से लेकर फाइनैन्शल कमिश्नर तक के कर्मचारीगण हैं, वही इस काम को भी कर सकता है । यह महक्मा जिस तरह माल— गुजारी वसूल करता है उसी प्रकार प्रति एकड़ एक या दो रुपये हर किसान से वसूल कर सकता है ताकि जब कभी नैचुरल कैलेमिटी हो जाए या किसान का किसी तरह से नुकसान हो जाए तो उस पैसे से उसे कम्पनसेट किया जा सक्ता है । इस वसूली को पटवारी मालगुजारी के साथ बड़ी आसानी से कर सकता है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, देहात में और शहरों में दोनों ही जगह पीने के पानी की बहुत किल्लत है । कई देहातों में, जहां पानी खारी है, मीलों से पानी लाना पड़ता है । खास तौर पर गुड़गांव जिले में जहां पहाड़ी इलाका है, उसके साथ—साथ मीलों तक पानी नही है । इसलिए उस इलाके को जल्दी से जल्दी वाटर सप्ला ई स्कीमज मुहैया की जाए । इसी तरह सिंचाई के पानी का भी प्रबन्ध किया जातु । जहां न तो नहरे हैं, न मीठा पानी. है जो फसलों के लिए इस्तेमाल हो सके, कई जगह इस तरह के दस गांव हैं, कई जगह पन्द्रह गांव हैं और कई जगह एक गांव है,

वहां सिंचाई के लिए ट्यूबवैल्ज. के जरिए दें–लतों को पानी सप्लाई किया जाए । यह बात निहायत ही जरूरी हए । डिप्टी स्पीकर साहब, गुड़गांव जिला फरीदाबाद कम्पलैक्स को छोड़कर निहायत ही बैकवर्ड जिला है । इसलिए मैं अपनी सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस डिस्ट्रिक्ट को बैकवर्ड एरिया डिक–लेयर किया जाए । इस जिले में जहां बहुत गरीबी है, जहां रोजगार का कोई साधन नही जमीन नाकस है, पानी का बंदोबस्त नहीं है, वहां पर सरकार यदि ऐग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज बना दे तो वहां के. लोगों को रोजगार मिल सकेगा और वे अपना गुजारा कर सकेंगे ।

डिप्टी स्पीकर साहब, कृषि के लिए इन–पुटस और इम्पलीमैंटस बहुत मंहगे हैं । इनकी कीमत सन् 1972 के बाद दो गुनी और तीन गुनी हो गई है । हमारी सरकार नैं और केन्द्रीय सरकार ने इसमें थोड़ा रिलीफ दिया था लेकिन वह नाकाफी है । इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ट्रैक्टर्ज, फर्टिलाइजर और दूसरे कैमिकल्ज और इन–पुटस की तरफ यह विशेष ध्यान दे ताकि इनकी कीमतें पचास परसैट कम आ सके ।

इसके अलावा, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं फ्लडज के बारे में कुछेक बातें जरुर कहना चाहूंगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव हरियाणा में सबसे ज्यादा बाढ पीडित है । साहबी नदी के लिए अभी कुछ स्कीम हमारी सरकार ने बनाई है । (विघ्न) हमारे। सरकार मसानी गांव के पास एक बैराज बनाने जा रही हूँ लेकिन वह काफी नही रहेगा । इसके बारे में मेरा एक सुझाव छुश्व ।

साहबी नदी जब हरियाणा में एन्टर करती है तो रणोली, प्राणपुरा झाबुआ, पांवटी बगैरा जो गांव हैं, वहां अगर एक बड़ी झील बनाई जाए तो वह पानी काफी मात्रा में सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो सकता है ।

आगरा कैनाल के बारे ने भी, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं चन्द शब्द जरूर कहना चाहूंगा । आगरा कैनाल में से जो गुडगांव कैनाल निकलती है उसकी कैपेसिटी पन्द्रह सौ क्यूसिक है लेकिन इस समय उसे सारा दो सौ क्यूसिक पानी मिलता है । इसके अलावा वैस्टर्न जमुना कैनाल में से मोनक ऐस्केप से आठसौ क्यूसिव पानी जमुना नदी' मे डाले दियां जाता है जिसमे से चार सौ क्यूसिक दिल्ली वाटर सप्लाई स्कीम वाले इस्तेमाल– करते हैं और दो सौ क्यूसिक जमुना में कही चला जाता है. । इस तरह गुड़गांव कैनाल के लिए सिर्फ दो सौ क्यूसिक पानी बचता है । गुडगावा कैनाल और नजफगढ ड्रेन के बीच 20 मील का टुकड़ा है । अगर इस टुकड़े को गुड़गावा कैनाल के साथ मिला दिया जाये तो नजफगढ ड्रेन में जो 800 क्यूसिक पानी है वह भी गुडगांवा कैनाल में चला जायेगा और उस कैनाल में एक हजार क्युसिक पानी हो जायेगा । इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहब पिछली सरकार ने हर जिले में मैडिकल कालेज और आयुवैंदिकं कोलेज बनाये हैँ लेकिन दुर्भाग्य से गुडगांवा जिला जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है

आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी, शायद रकबे के लिहाज से हिमार के बराबर हो लेकिन वहां पर कोई भी मैडिकल कालेज और आयुर्वेदिक कालेज नही बताया गदा । डिप्टी स्पीकर साहब वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन के पास और केन्द्रीय सरकार के रास काफी असिस्टेन्स होती है, उसकी सहायता से एक आयुर्वेदिक कालेज या मैडिकल कालेज गुडगांवा में जरूर बनाया जाये ।

एक रेलवे लाइन के बारे में जरूर कहना चाहूंगा । गुडगांवा से गुह फिरोजपुर झिरका तह रैलवे केसाथ 'कनैक्ट किया जाना चाहिए । उस एरिया में आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेल में बैठ कर नहीं देखा है । हमारी राज्य सरकार तो नहीं बना सकतीं लेकिन केन्द्रीय सरकार को परसुवेड कर सकती है । एक रेलवे लाईन भिवानी से झज्जर फारुखनगर गढ़ी हरसरूप, सोहना और नुह–फिरोजपुर झिरके तक मिलायी जाये । यह बड़ी वायबल और मुनाफे वाली लाईन होगी ।

एजूकेशन के बारे में कुछ थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं । एजूकेशन विभाग के लिए नान–लान के बजट में केवल अढाई परसैन्ट पैसा दिया गया है । नान– गवर्नमैंट कालेजीज की हालत बहुत खराब हे । गुडगांवा में डी0एस 0डी0 कालेज है, होडल में ब्रिज मंडल कालेज है और पटौदी के अन्दर के0एन0 कालेज है वहां सभी कालेजीज की हालत खराब है । वहां के स्टाफ को आठ–आठ और छः छः महीने से तन्खाहें नहीं मिलती है

। मैं सरकार का खासतौर पर ध्यान दिलाना चाहूंगा क्योंकि यह बहुत इम्पो– टेंट सब्जैक्ट है और सरकार का भी यह फर्ज है कि इस ओर ध्यान दे । एजूकेशन डिपार्टमैंट को जो अढ़ाई परसैन्ट नान–प्लान के लिए पैसा दिया गया है यह बहुत कम है, कम से कम दस परसैन्ट इसको कर दिया जाये । जो कालेजीज अपने स्टाफ को तन्खाह नही दे पा रहे हैं उनकी मदद की जाये ।

इसके साथ ही साथ मैं एजूकेशन के स्टेन्डर्ड के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं । हरियाणा में स्टैन्डर्ड आफ एजूकेशन बहुत ज्यादा गिर गया है । गुडगांवा जिले में और गुडगांवा के आसपास जो भी टाउन हैं उनमें ज्यादातर स्टाफ लेडीज का है । वे लेडीज ज्यादातर देहली से आती हैं । वे स्कूलों में बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाती हैं । वहां पर यह हालत है कि सौ में से एक लड़का पास होता है और 150 में से दो लड़के पास होते हैं । यह हालत वहां की एजूकेशन की है । मैं निवेदन करूंगा कि जिस स्टाफ का रिजल्ट बहुत ही बिलोक्टैन्डर्ड है उनको इन्टीरीयर में ट्रांसफर कर दिया जाये क्योंकि वहां सिवाए पडाने के कोई और काम नहीं होगा । जो शहरों में स्टाफ लगा हुआ है वह पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं देता दूसरी चीजों में ज्यादा इन्टैरस्ट लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई में कोई इन्ट्रैस्ट नहीं लेते हैं । इस सारे स्टाफ का रिजल्ट खराब है लेकिन फिर भी शहरों में आराम सें बैठे हैं । जो अच्छा स्टाफ है, पड़ाने वाला है उसको 20– 20 किलो–मीटर इन्टी– रीयर में भेज रखा है । इसलिए मेरी आपके

जरिए सरकार से दरखास्त है कि जिन लोगों का रिजल्ट खराब है उनका वहां से तबादला किया जाये और सबको इन्टीरीयर में भेजा जाये ।

मैं आपके जरिए एक अकाडमी के लिए भी जरूर सुझाव रखूगा । हरियाणा सरकार को एक अकाडमी अवश्य खोलनी चाहिए जिसमें आई0ए 0एस0 और आई0 पी0एस0 और दूसरे जो एच0सी0एस0 और अलाइड सर्विसीज हैं, उनके इस्तहानो की तैयारी करायी जाये । वहां पर इन परीक्षाओं के लिए बाकायदा कोचिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि हरियाणा के लोग उन इम्तहानों में कामयाब हो सके ।

डिप्टी स्पीकर साहब जिस तरह से राई के अन्दर स्पोर्टस स्कूल है इसी प्रकार लड़कियों के लिए भी एक स्पोर्टस स्कूल और खोला जाना चाहिए । ऐसा करने से हमारी लड़कियां भी आगे आयेंगी ।

इसके अलावा मेरा एक सुझाव और है वे जो वाटर रेट्स के बारे में है । काफी विधायकों ने, मेरे दोस्तों ने उसके बारे में कहा है । मैं यह कहूंगा कि इस वक्त किसानों की हालत बहुत अच्छी नहीं है । यह जो दस परसैन्ट वाटर रे ट्स की बढ़ौतरी की जा रही है, इसपर अवश्य ध्यान दें । आपने जो मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपुका आभारी हूं । इस बजट की ताइद करते हुए, अपनी जगह लेता हू ।

चौधरी गया लाल (हसनपुर अनुसूचित जाति) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बजट पर बोलने के लिए समय दिया है, समय तो बहुत थोड़ा है । इस बजट में जो ग्रामीण उद्योग योजना की चर्चा की गई है, उसके बारे में कुछ अपने सुझाव पेश करना चाहता हूं । ग्रामीण उद्योग योजना चार या दो यूनिट की यह स्कीम हमारी सरकार ने लागू की है । यह वाकई ही बड़ी सराहनीय है । इससे हमारे पढ़े–लिखे नौजवान जो बेकार पिर रहे थे, उनकी बेरोजगारी दूर होने में सहायता मिलेगी । बेकारी के कारण लोगों को इस समय काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । मैं सरकार को बताना चाहता हू कि इस स्कीम में 80 परसैन्ट पैसा बैकों से मिलता है लेकिन उसमें बैक बिल्कुल सहयोग नहीं दे रहे है, वे इस स्कीम को फेल करने पर तुले हुए हैं । मैं आपके जरिए गवार बा ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस स्कीम को अगर कामयाब बनाना है तो, स्टेट के अधीन तो यह बैक नही हैं, इस बारे में केन्द्रीय सरकार से बातचीत की जाये बिरू वे बैकों को यह आदेश दें कि इस स्कीम को ज्यादा से ज्यादा रुपया देकर कामयाब बनाया जा ये । मैं समझता हू कि इस स्कीम में तहत काफी बेरोजगारी दूर होगी और नौजवान लड़के जो बेकार फिर रह हैं, करोड़ों लाखों और हजारों की तादाद में, उनको रोजगार मिल सकता है । दूसरी बरत एक हरिजन कल्याण विभाग के बारे में बताना चाहता हूं । बजट में 38 –12 लाख रुपये को रकम हरिजन कल्याण के लिये रखी गयी है जिसमें से 8 लाख रुपया विद्यार्थियो/ बच्चों का वजीफा है, 3 लाख रुपया कुएं

व हैड पम्पस के लिये ग्रान्ट बुक । एक लाख रुपया हरिजन कन्या स्टुडैन्ट्स को वस्त्रों के लिये रखा गया है तथा 12 लाख रुपया मकानो/चौपालो की ग्रांट के लिये है । इसके अलावा एक लाख रुपया हाउसिज के लिये ग्रान्ट देने के लिये है । एक लाख रुपया सूअर पालने के लिये लोन के लिये रखा गया है । बकाया रकम उद्योग धन्धों, दस्तकारी के लिये रखी गयी है । उपाध्यक्ष महोदय, यह साढ़े 38 लाख रुपये की जो रकम हरिजन कल्याण के लिये रखी गयी है, यह बहुत कम है । आप देखिये हरियाणा में हरिजन भाईयों की आबादी लगभग 20, 22 या 25 लाख के करीब हैं ।

हम पैसे में से 10, 000 रुपया कानूनी सहायता के लिये भी रखा गया है और कुछ दूसरी बातों के लिये भी रखा गया है । मेरा कहना यह है कि केवल साढ़े 38 लाख रुपया रखा मग मै जबकि हरिजनों की शडयूल्ड कास्टस या शडयूल्ड ट्राइब्ज लोगों की आबादि करीब 25 लाख ीऐ । अगर 25 लाख की आबादी है तो एक रुपया 5 1 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से उन पर खर्च किया जा रहा है. और अगर 20 लाख की आबादी है तो एक रुपया 80 या 82 पैसे फी आदमी साल के हिसाब से उन्हें मदद दे रहे है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरीके से जो यह पैसा हरिजन कल्याण के लिये रखा गया है, यह बहुत ही निराशाजनक मद है । क्या यह हरिजनों की आबादी के हिसाब से थोड़ा नहीं है? यह एक झूठा धोखा है । इससे हरिजनों का कोई कल्याण नहीं हो सकता । कांग्रेसियों ने भी 30 वर्ष तक हरिजनों को

काफी धोखा दिया है । आज भी हरिजनो की वही दशा है, आजु भी वे कच्चे मकानों में रहते हैं । आज भी वे झोपडियों में रहते हैं । वही बेरोजगारी अब भी उनमें है । उन के पास न तो कोई फैक्ट्री है औरज न जमीन है । उनके पास अपने हाथ है । वह हाथ से मेहनत करके रोटी कमाता है और अपना गुजारा करता है । आज उसके लिये कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां पर वह मेहनत से काम करके अपना गुजारा कर सके, जिससे उसको रोजगार दिया जा सके । इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह जो पैसा हरिजनों के कल्याण के लिये रखा गया है) यह ना–काफी है । इस मद में और रकम बढ़ायी जाये । इसके साथ ही खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए 14 लाख 45 हजार रुपया रखा गया है । यह केवल उन्ही लोगों के लिये होता है, चाहैं वे शडयूल्ड कास्ट के हैं या बैकवर्ड क्लासिज के हें, जो अपने हाथ से काम करना चाहते है । ते मेरा कहना यह है कि हरियाणा स्टेट के लिये 14 साढ़े 14 लाख रुपया के करीब राह जो पैसा रखा गया है, यह बहुत थोु़ा है । इससे उद्योग धन्धा करने वाले लोगों के कितना पैसा कितना पैसा बांट कर हिस्से आयेगा, इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं । मेरे ख्याला में यह बहुत कम है । इसलिये मेरा कहना यह है कि खादी ग्रामोद्योग के लिये भी ज्यादा पैसा रखा जाये । तीसरी बात मैं शराब के ठेकों के बारे में कहूंगा । शराब के ठेकों के बारे में जनता सरकार ने काफी विचार किया है कि देशी शराब को खत्म दिया जाये और जो इंग्लिश शराब है, उस पर ज्यादा डियूटी लगाकर उसको और मंहगा कर दिया जाये

ताकि गरीब लोग इससे बच सकें । मेरा इस पर यह सुझाव है कि 10 हजार से कम आबादी वाले गांव से यह शराब के ठेके समाप्त कर दिये जायें और इंग्लिश शराब के जो ठेके हैं, वे बेशवय और ज्यादा बढ़ा दिये जाये क्योंकि यह शराब ही भ्रष्टाचार की जड़ है । अगर गाव से, देहात से शराब. खत्म हो जायेगी तो गांव के रहने वाले सीधे–सादे गरीब लोग इस भ्रष्टाचार से और इस तबाही से बच जायेंगे ।

अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह खेतीबाड़ी के बारे मे है । जनता सरकार ने काफी रुपय खेतीबाडी को प्रोत्साहन– देने के लिये खर्च करने का निर्णय लिया हे । आपको भी पता है कि हिन्दुस्तान की 7 0 80 प्रतिशत जनता जिसमें हरियाणा भी शामिल हे, देहातों में रहती है । और यह जनता खेती पर ही निर्भर करती है च, हे वह खेत का मालिक हो या खेत में काम करने वाला मज–दूर हो । इस बजट में खेती के लिये जो पैसा रखा गया है यह वाकई एक क्रान्तिकरी कदम है क्योंकि इससे ज्यादा पैसा बजट का 40– 45 प्रतिशत हिस्सा पहले कमी नहीं रखा गया । इससे जहा बेकारी दूर होगी वहां टिब्बे जहां–जहां पर हैं उनको एकसार किया जायेगा । इस पैसे से जहां पर कवर या कल्लर जमीन पड़ी हुई है, उसको ठीक किया जायेगा । जिन खेतों में पानी नही पहुंचता है, उन– खेतों में पानी पहुंचाया जायेगा । पिछले 30 सालों से पिछली सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था । हमारे चीफ मिनिस्टर साहब

ने यह कहा है कि भ्रष्टाचार बन्द हो और पानी का प्रबन्ध हो' । मेरा कहना यह है कि इस पैसे से हरियाणा की चप्पा चप्पा जमीन के लिये पानी का प्रबन्ध किया जायेगा इससे गरीबी भी दूर होगी और किसान खुशहाल होगा । अगर किसान खुशहाल होगा तो जो उसके साथ मजदूर रहता है, वह भी खुशहाल होगा । और दूसरे जो उसके साथ सम्बन्धित लोग हैं, वे भी खुश होंगे । तो मैं इस बजट के अन्दर जो खेती के लिये पैसा रखा गया है, उसका हार्दिक समर्थन करता हूं और यह समझता हूं कि वाकई यह एक क्रान्तिकारी कदम है । जहां तक सरकार ने जो आबियाना टैक्स तथा यात्री टैक्स बढ़ाया है, इसका सम्बन्ध है, इसकी कोई आवश्यक्ता नहीं थी क्योंकि जनता पार्टी किसानों और मजदूरों को पर उठाना चाहती है और यह जो टैक्स लगाया गया है, इसका डायरैक्ट असर, किसान और मजदूर पर पड़ता है । इसके अलावा मैं एक सुझाव और पेश करता हूं । मैंने देखा है कि हमारे मंत्री गणों का लगभग 43 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च आता है जोकि बहुत ज्यादा है । इसमें 5 लाख के करीब रुपया एक मंत्रीकी कोठी के किराये के लिये दिया गया है जोकि बहुत ज्यादा है । हमारी जनता पार्टी जिसने यह तय किया था और जिसे बाबू जय प्रकाश नारायण ने भी कहा था कि हम एक छोटे मकान में रह कर राज चलायेगे तो हमारे लिए बड़ी कोठियों की जरूरत नहीं है । इसके लिये हमें इतना लम्बा–चौडा खर्च नहीं करना चाहिये । अगर हमने उन के बताए हुए आदर्शों पर चलना है, अगर हमने महात्मा गांधी जी के आदेशो पर चलना है तो हमें यह खर्च घटाना चाहिये ।

Mr. Deputy Speaker : The house stands adjourned* till 9.30 a.m. tomarrow.

13.00 बजे ।

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. on Thursday, the 9th March, 1978.)